RNI NO. DELHI/2012/48369
वर्ष 8 अंक 315
नई दिल्ली, सोमवार, 21 सितंबर, 2020
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

कोहली आईपीएल खिताब के सपने को पूरा करने को उतरेंगे
स्पोर्ट्स-10

कृषि सुधार विधेयकों पर संसद की लगी मुहर

रास में कड़ा विरोध-भारी हंगामा, एक्शन लेंगे वेंकैया

दीपक कुमार झा। नई दिल्ली

राज्य सभा में कृषि विधेयकों के विरोध में रविवार को नियम पुस्तिका को उप सभापति हरिवंश की ओर फेंकते तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन

अभूतपूर्व हंगामे के बीच रविवार को राज्यसभा ने दो महत्वपूर्ण कृषि विधेयकों को पारित कर दिया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य कोविड-19 प्रोटोकॉल को तोड़कर वेल तक पहुंच गए, दस्तावेजों को फाड़ दिया, सभापति के डेस्क पर लगे माइक को उखाड़ने की कोशिश की और संसद नियम पुस्तिका को पीठासीन अधिकारी, उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह पर फेंक दिया।

सत्तारूढ़ पार्टी दो विवादित कृषि विधेयकों को आगे बढ़ाने में कामयाब रही। ये दोनों लोकसभा में विपक्ष के सांसदों के विरोध के बीच पहले ही पास हो चुके हैं। समस्या तब शुरू हुई जब राज्यसभा का निर्धारित समय विधेयकों को पारित करने के लिए बढ़ाने की अनुमति दे दी गई। विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया। उसका मानना था कि ऐसा कोई कदम सर्वसम्मति से ही उठाया जाना चाहिए। विपक्षी दलों के सदस्य वेल में पहुंच गए तथा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और बिल को किसानों के लिए 'डेथ वारंट' करार दिया। विपक्ष ने जहां उप सभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, वहीं सरकार और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू इस बात पर विचार कर रहे हैं उन सदस्यों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए जिन्होंने सदन में हंगामा किया। सरकार तीसरा कृषि बिल संसद के ऊपरी सदन में सोमवार को पेश करेगी।

इन विधेयकों को अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। चार विपक्षी दलों ने इन दोनों बिलों को जांच के लिए हाउस पैनल को भेजने के प्रस्ताव दिया जिसे ध्वनिमत से नकार दिया गया लेकिन कांग्रेस, टीएमसी, भाकपा और द्रमुक के सदस्यों ने मुद्दे पर मत विभाजन की मांग की। उप सभापति हरिवंश ने जैसे ही यह कहते हुए मत विभाजन से इनकार किया कि यह केवल उसी समय हो सकता है जब सदस्य अपनी सीट पर हो, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन पीठ की ओर तेजी से बढ़े और नियम पुस्तिका को उप सभापति की ओर फेंक दिया। हाउस मार्शलों ने उनके इस कदम को विफल कर दिया और हरिवंश की ओर फेंकी गई किताब को बीच में ही पकड़ लिया। इसके अलावा चेयर पर लगे माइक्रोफोन को भी उखाड़ने का प्रयास किया गया लेकिन मार्शलों ने ऐसा होने से रोक लिया। ओब्रायन के साथ द्रमुक नेता तिरुची सिवा, कांग्रेस के वेणुगोपाल तथा भाकपा के केके रागेश, जिन्होंने विधेयकों को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के लिए प्रस्ताव पेश किया था, ने कागजों को फाड़कर हवा में उड़ा दिया।

हरिवंश ने सदस्यों को अपने स्थान पर जाने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते वेल में न आने की हिदायत दी। इसके बाद कार्यवाही के हो रहे लाइव प्रसारण का ऑडियो बंद कर दिया गया लेकिन हंगामा जारी रहा। बाद में उन्होंने कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्ष ने फिर नारेबाजी की लेकिन हरिवंश को ध्वनिमत के लिए विधेयक को पटल पर रखने से नहीं रोक सके। सदन में पहला बिल ध्वनिमत से पारित होने तथा उसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव खारिज होने के बाद, दो सदस्यों ने राज्यसभा अधिकारियों के टेबल पर चढ़ने की कोशिश की जिन्हें उतार दिया गया। दोनों विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया तथा विपक्षी पार्टियों द्वारा पेश किए गए संशोधनों को खारिज कर दिया गया। लेकिन कृषि बिलों को (शेष पेज 9)

किसानों को सशक्त बनाएंगे विधेयकः मोदी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● बरसे राजनाथ, राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों का आचरण 'शर्मनाक'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से कृषि संबंधी दो विधेयकों को मंजूरी मिलने को ऐतिहासिक करार देते हुए रविवार को कहा कि इससे न केवल खेती-बाड़ी के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन होगा बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। उन्होंने एकबार फिर से किसानों को आश्वस्त किया कि वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी।

मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, 'दशकों तक हमारे किसान भाई-बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सबसे आजादी मिली है। इससे किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी।' पंजाब के किसानों तक पहुंच बनाने का प्रयास करते हुए प्रधानमंत्री ने पंजाबी में भी ट्वीट किया। बहरहाल, मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, 'भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं।

यह न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे।' मोदी ने कहा, 'मैं पहले भी कहा चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था जारी रहेगी। सरकारी खरीद जारी रहेगी।' उन्होंने कहा, 'हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे।' प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, 'हमारे कृषि क्षेत्र को आधुनिकतम तकनीक की तत्काल जरूरत (शेष पेज 9)

कांग्रेस में पायलट के अच्छे दिन लौटे, सिंधिया के गढ़ में गरजेंगे

मध्य प्रदेश उपचुनाव

उषा श्रीवास्तव। नई दिल्ली/भोपाल

● कमलनाथ ने महाराजा के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में गुर्जर बहुल सीटों (16) पर पार्टी के प्रचार को बुलाया, सहर्ष मान गए सचिन

● 230 सदस्यीय विधानसभा की 28 सीटें हैं रिक्त, 22 सिंधिया समर्थकों व तीन अन्य कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफों और 3 सीटें जन प्रतिनिधियों के निधन से हुई खाली

पुरानी कहावत है कि राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठेगा, यह भांप पाना बेहद कठिन होता है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो इन दिनों इसके नेता कुछ इसी उधेड़बुन से दो-चार हैं। कभी एक दूसरे की गाढ़ी दोस्ती की कसमें खाने वाले सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, आज दुश्मन बनकर आमने-सामने हैं।

राजस्थान में पार्टी सरकार के खिलाफ खुली बगावत के बाद मनुहार कराकर पायलट तो घर लौट आए लेकिन सिंधिया कांग्रेस की बैरी नंबर वन-भाजपा के होकर रह गए। अब, मध्य प्रदेश उपचुनाव में उनके गढ़ ग्वालियर-चंबल में गरजने को कांग्रेस ने पायलट को चुना है और वे सहर्ष मान भी गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति के बेहद अहम मोड़ पर, गुर्जर वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखने वाले राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की एंट्री, पार्टी संगठन में उनके अच्छे दिन लौटने का संकेत है। 230 सदस्यीय राज्य विधानसभा की 28 सीटें रिक्त हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं।

इनमें से 25 सीटें सिंधिया की बगावत में शामिल होकर कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 22 कांग्रेसी विधायकों के भाजपा में चले जाने से खाली हुई हैं। बाद में अन्य तीन कांग्रेसी विधायक भी इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए यानी कुल 25। शेष तीन सीटें कांग्रेस (2) और भाजपा (एक) विधायकों के निधन से रिक्त (शेष पेज 9)

विपक्ष नाराज, गदगद सरकार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● उपसभापति के खिलाफ 12 पार्टियों ने दिए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस

राज्यसभा में दो कृषि विधेयकों को पास होने के बीच विपक्षी पार्टियों ने रविवार को राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि कृषि विधेयकों को पारित कराने में सरकार की मदद के लिए उन्होंने संसदीय नियमों का उल्लंघन किया है। प्रस्ताव पर करीब 100 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं और इसे संसद के नोटिस ऑफिस दाखिल किया गया है क्योंकि महासचिव उपस्थित नहीं थे। दूसरी ओर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू विपक्ष के उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं जो कृषि विधेयकों का विरोध करते हुए सदन के वेल में पहुंच गए थे तथा जबरदस्त हंगामा किया था।

नायडू ने उप सभापति हरिवंश तथा संसदीय मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ बैठक की तथा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और तोमर के साथ मुद्दे पर चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि सोमवार को जब सदन का कार्यवाही शुरू होगी तो नायडू बयान देंगे और सरकार द्वारा उपलब्ध नियमों के प्रावधान से जुड़े प्रस्ताव को पेश करने के बाद वे कार्रवाई का ऐलान करेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने कहा, 'उन्हें (राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश) को लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय, उनके रवैये ने आज लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए हमने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।' अहमद पटेल ने कहा 'यह दिन इतिहास में 'काला दिन' के रूप में दर्ज होगा। जिस तरह से ये बिल पारित किए गए हैं, वह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और लोकतंत्र की हत्या है। 12 विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है।' इससे पहले राज्यसभा में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) विधेयक-2020 तथा कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 को मंजूरी मिल गई। ध्वनिमत से पारित होने से पहले इन विधेयकों पर सदन में खूब हंगामा हुआ। नारेबाजी करते हुए सांसद वेल तक पहुंच गए। कोविड-19 के खतरे को दरकिनार करते हुए धक्का-मुक्की भी हुई। विपक्ष ने इसे 'काला दिन' बताया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि यह 'लोकतंत्र की हत्या' है। भाजपा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने विपक्ष के सदस्यों के व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पीठ यह फैसला लेने में सक्षम है कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं कई सांसद ने शिकायत की कि ऑडियो सिस्टम बंद है जिससे राज्यसभा टीवी के जरिये सदन की कार्यवाही का लाइव प्रसारण बाधित हो रहा है। यह स्पष्ट नहीं हो सका कि माइक को पीठ के निर्देश पर बंद किया गया था। संसद के बाहर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने कहा ' लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनमत दिया है और यह हंगामा लोगों के जनमत का अपमान है।'

कृषि विधेयकों के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान

अमृतसर में कृषि विधेयकों का पुतला जलाकर विरोध करते विभिन्न संगठनों के किसान

राजेश कुमार। नई दिल्ली

● पंजाब, हरियाणा में सड़कों पर उतरे अन्नदाता, ट्रैक्टर रैलियां निकालीं, कई हाइवे पर लगाया जाम

देश में कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। जब रविवार को राज्यसभा में हंगामे के बीच संसद दो कृषि बिलों को पारित कर रही थी, उसी समय हरियाणा पुलिस पंजाब से हरियाणा में प्रवेश करने वाली ट्रैक्टर रैली पर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही थी। पुलिस ने पंजाब के युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में चली किसानों की रैली को अंबाला-मोहाली सीमा पर सोदापुर के पास रोक लिया। किसान संगठनों ने पंजाब में अपने विरोध प्रदर्शन को और तेज कर दिया है। हरियाणा में कई राज्य और राष्ट्रीय (शेष पेज 9)

भारत में एक दिन में 92,605 कोरोना संक्रमित, 1133 मौतें

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

भारत में रविवार को लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस से उबर चुके लोगों की संख्या संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या से अधिक रही। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार विगत 24 घंटे के दौरान 94,612 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से उबरे हैं, जिसके बाद रोगियों के ठीक होने की दर 79.68 हो गई है। इसी अवधि के दौरान 92,605 लोग वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या 54,00,619 हो गई। सुबह आठ बजे तक अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से 1,133 रोगियों की मौत हुई है, जिसके बाद महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 86,752 हो गई है। देश में कोविड-19 से उबर चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 43,03,043 हो गई है और कोविड-19 संबंधी मृत्यु दर अब 1.61 प्रतिशत है। देश में अब भी 10,10,824 लोग वायरस से संक्रमित हैं।

कर्नाटक, केरल में आईएस आतंकियों की भारी मौजूदगी का दावा नकारा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● गृह मंत्रालय ने लोस में यूएन रिपोर्ट को तथ्यात्मक रूप से बताया गलत

सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट को रविवार को 'तथ्यात्मक रूप से सही नहीं' बताते हुए खारिज कर दिया जिसमें केरल और कर्नाटक में आईएसआईएस आतंकियों की 'अच्छी-खासी संख्या' में मौजूदगी का दावा किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार को रिपोर्ट की जानकारी है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी एक सवाल का लिखित जवाब दे रहे थे जिसमें पूछा गया था कि क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र की 'आईएसआईएस, अल-कायदा और संबंधित लोगों के बारे में विश्लेषणात्मक सहायता और प्रतिबंध निगरानी टीम की 26वीं रिपोर्ट' से वाकिफ है। इस रिपोर्ट में केरल और कर्नाटक में बड़ी संख्या में आईएसआईएस आतंकवादी होने की बात कही गई है। मंत्री ने इस रिपोर्ट का खंडन किया और इस संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज मामलों के आंकड़े पेश किए। रेड्डी ने कहा कि सरकार लगातार विभिन्न अंतरराष्ट्रीय, बहुपक्षीय और दुपक्षीय स्तर पर स्थापित तंत्र के साथ-साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से भारत की सही स्थिति पेश करने के लिए जरूरी कदम उठाती है। रेड्डी ने यह भी कहा कि इस्लामिक स्टेट (आईएस) की उपस्थिति से संबंधित 34 मामले और देश भर में लश्कर-ए-तैयबा की उपस्थिति से संबंधित 20 मामले राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज किए गए थे और इस सिलसिले में 240 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार को देश में आईएस, दाऐश, आईएस खोसरान, लश्कर-ए-तैयबा आदि आतंकवादी संगठनों की मौजूदगी के बारे में पता है। एनआईए ने अब तक इस्लामिक स्टेट (आईएस) की उपस्थिति से संबंधित 34 और लश्कर-ए-तैयबा की मौजूदगी के 20 मामलों की जांच की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अभी तक 160 आईएस और 80 लश्कर के कथित आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है।

बाजार

सेंसेक्स	38,845	
निफ्टी	11,504	
सोना	52,672	/10g
चांदी	69,841	/kg

क्विक न्यूज

फिल्मकार अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप

मुंबई। फिल्मकार अनुराग कश्यप ने अभिनेत्री पायल घोष के यौन शोषण आरोपों को रविवार को खारिज करते हुए इन्हें निराधार करार दिया। घोष ने शनिवार को ट्वीट किया था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के निर्देशक ने उनका यौन उत्पीड़न किया। अभिनेत्री ने अपना ट्वीट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को टैग करते हुए कश्यप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। घोष ने ट्वीट में कहा, अनुराग कश्यप ने मेरे साथ बुरी तरह जबर्दस्ती की। प्रधानमंत्री कार्यालय और नरेन्द्र मोदी जी कार्रवाई कीजिए तथा देश इस रचनात्मक व्यक्ति में छिपे शैतान को देखे। एबीएन तेलुगु को जारी एक वीडियो में घोष ने दावा किया कि घटना 2014-2015 की है। पायल दावा किया अन्य महिला कलाकारों के साथ भी उनके अंतरंग संबंध रहे हैं।

एफसीआरए कानून और होगा कठोर

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● सरकार करेगी विदेशी अंशदान कानून में संशोधन, पंजीकरण के लिए जरूरी होगा आधार

विदेशी अंशदान (नियमन) कानून (एफसीआरए) में संशोधन किया जाना है, जिसके तहत किसी भी एनजीओ के पंजीकरण के लिए पदाधिकारियों के आधार नंबर जरूरी होंगे और लोक सेवक के विदेशों से रकम हासिल करने पर पाबंदी होगी। विदेशी अंशदान (योगदान) विधेयक, 2020 रविवार को लोकसभा में पेश किया गया और इसमें प्रावधान है कि केंद्र किसी एनजीओ या एसोसिएशन को अपना एफसीआरए प्रमाणपत्र वापस करने की अनुमति दे सकेगा। मसौदा विधेयक में कहा गया है कि कुल विदेशी कोष का 20 प्रतिशत से ज्यादा प्रशासनिक खर्चे में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वर्तमान में यह सीमा 50 प्रतिशत है। विधेयक के लक्ष्य और कारणों के बारे में बयान में कहा गया है, विदेशी अंशदान (योगदान) विधेयक 2010 को लोगों या एसोसिएशन या कंपनियों द्वारा विदेशी योगदान के इस्तेमाल को नियमित करने के लिए लागू किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि के लिए विदेशी योगदान को लेने या इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है।

मसौदे में कहा गया है कि कानून एक मई 2011 को लागू हुआ था और दो बार इसमें संशोधन हुआ। वित्त कानून की धारा 236 के जरिए पहला संशोधन हुआ और वित्त कानून,2018 की धारा 220 से दूसरा संशोधन हुआ। इसमें कहा गया है कि हर साल हजारों करोड़ों रुपए के विदेशी योगदान के इस्तेमाल और समाज कल्याण का काम करने वाले वास्तविक गैर सरकारी संगठनों या एसोसिएशनों और भुगतान में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ान के (शेष पेज 9)

चुनावी गर्मी में चिराग की मार्मिक चिट्ठी की फुहार

दिल्ली छोड़ बिहार न जाने पर लोजपा कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों से कहा- आईसीयू में भर्ती पिता (पासवान) को मेरी जरूरत

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

● इस समय उनके साथ नहीं रह पाया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा

एक तरफ चुनाव जैसी बड़ी चुनौती, दूसरी ओर बीमार पिता की देखभाल करने वाले बेटे वाली जिम्मेदारी। बिहार की राजनीति के होनहार युवा चेहरे चिराग पासवान ने चुनौती को साथ लेकर पहले जिम्मेदारी निभाने का निश्चय किया। चिराग के पिता केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान दिल्ली के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हैं।

ऐसे में चिराग बिहार में राजनीतिक गहमागहमी छोड़ अपने पिता का इलाज करा रहे हैं। बिहार में आगामी नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी गठजोड़, सीट बंटवारे, नाराज नेताओं को साधने और मतदाताओं को लुभाने के लिए जदयू के नेतृत्व वाला राजग गठबंधन और राजद नीत महागठबंधन के बीच कड़ी जोर आजमाइश चल रही है। पार्टी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कहीं अपना घरोंदा बिखर न जाए, छोटे पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और पार्टी प्रत्याशियों को मार्मिक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस समय पिता के साथ नहीं रह पाया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।

इसमें उन्होंने बिहार के लोगों को भी जिम्मेदार बेटा होने का संदेश देने की कोशिश की है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस चिट्ठी में पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के स्वास्थ्य का जिक्र किया है। पत्र के मुताबिक, राम विलास पासवान आईसीयू में भर्ती हैं और बीमारी से जूझ रहे हैं।

चिराग पासवान ने बेहद मार्मिक शब्दों में कहा कि आज जब पिता को मेरी जरूरत है तो मुझे उनके साथ रहना ही चाहिए, अन्यथा वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। बता दें कि इन दिनों राजग में सीटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची चल रही है और ऐसे समय में चिराग पासवान दिल्ली में हैं। चिराग पासवान ने 20 सितंबर को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए जारी पत्र में लिखा कि कोरोना काल में लोगों को राशन मिलने में दिक्कत न आए, इस वजह से पापा (राम विलास पासवान) अपने नियमित स्वास्थ्य जांच को टालते रहे। इस कारण वह थोड़ा अस्वस्थ हो गए।

पिछले तीन हफ्तों से दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। वह खुद अस्पताल में पापा को रोज बीमारी से लड़ते हुए देख रहे हैं। पापा ने उन्हें कई बार पटना जाने का सुझाव भी दिया, लेकिन बेटा होने के नाते उन्हें छोड़कर जाना उनके लिए संभव नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे उन साथियों की भी चिंता है, जिन्होंने अपना जीवन 'बिहार पहले-बिहारी पहले' के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने यह भी लिखा कि अब तक गठबंधन के साथियों से न ही बिहार के भविष्य को लेकर और न ही सीटों के तालमेल को लेकर कोई चर्चा हुई है।

बिहार संसदीय बोर्ड और सभी सांसदों के साथ बैठक में उन्होंने ये बातें बताई हैं। लोजपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि जब तक रामविलास पासवान ठीक नहीं हो जाते हैं, सभी पार्टी नेता और कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र में लोगों की कोरोना और बाढ़ की विपदा से लड़ने में मदद करें और अपने विधानसभा क्षेत्र में ही रहें।

पायनियर
नई दिल्ली, सोमवार 21 सितंबर, 2020

पूर्व मुख्यमंत्री बताएं भोले किसानों को क्यों कर रहे गुमराह : दुष्यंत चौटाला

विपक्ष से पूछा, केंद्र सरकार के कृषि संबंधी अध्यादेशों में कहां लिखी एमएसपी समाप्त करने की बात

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ़

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि केंद्र सरकार के कृषि संबंधित नए अध्यादेशों में कहीं भी फसलों के एमएसपी को समाप्त करने की बात नहीं कही गई है। किसानों की फसल अनाज मंडियों में बिना किसी रूकावट के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर ही खरीदी जाएंगी। ज्यादा कीमत का अवसर मिलने पर किसान चाहेंगे तो ओपन मार्केट में भी बेच सकेंगे। जिस दिन अन्नदाताओं को उनकी फसल का एमएसपी देने की व्यवस्था पर कोई आंच आएगी, उसी दिन मैं अपना पद छोड़ दूंगा। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर पत्रकारों के सवालों के जबाव में ये बातें कहीं। इस विषय पर किसान लोग किसी के बहकावे में ना आएं।

डिप्टी सीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने राजनीतिक स्वार्थ की खातिर भोले-भाले किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नए अध्यादेशों का विरोध करने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री रहते हुए ना केवल ओपन मार्केट की वकालत की थी बल्कि केंद्र की तात्कालिक मनमोहन सिंह सरकार द्वारा गठित समिति के चेयरमैन के तौर पर इन सिफारिशों पर दस्तखत भी किए थे। उन्होंने हुड्डा से सवाल किया कि वे किसानों को बताएं कि उनके इस दोगली नीति को अपनाने के पीछे क्या मजबूरी है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार अगले माह से खरीफ फसलों का एक-एक दाना तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा।

सीएम, डीजीपी, गृहसचिव दिनभर लेते रहे जिलों से रिपोर्ट

कृषि अध्यादेशों के खिलाफ पंचकूला से पलवल तक एक हुए किसान

पायनियर समाचार सेवा। चंडीगढ

एक तरफ रविवार को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कृषि अध्यादेश पास करवाए तो दूसरी तरफ हरियाणा के हजारों किसान सड़कों पर उतर आए। हरियाणा में दिनभर पंचकूला लेकर पलवल तक और मेवात से लेकर सिरसा तक न केवल सड़कें जाम रहीं बल्कि किसानों ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन भी किए। कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की खबर नहीं है।

भारतीय किसान यूनियन ने हरियाणा के 17 संगठनों के सहयोग के साथ रविवार को चक्का जाम करने का ऐलान किया था। जिसे लेकर प्रदेश की पुलिस व सरकार शनिवार रात से ही सतर्क थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव तथा गृहसचिव विजय वर्धन सभी जिलों से पल-पल की अपडेट लेते रहे। पूरे प्रदेश में बीस हजार से अधिक पुलिस के जवान तैनात किए गए थे।

किसान आंदोलन में पुलिस व सरकार की हुई परीक्षा

हरियाणा में रविवार को किसान आंदोलन के दौरान प्रदेश सरकार तथा पुलिस के संयम की परीक्षा हुई। कई जिलों से मिल रही खबरों के मुताबिक कई बार उग्र माहौल हुआ लेकिन पुलिस को कर्मियों को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह लाठीचार्ज नहीं करेंगे। जिसके चलते जिला पुलिस अधीक्षक बार-बार जवानों को निर्देश देते रहे कि कोई भी कर्मचारी व अधिकारी प्रदर्शन के दौरान अपना संयम नहीं खोएगा और स्थिति को बेहद सामान्य तरीके से नियंत्रित किया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

आर्ट ऑफ लिविंग का ऑनलाइन सुदर्शन क्रिया फॉलोअप

कैथल। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था कैथल इकाई के तत्वावधान में साधकों को आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ रखने के लिए योग, ध्यान तथा गुरु-ज्ञान जैसे दिव्य गुणों से सुसज्जित राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन सुदर्शन क्रिया फॉलोअप कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्या सोनिया मिगलानी संग प्रतिभागी साधकों द्वारा सम्पूर्ण विश्व-कल्याण के लिए मंगलकामना के पवित्र श्लोक के मंगल गायन के साथ हुआ। फॉलोअप संयोजक डॉक्टर राजेश सीकरी ने बताया कि आचार्या सोनिया मिगलानी के पावन सानिध्य में साधकों ने गुरुदेव रविशंकर की पवित्र वाणी में अद्भुत सुदर्शन क्रिया के पश्चात् ध्यान करते हुए परमानन्द एवं दिव्य-ऊर्जा की सुखद अनुभूति अर्जित की। कार्यक्रम के अंतिम चरण में आचार्या सोनिया मिगलानी संग प्रतिभागी साधको द्वारा पावन श्लोक के मधुर गायन के माध्यम से प्रार्थना की गई । आज के आयोजन से आचार्या सोनिया मिगलानी, अमर ठाकुर, कुलदीप सिंह, विनोद कुमार, गायत्री खुराना, सुषमा वत्स, दिव्या शर्मा तथा कमल कान्त गाँधी आदि साधक लाभान्वित हुए।

कैथल में तीनों अध्यादेश के विरोध में लगाया जाम

कैथल। तीन अध्यादेश बिल लागू करने के विरोध स्वरूप आज यहां कैथल में किसानों ने जाम लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया व तितरम मोड़ पर धरना व प्रदर्शन किया। इस अवसर पर जहां किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी की परवाह न करते हुए प्रदर्शनकारियों ने सोशियल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई। रविवार के प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी ने भी अपना खुला समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखबीर चहल ने पत्रकारों को बताया कि आज इस बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ वोट करेगी। किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला कर इनका साथ देगी। किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो सरकार इन तीन अध्यादेशों को वापिस ले नहीं तो सरकार गंभीर परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। धरने पर बैठे किसान नेताओं ने सरेआम चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाली 25 तारीख को समूचा भारत इन बिलों के विरोध में बंद रहेगा। उस दिन किसान न तो दूध की सप्लाई करेंगें, ना ही फलों व सब्जियों की सप्लाई की जाएगी। इसके साथ साथ मुख्य मार्गों को भी जाम लगाकर बंद किया जाएगा।

रेलवे एम्प्लाइज यूनियन ने निजीकरण के खिलाफ निकाला जुलूस

भिवानी। भारतीय रेलवे के निजीकरण के किये जाने के उद्देशीय से केन्द्र सरकार द्वारा 151 गाड़ियों को प्राइवेट कंपनी को सौंपे जाने व अन्य लंबित मांगों को लेकर निपटारा नहीं किये जाने के खिलाफ नार्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन के द्वारा 14 से 19 सितंबर तक विरोध सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी विरोध सप्ताह के तहत 18 सितम्बर की रात 7 बजे रेलवे स्टेशन से लेकर नेकीराम चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें काफी रेल कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और निजीकरण के खिलाफ जोरादर नारे लगाए गए। मंडल युवा संयोजक कृष्ण कौशिक ने बताया कि विरोध सप्ताह के तहत उन्होंने अलग-अलग जगह जाकर आम पब्लिक को निजीकरण होने के बाद आने वाली परेशानी के बारे में अवगत करवाया।

आज होगा भिवानी में कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन

भिवानी। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन फौजी ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी तीनों अध्यादेश पारित करके किसानों को तबाह की दलदल में धकेल दिया है। अध्यादेश पारित होने से किसानों के समक्ष खेती से तौबा करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचेगा। हैरानी की बात ये है कि सरकार ने अवकाश के दिन राज्यसभा के सदस्यों को बुलाकर उक्त बिलों को पारित करवा लिया है। ताकि दूसरी पार्टी के राज्य सभा सदस्य इसका विरोध न कर सके। केंद्र सरकार के इस अध्यादेश से कांग्रेस कतई सहमत नहीं है। वे इसके विरोध में 21 सितम्बर को भिवानी रोष प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे। पूर्व सीपीएस फौजी ने कहा कि विगत में इस अध्यादेश के विरोध में किसान पिपली में प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने उनकी आवाज को लाठी से दबाने का प्रयास किया।

धोखाधड़ी कर 18 लाख रुपये हड़पने के दो आरोपी गिरफ्तार

कुरुक्षेत्र। अमेरिका भेजने का झांसा देकर 18 लाख रुपये हड़पने के दो आरोपियों को एंटी नारकोटिक सैल पुलिस टीम ने काबू किया है। एक आरोपी को प्रोडैक्शन पर पानीपत जेल से यहां लाया गया है, जबकि दूसरे को अन्य स्थान से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार साहिल पुत्र सोहन लाल निवासी मथाना ने मई 2020 को शिकायत की थी कि वर्ष 2019 में उसकी मुलाकात गांव कुराना जिला पानीपत निवासी जसवंत पुत्र रघबीर सिंह व सुरेंद्र उर्फ सिंदर से हुई थी।

बिजली चोरी पकड़ने गई टीम से अभद्र व्यवहार, केस दर्ज

रादौर। शिवकालोनी में बिजली चोरी पकड़ने गई निगम की टीम के साथ एक मां-बेटे ने अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान बिजली चोरी को लेकर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे एक कर्मचारी का मोबाइल युवक ने तोड़ दिया। सरकारी काम में बांधा पहुंचाते हुए टीम के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। रादौर पुलिस ने एसडीओ बिजली निगम की शिकायत पर मां-बेटे के विरूद्ध मामला दर्ज किया है। एसडीओ बिजली निगम शमशेर सिंह धारीवाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शहर की शिव कालोनी में निगम की टीम 19 सितंबर को बिजली की चेकिंग करने के लिए गई थी।

निफा ने की अपने 20वें स्थापना वर्ष के आयोजनों की शुरूआत

पायनियर समाचार सेवा। करनाल

पुण्य, पवित्रता, प्रकृति प्रेम की भावना के साथ आज निफा के 20वें स्थापना वर्ष के आयोजनों की शुरुआत की गई। 20 सितम्बर से 9 अक्टूबर तक नेशनल इंटेग्रेटेड फोरम आफ आर्टिस्ट्स एंड एक्टिविस्टस (निफा) की ओर से हर रोज एक रक्त दान शिविर लगाने साथ ही प्रतिदिन पौधा रोपण व पौधा वितरण के कार्यक्रम का आगाज आज निलोखेड़ी कस्बे की परशुराम धर्मशाला से किया गया।

कार्यक्रम में उस समय रक्त दान के पुण्य के साथ साथ पवित्रता व प्रकृति प्रेम का। भी समावेश हो गया जब हर रक्त दाता को रक्त दान के प्रमाण पत्र ओर निफा की ओर से विशेष प्रशस्ति पत्र के साथ-साथ तुलसी एक एक पौधा ओर गुरु नानक देव जी पवित्र स्थानों की मिट्टी व जल भी दिया गया। ये पवित्र मिट्टी व जल निफा द्वारा बीते वर्ष गुरु नानक देवजी के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष में निकाली गई गुरु नानक सद्भावना यात्रा के दौरान भारत व अन्य देशों से गुरु नानक देवजी से सम्बंधित स्थानों से इकट्ठी की गई थी। मुख्य अतिथि डीएसपी रमेश कुमार ने कहा कि निफा ने अपने 20 वें स्थापना वर्ष को किसी बड़े आयोजन के स्थान पर रक्तदान व पौधारोपण के साथ जोड़ कर मनाया है, जो वास्तव में सराहनीय है।

इस अवसर पर निफा के विशेष आजीवन सदस्य ऊधम सिंह कम्बोज, नगर पालिका निलोखेड़ी की प्रधान के प्रतिनिधि के तौर पर समाज सेवी सतनाम आहूजा समाज सेवी शिव नाथ कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान चंद अरोड़ा, पार्षद अर्जुन भाटिया, पार्षद सुखविंदर उर्फ़ बबलू, रणबीर सिंह संधीर, साहब सिंह निलोखेड़ी, सुरेश बराना, विक्रम भुखापुरी ने भी विशिष्ट के रूप शिरकत कर निफा के इस पुण्य अभियान की शुरुआत निलोखेड़ी से करने पर संस्था का आभार व्यक्त किया।

पानी की किल्लत झेल रहे शहरवासी : मदान

सोनीपत। समाजसेवी एवं कांग्रेस नेता निखिल मदान ने कहा कि नगर निगम प्रशासन और सरकार द्वारा रोजाना ये दावा किया जाता है कि अमृत योजना के अंतर्गत आज पूरे शहर में पानी की लाइन बिछाई जा चुकी है और हर जगह सप्लाई का पानी दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत में आज भी शहर की दर्जन भर कालोनियों में पेयजल की किल्लत चल रही है। इनसे जुड़ी समस्याएं जस की तस है।

लोगों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए और जनता के आग्रह पर टीम दीपेन्द्र सोनीपत एवं कृष्णा चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा निःशुल्क पानी के टैंकर की व्यवस्था की गई है। जिसके तहत रोजाना जरूरतमंद लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। निखिल मदान ने बताया कि शहर की दहिया कालोनी और शादीपुर गांव में पिछले एक माह से सप्लाई का पानी नहीं आ रहा है। यहां टीम दीपेन्द्र सोनीपत द्वारा रोजाना पानी का टैंकर भेजा जा रहा है।

मदान ने बताया कि उनके जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्हें काफी लोगों ने बताया कि गांव और कॉलोनी के अंतिम छोर पर बसे घरों में सप्लाई का पानी नहीं आता और उनके घर तक आते-आते पानी पीछे से बंद कर दिया जाता है। वहीं शादीपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में लगे टयूबवेल को खराब हुए महीना बीत चुका है। इन सभी समस्याओं को लेकर लोग काफी बार निगम कार्यालय में शिकायत कर चुके हैं।

किसान, व्यापारियों व मजदूरों के खिलाफ है अध्यादेश

कुरुक्षेत्र। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस महिला विंग की प्रदेश उपाध्यक्षा सुनीता नेहरा ने कहा कि भाजपा सरकार के तीन अध्यादेश किसानों, व्यापारियों व मजदूरों के खिलाफ है। भाजपा ने सत्ता के नशे में इन्हें पास करवाया है। सुनीता नेहरा रविवार को पत्रकारों से बातचीत कर रही थी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरु से ही इन अध्यादेशों का विरोध कर रही है और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले किसानों के साथ हमेशा खड़ी है। उन्होंने बताया कि इन अध्यादेशों के खिलाफ पार्टी द्वारा 21 सितम्बर को जिला लघु सचिवालय पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। जिसमें पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे।

हरियाणा सरकार जल्द करें अनुसूचित आयोग का गठनः डाबला

रेवाड़ी। हरियाणा कांग्रेस के प्रव1ता औमप्रकाश डाबला ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में पिछले १०० दिनों से चेयरमैन व सदस्यों के खाली पड़े पद सरकार की एससी विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। सरकार को चाहिए कि इन पदों को तत्काल प्रभाव से भरें तथा हरियाणा में भी आयोग का जल्द से जल्द गठन करें।

कांग्रेस प्रव1ता ने जारी एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में सभी पद खाली पड़े हैं, जो चिंता का विषय है। इसी प्रकार हरियाणा में भी आयोग का प्रस्ताव तथा गजट नोटिफिकेशन हो चुका है। सरकार इस मामले में सिविल सेवा के एक अधिकारी को सदस्य सचिव भी नियु1त कर चुकी है, लेकिन इसमें भी आज तक अध्यक्ष व सदस्यों की नियु1ित नहीं हो पाई है।

अल्जाइमर रोग में मरने लगती है मस्तिष्क की कोशिकाएं : डा. शैली

विश्व अल्जाइमर दिवस 2020-21 सितंबर पर विशेष

कुरुक्षेत्र। अल्जाइमर रोग स्मृति लोप का सबसे आम कारण है। 50 से 75 फीसदी मामलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। बढ़ती उम्र इस बीमारी का मुख्य कारण मानी गई है। ये जानकारी लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक और हृदय एवं छाती रोग विशेषज्ञ डा. शैलेंद्र ममगाईं शैली ने आज विश्व अल्जाइमर दिवस की पूर्व संध्या पर दी।

डा. शैली ने बताया इस बीमारी में मस्तिष्क में हो रही हानि की खास पहचान है बीटा-एमीलायड और न्यूरो फिबरलरी टैंगल, जिन्हें जिन्हें प्लैक और टेंगल नाम से भी जाना जाता है। इनके कारण मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं। वह एक दूसरे को संदेश ठीक ढंग से नहीं पहुंचा पाती और मस्तिष्क सिकुड़ने लगता है। बीमारी के बढने के साथ-साथ मस्तिष्क के अनेक भाग भी ठीक से काम नहीं कर पाते। इससे बचने का को पक्का तरीका अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं। जिनके अपनाने से इसकी संभावना कम हो जाती है, जिनमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, नियमित व्यायाम और पौष्टिक भोजन करना, सक्रिय सकारात्मक जीवन बिताना, अर्थ पूर्ण काम करना, अवसाद या अवसाद पैदा करने वाली परिस्थितियों से बचना, लोगों से मिलना जुलना, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना मुख्य रूप से शामिल हैं।

रक्तदान रूपी सेवा से बढकर नहीं कोई दूसरी मानव सेवा : सांसद रमेश कौशिक

शिविर में भाजपाइयों ने किया 101 यूनिट रक्तदान

पायनियर समाचार सेवा। सोनीपत

अग्रसेन भवन में आयोजित शिविर में रक्तदान करते भाजपा नेता राजीव जैन।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के उपलक्ष में आयोजित रक्तदान शिविर की शुरुआत मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने स्वयं रक्तदान करते हुए की। शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 101 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। सेक्टर-14 स्थित अग्रसेन भवन में सेवा सप्ताह के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें सोनीपत विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ सांसद रमेश कौशिक व भाजपा जिलाध्यक्ष एवं विधायक मोहनलाल बड़ौली तथा पूर्व मंत्री कविता जैन और पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया। साथ ही उन्होंने पं. दीनदयाल उपाध्याय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं पर भी माल्यार्पण करते हुए नमन किया।

सांसद रमेश कौशिक ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्द्धन करते हुए कहा कि इस सेवा से बढकर दूसरी कोई मानव सेवा नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मोत्सव के मौके पर रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। इनमें भाजपा कार्यकर्ता बढ़-चढकर रक्तदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव तथा पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को ऐतिहासिक रूप में मनाया जा रहा है। सेवा के कार्य बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं, जिन्हें नियमित रूप से जारी रखा जाएगा।

जिलाध्यक्ष एवं विधायक मोहनलाल ने रक्तदान को जीवनदान की संज्ञा दी। पूर्व मंत्री कविता जैन ने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रक्तदान करना गौरवमयी है। पूर्व मीडिया सलाहकार एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव जैन ने इस मौके पर कहा कि रक्तदान एक महादान है। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

स्ट्रीट लाइट और सफाई व्यवस्था से बदहाल हेमनगरवासी

पायनियर समाचार सेवा। सोनीपत

सोनीपत। शहर के हेमनगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बदहाल व स्ट्रीट लाइटों के ठप होने से क्षेत्र में रोजाना हादसे हो रहे हैं। समस्या से परेशान लोगों ने नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन अशोक छाबड़ा को शिकायत की है। शिकायत के बाद छाबड़ा के पुत्र अनुज छाबड़ा ने मौके पर पहुंचकर लोगों से समस्या की सूची मांगी है। कांग्रेस युवा नेता अनुज छाबड़ा ने लोगों की शिकायत सुनते हुए कहा की इन समस्याओं की असली जड़ नगर निगम के चुनाव न होना है। नगर निगम के चुनाव हो जाते तो निगम के अधिकारी अपनी मनमानी से इस तरह काम न करते। निगम के अधिकारियों की मनमानी से आज शहरवासियों को विभिन्न परेशानी से जुझना पड़ रहा है। अनुज छाबड़ा ने कहा कि गठबंधन सरकार की तरफ से भी निगम के चुनाव की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कांग्रेसी नेता ने इस दौरान बरोदा उपचुनाव को लेकर भी युवाओं से आग्रह किया कि वे पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरकर लोगों को कांग्रेस की विचारधारा के प्रति जोड़ें। इस दौरान नीरज मल्होत्रा, हिमांशु शर्मा, मनोज गोयल, विकास नारंग, रमन, मेसी, महेश नारंग, विपिन ढिंगड़ा, लव, जोनी, इश कुमार, संजय नारंग आदि ने कहा कि उनके क्षेत्र में काफी समय से सफाई नहीं हो रही हैं। वहीं कूड़ा भी सडक़ों पर गिरा रहता है।

प्रेरणा

विकेश भारतीय
लेखक एवं मोटिवेशनल स्पीकर

किसानों को पुरस्कार की बजाय तिरस्कार क्यों,
ढोंगी का सम्मान मेहनती का बहिष्कार क्यों,
जिसे मालाएं फूलों की पहनानी थी आपको,
उसके जिस्म पर ये अंगारों की बौछार क्यों।

भिवानी 67 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, केवल एक नया केस आया

भिवानी। भिवानी जिले में रविवार को खबर लिखे जाने तक एक नया कोरोना पॉजिटिव का केस सामने आया है, जो कि 24 वर्षीय युवती है। अब तक जिले में कुल 2397 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। जिसमें से 1962 ठीक हो चुके हैं।

अब जिले में कोरोना के 409 एक्टिव केस है। रविवार को जिले से 100 सैम्पल लिए जा चुके है। जिले में रविवार को 67 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए है।

सीएनएच इंडस्ट्रियल इंडिया ने किए निर्यात बांग्लादेश को 100 ट्रैक्टर

पायनियर समाचार सेवा। करनाल

सीएनएच इंडस्ट्रियल इंडिया, देष के इनलैंड कंटेनर डेपो (आईसीडी) दादरी, नोएडा से बांग्लादेष पहुंची पहली मालगाड़ी से 100 कृषि कार्य ट्रैक्टर निर्यात करने वाली भारत की पहली कम्पनी बन गई है। यह ट्रैक्टर 2 सितम्बर को मालगाड़ी द्वारा बांग्लादेश को रवाना हुए थे। इन ट्रैक्टरों को लेकर 25-वैगन की इस मालगाड़ी को सार्क देशों (बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका) के व्यापार प्रमुख विकास कीकन ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया था।

मालगाड़ी 7 सितंबर, 2020 को बेनापोल, बांग्लादेश पहुंची। इसे भारतीय रेल और पूरे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए रेल मंत्रीए श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार इनलैंड कंटेनर डेपो, दादरी से 100 ट्रैक्टर बांग्लादेश निर्यात किये गए है।

इस मौके पर सीएनएच इंडस्ट्रियल इंडिया के प्रबंध निदेशक और देश प्रमुख (भारत और सार्क) रौनक वर्मा ने कहा कि, इस ऐतिहासिक घटना का हिस्सा होने की हमें बहुत प्रसन्नता है। हम हृदय से भारतीय रेल और कंटेनर कॉर्पोरेशन को उनके निरंतर सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि, कोविड-19 महामारी के इस दौर में बांग्लादेश सीमा पर देश के सबसे बड़े भूमि बंदरगाह पेट्रापोल, पश्चिम बंगाल पर सड़क से माल परिवहन रुक गया है। जिसके कारण हमारी टीम ने भारतीय रेल के नेटवर्क से ट्रैक्टर भेजने का समाधान निकाला। इस द्रुत समाधान से न केवल बांग्लादेश के डीलरों से हमारा संबंध मजबूत हुआ है बल्कि भारतीय रेल के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो गया है जिसका हिस्सा होना हमारे लिए सम्मान की बात है।''

सीएनएच इंडस्ट्रियल इंडिया बांग्लादेश में अपने डीलर नेटवर्क के माध्यम से 35 एचपी से लेकर 90 एचपी तक के केस आईएच और न्यू हॉलैंड एग्रीकल्चर ट्रैक्टरों का निर्यात और व्यवसाय करता है। कम्पनी का कस्टमर केयर सेंटर पूरे भारत और बांग्लादेश के ग्राहकों की मदद के लिए दस भाषाओं में सेवारत है और टोल फ्री नंबर 1800-419-0124 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

वी ने 405 रुपये पर लॉन्च किया एक साल का जी 5 प्रीमियम सबस्क्रिप्शन

वी के उपभोक्ता को मिलेगा एक साल के लिए जी 5 प्रीमियम सदस्यता तथा 28 दिनों के लिए 90 जीबी डेटा एवं अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम / हिसार

नया टेलीकॉम ब्राण्ड वी अब अपने प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए एक अनूठी पेशकश लेकर आया है। जिसके द्वारा वे बिना किसी अतिरिक्त लागत के एक साल के लिए जी 5 प्रीमियम सदस्यता का लाभ उठा सकते हैं। ये ऑफर रु 405 से शुरू होने वाले चुनिंदा डेटा प्लान्स पर उपलब्ध है और वी के उपभोक्ताओं को 12 भाषाओं में जी5 के प्रीमियम कंटेंट का शानदार अनुभव प्रदान करेगा। जिसके तहत उपभोक्ता ओरिजिनल्स, शोज एवं ब्लॉकबस्टर मुवीज का आनंद उठा सकते हैं।

सभी मोबाइल उपभोक्ताओं को इस आकर्षक ऑफ र के साथ मनोंरजन का लुत्फ उठाने के लिए आमंत्रित करते हुए अवनीश खोसला-मार्केटिंग डायरेक्टर, वोडाफ ोन आइडिया लिमिटेड ने कहा, ''हाल ही में कंटेंट के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। अब उपभोक्ता अपनी डिवाइसेज पर विभिन्न प्रकार का कंटेंट देखने में 25-30 फीसदी ज्यादा समय बिताते हैं (एक दिन में 3 घण्टे से ज्यादा)। जी 5 एक अग्रणी ओटीटी प्लेटफॉर्म के रूप में बेहतरीन कंटेंट पेश करता है। जो समाज के विभिन्न वर्गों को लुभाता है।

हिंदी एवं अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उकनी फि ल्में और ओरिजिनल शोज की व्यापक रेंज उन्हें हमारे लिए आदर्श साझेदार बनाती है। जो देश में बड़ी संख्या में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को लुभाएगी, जो अपने मोबाइल डिवाइसेज के साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं। रु 405 पर उपलब्ध नए नए जी 5 रीचार्ज पैकेज साथ उपभोक्ता टेलीकॉम फ ायदों के साथ-साथ एक साल के लिए जी 5 के मनोंरजन का लुत्फ भी उठा सकेंगे। ऐसे में टेलीकॉम और मनोरंजन का यह बेहतरीन संयोजन उपभोक्ताओं को बेजोड़ अनुभव प्रदान करेगा।''

जी 5 की सालाना सदस्यता रु 355, रु 405, रु 595 और रु 2595 की कीमत पर वी डेटा प्लान्स के साथ उपलब्ध है। इस साझेदारी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राहुल मरोली, सीनियर वाईस प्रेजीडेन्ट एवं हैड एसवीओडी जी 5 इंडिया ने कहा, ''जी 5 और वी उपभोक्ता उन्मुख ब्राण्ड हैं और यह साझेदारी आज के भारत के उभरते डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए मनोरंजन की अनूठी पेशकश लेकर आई है। इस बेजोड़ पेशकश के साथ वी के उपयोगकर्ता जी5 के शानदार प्रीमियम कंटेंट का लाभ उठा सकेंगे, जो 5 वी प्रीपेड रीचार्ज पैक्स के साथ 12 भाषाओं में उपलब्ध है। यह अपनी तरह की पहली साझेदारी है जो वी के उपभोक्ताओं को उनकी सुविधानुसार शानदार कंटेंट देखने का अवसर प्रदान करेगी।''

पायनियर
नई दिल्ली, सोमवार, 21 सितंबर 2020

कृषि बिल पास : किसान नाराज दिल्ली में धमक रोकने को अलर्ट

पंजाब-हरियाणा-उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं पर अतिरिक्त जवान तैनात

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

फाइल फोटो

विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच रविवार को कृषि क्षेत्र से जुड़े दो विधेयक राज्यसभा में पास हो गए। इस बिल खिलाफ विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर हमला तेज कर दिया है। इसके अलावा सड़क पर कई किसान संगठन प्रदर्शन के लिए भी उतर गए हैं। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट हो गई है। उसने पड़ोसी राज्यों में किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर ऐहतियाती तौर पर सीमावर्ती इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिकर्मी तैनात किए हैं।

पुलिस के अनुसार गाजियाबाद की ओर अशोक नगर के निकट बल की दो कंपनियां तैनात की गई हैं। फिलहाल सीमा पर कोई प्रदर्शनकारी नहीं है। इसी तरह हरियाणा सीमा पर भी सतर्कता बढ़ा दी है। डीसीपी जसमीत सिंह ने कहा उन्होंने दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर ऐहतियाती तौर पर पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा इकाई ने घोषणा की थी कि वह केन्द्र सरकार के कृषि अध्यादेशों के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी। इस दौरान उसके सदस्य

इससे पहले सीएम केजरीवाल ने रविवार को गैर भाजपा पार्टियों से अपील की कि वे राज्यसभा में कृषि विधेयकों के विरोध में अपना वोट दें क्योंकि यह किसानों की इच्छा है।

वायुसेना के रिटायर्ड अफसर की पत्नी ने छत से कूदकर दी जान

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

जनपद गौतमबुद्धनगर के दो थाना क्षेत्रों में एक महिला समेत दो लोगों ने आत्महत्या कर की। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के मीडिया प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र के सेक्टर 153 स्थित एक सोसाइटी में रहने वाली सीमा सिरोही (50) ने अपनी सोसाइटी की ऊपरी मंजिल से रविवार सुबह छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली।

उन्होंने बताया कि मृतका के पति ओमप्रकाश सिरोही वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि महिला काफी दिनों से मानसिक तनाव में थी और वह ग्राउंड फ्लोर में रहती थी। उन्होंने बताया कि सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे की सहायता से पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि उन्होंने किस मंजिल से छलांग लगाई थी।

मीडिया प्रभारी ने बताया कि एक अन्य घटना में थाना बादलपुर क्षेत्र के विश्नोली गांव में रहने वाले मनोज (40) ने रविवार सुबह घर पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि वह बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है। मौके पर पहुंची थाना बादल पुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है।

- पिछले कुछ दिनों से तनाव में थी मृतका

मुआवजे मांगते किसानों ने जेसीबी पर किया कब्जा

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

- जमीन अधिग्रहण के बाद दो साल से आंदोलन कर रहे अन्नदाता

जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा न मिलने पर पिछले दो साल से जिले के आधा दर्जन गांव के किसान आंदोलनरत हैं। जिला प्रशासन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कराने के लिए किसानों ने रविवार को जहां प्रशासन की जेसीबी मशीन पर कब्जा कर लिया वहीं मौके पर पहुंची पुलिस के जवानों को खेतों में उग रही लोकी व तोरी की सब्जी महिला किसानों ने भेंट करने का प्रयास किया।

हालांकि पुलिस के जवानों ने महिलाओं की इस भेंट को स्वीकार तो नहीं किया अलबत्ता उन्हें मुस्कराकर मौन रूप से धन्यवाद जरूर दे दिया। दरअसल, मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के तहत जिले के छह गांवों सदरपुर मोरटा, रहीसपुर, दुहाई, नगलायाकुपर और नैनापुर की जमीन कई वर्ष पहले अधिग्रहण की गई थी। किसानों का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण करने के बाद उन्हें बाजार रेट पर एक समान मुआवजा नहीं दिया गया।

इस मांग को लेकर ही किसान पिछले दो साल से मधुबन-बापूधाम आवासीय योजना के मुख्यद्वार पर धरने पर बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए किसानों ने रविवार को अनूठे अंदाज में सबसे पहले कार्यस्थल पर मौजूद जेसीबी मशीन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद मामले को शान्त करने के लिए पहुंची पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया।

मधुबन-बापूधाम में प्रशासन की जेसीबी मशीन को घेरकर खड़े किसान।

रिश्वत लेने का वीडियो वायरल, जेई सस्पेंड

नोएडा। ग्रेटर नोएडा के भट्टा गांव के विद्युत उपकेंद्र पर तैनात एक जेई पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए विभाग के अधीक्षण अभियंता ने तत्काल प्रभाव से जेई को सस्पेंड कर दिया है।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि जेई डालचंद ठसराना गांव में अवैध विद्युत मोटरों की जांच के लिए पहुंचा था। इस दौरान जेई को एक मोटर खेत पर रखी हुई दिखाई दी जो बिजली लाइन से नहीं जुड़ी थी। आरोप है कि इसके बावजूद भी जेई ने किसान चंद्रपाल सिंह को धमकी देते हुए 20 हजार लिए जिसका पीड़ित ने वीडियो बना लिया था।

सरकारी भवनों पर लगेंगे रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

- सिंचाई विभाग की देखरेख में होगा काम

बरसात के मौसम में वर्षा का पानी बेकार ना हो इसके लिए जिला प्रशासन ने सरकार के सभी अर्धशासकीय व शासकीय भवनों पर रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है।

जिलाधिकारी डॉ. अजयशंकर पांडे ने बताया कि वर्षा के दौरान यदि इस पानी का संचय कर लिया जाये तो इससे भूजल स्तर तो बढ़ेगा ही साथ ही शहर में होने वाले जलभराव की स्थिति से भी आसानी से निपटा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन ने राज्य के सभी जिलों में एक जीओ भेजा है जिसमें सभी सरकारी कार्यालयों में रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना का निर्देश दिया गया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि गाजियाबाद में इसकी शुरूआत कर दी गयी है और इस वर्ष के अन्त तक रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्थापित करने की योजना कारगर रूप से लागू हो जायेगी। खास बात यह है कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्थापित करने की योजना सिंचाई विभाग की देखरेख में होगी। जिस कार्यालय में रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग स्थापित हो जायेगा उसकी सूचना भी विभाग प्रमुख को सिंचाई विभाग को देनी पड़ेगी। रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग का नोडल अधिकारी मनोज कुमार जायसवाल को बनाया गया है जो समय-समय पर सभी विभाग प्रमुखों को तकनीकि सलाह भी देंगे।

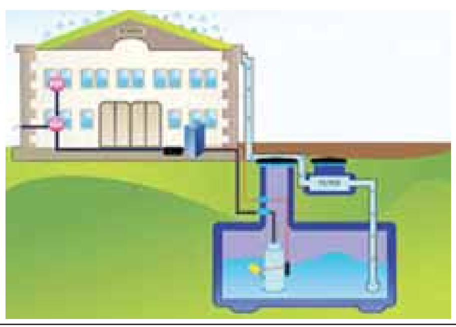

कोरोना से पिछले 5 दिनों में हुईं लगभग 40 मौतें

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 19 सितंबर के बीच कोविड-19 से प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या 30-40 के बीच में रही, जबकि इस दौरान रोजाना 4,000 से अधिक नए मामले सामने आए। आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी सामने आई है।

इस पांच दिन के दौरान हर दिन रिकॉर्ड 60,000 से 62,000 जांच की गईं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, कोविड-19 मामलों में इस महीने की शुरुआत से काफी अधिक बढ़ोतरी आई है। गत 16 सितंबर को 4,473 नए मरीज आए थे, जो अब तक एक दिन में मामलों की संख्या में सर्वाधिक बढ़ोतरी है।

प्रमित कुमार गर्ग बने डीएमआरसी निदेशक

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

भारतीय रेलवे अभियांत्रिकी सेवा (आईआरएएई) वर्ष 1992 बैच के अधिकारी प्रमित कुमार गर्ग दिल्ली मेट्रो रेल निगम के निदेशक (व्यवसाय विकास) बनाए गए हैं। उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। गर्ग दिल्ली मेट्रो में वर्ष 2002 से सेवारत हैं और कार्यकारी निदेशक/परामर्श व्यवसाय जैसे महत्त्वपूर्ण पद भी संभाल चुके हैं।

प्रमित कुमार गर्ग ने रुड़की विश्वविद्यालय (वर्तमान में आईआईटी, रुड़की) से सिविल इंजीनियरिंग की और आईआईटी दिल्ली इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। करीब 27 सालों के वृहत अनुभव में उन्होंने भारतीय रेलवे व मेट्रो के लिए कई महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यान्यवन व निष्पादन में अहम भूमिका निभाई। नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो लाइन के कुशल निष्पादन के लिए प्रोजक्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन इंडिया द्वारा उन्हें वर्ष 2019 में 'प्रोजेक्ट लीडर ऑफ द इयर' की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है।

शांति व सद्भाव समिति ने फेसबुक के उपाध्यक्ष को 23 को किया तलब

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा की शांति व सद्भाव समिति ने फेसबुक को भी दिल्ली दंगे का आरोपी माना है। इसे लेकर विधानसभा में समिति लगातार सुनवाई कर रही है। इसी कड़ी में समिति ने फिर से फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अजित मोहन को तलब किया है। इस नोटिस के जरिए उन्हें 23 सितंबर को समिति के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। इससे पहले भी मोहन को नोटिस भेजा जा चुका है। लेकिन उस नोटिस पर उन्होंने समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके थे। फेसबुक ने तल्ख अंदाज में उस नोटिस का जवाब भी दिया था।

पत्रकार के वकील का दावा झूठा है जासूसी का मामला

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ सरकारी गोपनीयता कानून के तहत दर्ज मामला झूठा है। पुलिस ने सबूतों को गढ़ा है। शर्मा के वकील आदिश अग्रवाल ने आरोप लगाया कि पुलिस का यह दावा सच नहीं है कि उनके पास से दोष साबित करने वाले सबूत मिले हैं।

आदिश अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि वह चीन के समाचार संस्थान के लिए काम कर रहे थे। विवाद सिर्फ पुलिस के इस दावे को लेकर है कि उन्हें दोष साबित करने वाले सबूत मिले हैं, जो सच नहीं है। अग्रवाल ने कहा सबूतों को बाद में गढ़ा गया है। पुलिस ने उन्हें 14 सितंबर को हिरासत में लिया था। उसी रात उनके घर की तलाशी ली गई और दोष साबित करने वाला कोई सबूत नहीं मिला। उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है।

इस्कॉन में इंटर फेथ कांफ्रेंस का आयोजन

नोएडा। रविवार को इस्कॉन नोएडा द्वारा एक इंटर फेथ कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कांफ्रेंस में विभिन्न धर्मगुरुओं ने भाग लिया। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व में शान्ति और प्रेम का सन्देश देना था।

कांफ्रेंस में नोएडा के सेक्टर 50 स्थित चर्च से विजयेश लाल, सेक्टर-50 स्थित मस्जिद से सैयद गुलाम अली नकवी, नोएडा सेक्टर-37 स्थित गुरूद्वारे से हरनीत सिंह, सेक्टर-33 स्थित आर्य समाज मंदिर से आचार्य जयेन्द्र कुमार तथा सेक्टर-33 स्थित ब्रह्मकुमारी आश्रम से राजयोगिनी बी के मन्जू ने भाग लिया।

महामारी पर फिर डराने लगी सरकार : भाजपा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

- स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के कम्युनिटी स्प्रेड के बयान की निंदा की

कोविड-19 महामारी को लेकर फिर डराने लगी दिल्ली सरकार। यह आरोप प्रदेश भाजपा ने केजरीवाल सरकार पर मढ़ा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका वाले बयान की निंदा करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए डर और भय का माहौल बनाने में लग गई है। ऐसे हालात में जहां सरकार को दिल्लीवालों को भरोसा दिलाना चाहिए वहीं लोगों के मन में डर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है।

आदेश गुप्ता ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन के दिल्ली में कोरोना के कम्यूनिटी स्प्रैड की आशंका वाले बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार एक बार फिर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए डर और भय का माहौल बनाने में लगे हैं। ऐसे हालात में जहां केजरीवाल सरकार को दिल्ली वालों को विश्वास दिलाना चाहिए वहीं लोगों के मन में डर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार को व्यवस्थाओं को सुधारने पर काम करना चाहिए ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके और डेथ रेट कम हो सके।

गुप्ता ने कहा कि गत एक सप्ताह से दिल्ली में रोजाना 4 हजार से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को भी 4071 नए मामले आए। स्थिति गंभीर है और इसे नियंत्रित करने की जरूरत है न कि लोगों के मन में डर पैदा करने की। जून में भी ऐसा ही देखने को मिला था।

संक्षिप्त समाचार

रविवार को दनकौर में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बैठक करते किसान एकता संघ के पदाधिकारी। फोटो : दीपक यादव

निजी स्कूलों की मनमानी के मुद्दे पर बैठक

नोएडा। रविवार को किसान एकता संघ की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान के नेतृत्व में कैंप कार्यालय दनकौर में सम्पन्न हुई। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रमेश कसाना ने बताया कि आगामी 24 सितंबर को किसान एकता संघ के बैनर तले नोएडा में निजी स्कूलों में अभिभावकों से हो रही मनमानी एवं शोषण के खिलाफ एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बैठक में महापंचायत को सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का आह्वान किया। इस मौके पर चौ बाली सिंह, सोरन प्रधान, देशराज नागर, रमेश कसाना, जयबीर नागर, मनोज नागर, बले नागर, सतीश कनारसी, अरबिद सैकेटरी, कृष्ण नागर, बिज्जन नागर, ओमबीर समसपुर, दुर्गेश शर्मा सहित आदि दर्जनों लोग उपस्थित रहे।

गंदगी की समस्या को लेकर गांव सरफाबाद पहुंचे प्राधिकरण इंजीनियर को शिकायत पत्र देते ग्रामीण। फोटो : दीपक यादव

गांव सरफाबाद में समस्याओं का अंबार

नोएडा। नोएडा के गांव सरफाबाद में प्राधिकरण के अधिकारियों की उदासीनता तथा लापरवाही के कारण समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सीवर की सफाई के लिए जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है परंतु हद तो तब हो गई जब सीवर से निकलने वाली गंदगी को आबादी के बीचोबीच सामने खाली पड़े प्लॉट में ही डाला जा रहा है। इससे गंदगी और बदबू के कारण आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। सपा नेता रवि यादव ने बताया कि कि गांव में जगह-जगह नालियां टूटी पड़ी हैं जिसके कारण घरों के सामने जलभराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। कई बार शिकायत दर्ज कराने के बाद रविवार को प्राधिकरण के जेई मुकेश भाटी गांव का दौरा किया। अब देखना यह है की गांव की इन समस्याओं को प्राधिकरण के अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं।

सुदीक्षा भाटी के परिजनों को सौंपा चेक

नोएडा। ग्रेटर नोएडा में डेरी स्कैनर गांव के निवासी राजेंद्र भाटी की बेटी सुदीक्षा भाटी की एक सड़क हादसे के दौरान बुलंदशहर में मौत हो गई थी। सुदीक्षा भाटी एक होनहार छात्रा थीं। उन्हें छात्रवृत्ति के आधार पर अमेरिका में दाखिला मिला था। राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेंद्र सिंह नागर की पहल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को 15 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी है। दूसरी ओर खुद सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी है।

डेंगू अभियान के तीसरे सप्ताह में अपने घर की सफाई करते सीएम केजरीवाल।

डेंगू रोकने के अभियान की रफ्तार बढ़ा रही दिल्ली सरकार

सीएम का आह्वान-दोस्तों व रिश्तेदारों को फोन कर जोड़ें

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दस हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट डेंगू विरोधी अभियान के तीसरा सप्ताह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से अपने 10 दोस्तों या रिश्तेदारों को फोन करने और डेंगू से बचाव के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया है। केजरीवाल ने रविवार को सुबह 10 बजे अपने घर में जमा साफ पानी की जांच की और इकट्ठा हुए पानी को बदला। इस दौरान उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास दिल्ली में इस बार भी पिछले साल की तरह डेंगू को हराने में सफल होंगे।

अरविंद केजरीवाल ने कहा, इस समय, दिल्ली वालें कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं लेकिन इसी मौसम में डेंगू ने भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। ऐसे में लोगों को डेंगू और कोरोना वायरस दोनों से ही सावधान रहना होगा।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने घर में जमा पानी को साफ करने के लिए उसकी जांच करें और डेंगू से बचाव के उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को इस मुहिम में शामिल होने के लिए कहें। पिछले साल इसी सामूहिक प्रयासों की वजह से मच्छरों से होने वाली बीमारी की संख्या में उल्लेखनीय कमी देखी गई थी। अभी उनकी सरकार कोरोना वायरस महामारी से निपट रही है। उन्होंने कहा कि यह डेंगू का भी मौसम है जब केस काफी बढ़ जाते हैं। यह डेंगू विरोधी अभियान का तीसरा सप्ताह है। वह नहीं चाहते हैं कि एक करोना से बचें और कहीं डेंगू की वजह से कुछ नुकसान हो जाए।

अलजाइमर्स बढ़ा देता है बुढ़ापे की मुश्किलें

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

विश्व अलजाइमर्स दिवस

जिला एमएमजी अस्पताल स्थित मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ अलजाइमर बीमारी के प्रति जागरूकता के लिए अलजाईमर्स वीक का आयोजन कर रहा है।

एसीएमओ डॉ. नीरज अग्रवाल ने बताया कि अलजाइमर्स वीक में जागरूकता के लिए मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ की ओर से बीमारी के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी जाएगी। मंगलवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन मोदीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होगा। इसके अलावा वृद्धाश्रम में जाकर भी मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ की टीम वहां रह रहे बुजुर्गों से बात करेगी और यदि किसी में लक्षण पाए जाते हैं तो उपचार भी शुरू करेगी।

मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के मनोचिकित्सक डॉ. साकेतनाथ तिवारी ने बताया कि कई बुजुर्ग भूलने की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण अलजाइमर्स नाम की बीमारी है जो अक्सर 60 साल की उम्र के बाद होती है।

हालांकि कभी-कभी डिप्रेशन के कारण भी लोग भूलने की बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी बुजुर्ग में यह लक्षण आने लगते हैं तो तुरंत किसी मनोचिकित्सक या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। यह अलजाइमर्स की शुरूआत हो सकती है। किसी भी रोग की जल्दी पहचान और उपचार शुरू होने से नजीते बेहतर होते हैं।

कंपनियों के लिए ग्रेनो में भूखंड योजना शुरू

नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आईटी और बीपीओ के लिए भूखंडों की योजना शुरू की है। यहां आईटी के 5 और बीपीओ के 15 भूखंड हैं। भूखंड लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ दीपचंद ने बताया कि जिन कंपनियों को 200 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करना है, वे औद्योगिक नीति मेगा, मेगा प्लस और सुपर मेगा की श्रेणी में आती हैं ऐसी कंपनियों को अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग एवं प्राधिकरण सीईओ के पास अपना प्रस्ताव व भूमि आवंटन का अनुरोध पत्र दे सकते हैं।

चिड़ियाघर में मातम-बीमार अफ्रीकी लंगूर ने तोड़ा दम

ग्यारह साल के शेर सुंदरम का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं, लकवा से है पीड़ित

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

चिड़ियाघर में अफ्रीकी लंगूर के दम तोड़ने से परिसर में मातम पसर गया है। यह अफ्रीकी लंगूर 10 सितंबर से बीमार था। दिल्ली चिड़ियाघर प्रशासन का दावा है कि लंगूर को सर्वश्रेष्ठ इलाज मुहैया कराया गया था। उसकी हालत पर चौबीसों घंटे नजर रखी गई। उसकी आंत को जांच के लिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली भेजा गया है। इसके साथ ही इस महीने दो लंगूर की मौत हो गई

जानकारी के अनुसार, पहले लंगूर की मौत 18 सितंबर को हुई थी। चिड़ियाघर में अब केवल तीन लंगूर बचे हैं। यहां एक 11 वर्षीय शेर सुंदरम का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। सुंदरम लकवा से पीड़ित है। दिल्ली चिड़ियाघर के निदेशक रमेश पांडे ने दावा किया पिछले छह महीने में यहा पशु मृत्यु दर में लगभग 45 प्रतिशत की कमी आई है।

पिछले साल भी चिड़ियाघर में दरियायी घोड़े के बच्चे, काला हिरण और एक अन्य जीव की मौत हो गई थी। दरियायी घोड़ा चिड़ियाघर की बीट-17 में रहता था। उसके मरने के कुछ घंटे पहले काला हिरण और एक अन्य जीव की मौत हो गई थी। तब पिछले 8 दिनों में जानवरों के मरने का आंकड़ा 5 तक पहुंच गया था। क्यूरेटर मो. रियाज खान ने हमेशा की तरह इस बार भी किसी जानवर की मौत को लेकर जानकारी नहीं वाला रवैया अपनाया था। उनका कहना था कि उनके पास फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

कुछ साल पहले तक जानवरों की मौत के 25 फीसदी मामलों की जानकारी ही प्रशासन को देता था। इस पर काफी हो-हल्ला मचा था। हाई कोर्ट में चल रहे एक मामले में चिड़ियाघर प्रशासन ने कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में माना था कि जून 2018 से 7 जून 2019 तक 245 जानवरों की मौत हो चुकी है

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक चन्दन मित्रा द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक: चन्दन मित्रा, स्थानीय सम्पादक: उषा श्रीवास्तव। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879800-4879900।

ऑनलाइन प्रतियोगिताओं ने मिटाई सरहदों की दूरी

विनोद शर्मा। पलवल

देश-विदेश के छात्रों से प्रतिस्पर्धा और शिक्षा-संस्कृति को जानने का मिल रहा मौका

कोरोना महामारी में स्कूल कॉलेजों की ओर से कराई जा रही ऑनलाइन प्रतियोगिताओं ने छात्रों को देश-विदेश के छात्रों से प्रतिस्पर्धा करने के साथ उनकी शिक्षा व संस्कृति को जानने का मौका मिल रहा है। इससे उनका ज्ञान तो बढ़ ही रहा है, सरहदों की दूरी भी मिट रही है।

पहले जहां शिक्षण संस्थानों में सीमित छात्रों को साल में तीन चार बार प्रदेश स्तरीय व एक दो बार ही राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिलता था। अब देश के साथ विदेशों में बसे छात्रों, साहित्यकारों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच अनूठा सांस्कृतिक सेतु तैयार हो रहा है। इसका बीड़ा निजी के साथ सरकारी कॉलेज भी उठा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा अत्याधुनिक तकनीक के पंखों का सहारा लिया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों की ओर से अलग-अलग विंग बनाई गई हैं, जिनमें देश के तकरीबन सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके अलावा विदेश में भी छात्र व शिक्षाविद इससे जुड़ रहे हैं। बाकायदा कैलेंडर बनाकर गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

महामारी में चलाई गई इस मुहिम के जरिए मौजूदा हालात का बेहतरीन रचनात्मक सदुपयोग करते हुए दुनियाभर के अनुभवी छात्रों को एक मंच पर लाया जा रहा है। ताकि तनावमुक्ति के साथ-साथ सांस्कृतिक, साहित्यिक और सामाजिक विषयों पर आदान-प्रदान की अनवरत प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कारगर मदद मिल सके।

- अश्विनी प्रभाकर, चेयरमैन एनजीएफ इंजीनियरिंग कॉलेज

इस अनूठी मुहिम के तहत महामारी के दौरान वेबिनार, लाइव कांफ्रेंस, जूम मीटिंग व ऑनलाइन टॉक जैसी गतिविधियों की श्रृंखला की शुरुआत हुई है। इन सभी ऑनलाइन गतिविधियों में अलग-अलग क्षेत्रों के जाने माने शिक्षाविद् बतौर स्पीकर व लीडर शामिल हो रहे हैं।

- कीर्ति सोनी, प्रधानाचार्या गुलाब पब्लिक स्कूल

ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के दौरान अनेक विषयों पर पेंटिंग, निबंध, भाषण, पावर प्वाइंट जैसी प्रतियोगिताएं होती हैं। जिनमें बांग्लादेश, मारीशस, श्रीलंका, नेपाल से लेकर कनाडा, अमेरिका और रूस समेत कई देशों के छात्र भी भाग लेते हैं। इससे छात्रों की रूचि पढ़ाई में बढ़ी है। वे पढ़ाई के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा में भी रूचिपूर्वक भाग ले रहे हैं।

- नरेश शर्मा, प्राध्यापक सरस्वती लॉ कॉलेज

हमें ऑनलाइन प्रतियोगिताओं से प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होने के साथ साथ दूसरे संस्थानों के विद्यार्थियों के अनुभवों को साझा करने का अवसर मिलता है। प्रतियोगिता में जब विजेता के रूप में नाम आता है तो खुशी होने के साथ-साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ऑनलाइन प्रतियोगिताएं अपने आपमें अनूठा प्रयास है।

- संजू तेवतिया, छात्रा

म्यूजिक की दुकान से चोरों ने लैपटॉप पर किए हाथ साफ

गुरुग्राम। सदर बाजार स्थित भार्गव प्लाजा में चोरों ने यहां भार्गव पैलेस में अलसुबह चोरी की घटना को अंजाम दिया। शनिवार अलसुबह चोर यहां एक म्यूजिक एंड कंप्यूटर्स नामक दुकान से लैपटॉप व अन्य सामान चोरी कर ले गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच-पड़ताल शुरू की।

जानकारी के अनुसार राम नगर निवासी आलोक अरोड़ा पुत्र ओमप्रकाश अरोड़ा ने थाना शहर में शिकायत देकर कहा कि उसकी भार्गव पैलेस के बेसमेंट में दुकान नंबर-9 व 10 वन म्यूजिक एंड कंप्यूटर्स के नाम से है। 18 सितम्बर 2020 को वह रात को करीब साढ़े आठ बजे दुकान बंद करके अपने घर चलाया गया था।

संक्षिप्त समाचार

इनेलो कार्यकर्ताओं ने दिया किसानों को समर्थन

पलवल। जिला इनेलो के कार्यकर्ताओं ने रविवार को ताऊ देवी लाल पार्क में चल रहे किसानों के प्रदर्शन को समर्थन दिया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों की आवाज उठाते हुए सरकार के रवैये की निंदा की। जिसमें पलवल से पूर्व प्रत्याशी सतपाल देशवाल, जिला अध्यक्ष अजीत बॉबी, शहरी अध्यक्ष अशोक शर्मा, देवी पहलवान आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला के निर्देश पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कृषि संबंधी तीन अध्यादेशों एवं पीपली में किसानों पर किए गए लाठीचार्ज और उन पर दर्ज झूठे मुकदमों के विरोध में इनेलो पार्टी द्वारा पहले चरण में प्रदेश के 14 जिलों में रोष प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। ये आक्रोश प्रदर्शन चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इनेलो पार्टी ताऊ देवी लाल का लगाया हुआ पौधा है। ये पार्टी उनकी नीतियों पर चलने वाली पार्टी है। किसानों के साथ हुई लाठीचार्ज बर्बरतापूर्ण था। इनेलो हमेशा किसान, मजदूर एवं छोटे व्यापारियों के हकों की लड़ाई लड़ती रही है। हमेशा लुटेरों के खिलाफ कमेरों के हक की आवाज बुलंद करती रही है। पिपली में किसानों के साथ हुए लाठीचार्ज एवं झूठे मुकदमे किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया, जोकि बेहद निंदनीय है।

महिला से सामूहिक बलात्कार कर दी धमकी

पलवल। रात के समय घर में घुसकर 26 वर्षीय महिला का गैंगरेप किया। विरोध करने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने आपबीती अपने पति को बताई और मामले की शिकायत पुलिस को दी। महिला थाना पुलिस ने शिकायत पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जांच अधिकारी एएसआई मुन्नी के अनुसार एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसके पति ड्राइवर हैं। जो काम के सिलसिले में अधिकतर बाहर रहते हैं। पिछली नौ सितंबर की रात वह बच्चों के साथ घर में सोई हुई थी। उसी रात करीब 12 बजे गांव दुरैंची निवासी आमिर, आरिफ व आशिक घर में घुस आए। पीड़िता का मुंह बंद कर तीनों ने बारी-बारी दुष्कर्म किया। जब आरोपियों का विरोध किया तो वे जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने फोन कर आपबीती अपने पति को बताई। पति की मदद से पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

कृषि अध्यादेश का विरोध आढ़तों को बंद करके किया

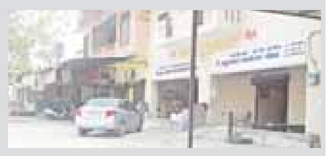

सोहना। सोहना सब्जी मंडी के आढ़तियों ने रविवार को कृषि अध्यादेश का विरोध अपनी आढ़तों को बंद करके किसानों प्रदेश स्तरीय आंदोलन का समर्थन किया। आढ़तियों का यह आंदोलन अनिश्चित काल के लिए भी बढ़ सकता है। सोहना अनाज मंडी में लाइसेंस धारक 22 आढ़तियों ने रविवार को केन्द्र सरकार के कृषि अध्यादेश प्रस्ताव को विरोध जताते हुए अपनी आढ़तों को बंद रखा। आढ़तियों ने ऐसा करते हुए रविवार को केन्द्र व राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। अनाज मंडी में सब्जी की आढ़त व दुकानें पूरा दिन खुली रही। लेकिन आढ़तियों ने अनाज का कामकाज नहीं किया। उस पर अनिश्चित काल के लिए ताला जड़ दिया है। आढ़त एसोसिएशन के प्रधान महेश आर्य ने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार उनके कारोबार को पूर्णरूप से ठप करना चाहती है। इस अध्यादेश से आढ़ती का रोजगार जीरो आ जाएगा। किसान आढ़तियों और आढ़ती किसान के माध्यम से सरकारों को कमाकर दे रहे हैं। आढ़ती विकास गर्ग का कहना है कि किसानों को छोड़कर आढ़ती अपना रोजगार नहीं चला सकता। आढ़ती किसान और सरकार के बीच की वह कड़ी हैं। जो दोनों के लिए कमाई करके देता है, लेकिन राज्य सरकार को किसान और आढ़तियों के हित का कार्य करना चाहिए। आढ़ती राजेश सिंगला का कहना है कि आज केन्द्र व राज्य सरकारें ने फसल आवक के दौरान जो नियम व शर्तें लगाई हैं। अब से पहले किसी भी सरकार ने ऐसे कानून नहीं बनाएं थे। उन्होंने कहा कि यूनियन का जो भी आदेश होगा। वह उसे मानते हुए इस हड़ताल को अनिश्चितकाल के लिए भी बढ़ सकते हैं।

मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे फसल : डीसी

नूंह। प्रदेश सरकार किसानों के कल्याणार्थ प्रतिबद्ध है। ये सुनिश्चित किया गया है कि राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्थापित मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद जारी रहेगी। ये जानकारी नूंह के डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने दी। उन्होंने आगे बताया कि इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चार प्रमुख खरीफ फसलों धान, बाजरा, मूंग और मक्का को भारत सरकार द्वारा खरीफ मौसम के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की योजना बनाई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और कृषि विभाग तथा खरीद की प्रभारी राज्य एजेंसियां इस संबंध में तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं। डीसी ने बताया कि वर्तमान समय में हम सभी कोविड-19 की निरंतर उपस्थिति देख रहे हैं। इसलिए, सरकार द्वारा विशेष व्यवस्था की जा रही है कि मंडियों में किसानों के आने के समय सामाजिक दूरी बनाए रखने के मानदंड का उचित अनुपालन हो साथ ही, संक्रमण से बचने के लिए मंडी परिसरों का और मंडी में आने वाले हर व्यक्ति का सेनेटाइजेशन किया जाए। इस संबंध में जिले में खरीद एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी और एजेंसियों के प्रयासों को समन्वित करने बारे जरूरी कदम उठाए जाएंगे, ताकि बड़े पैमाने पर होने वाली खरीद सुचारू रूप से संचालित हो और किसान राज्य सरकार के संकल्प के अनुसार लाभांवित हो सकें।

नूंह में कुपोषण के खात्मे को आगे आया बाल विकास विभाग

नूंह। नूंह जिले में बच्चों, किशोरियों व महिलाओं को कुपोषण से बचाने व जागरुक करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मना रहा है। जिले में इस अभियान की शुरुआत 7 सितंबर को की गई थी। इस दौरान प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर महिलाओं व किशोरियों को अच्छे खानपान व विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव के बारे में जागरुक किया जा रहा है। ये जानकारी नूंह उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने दी। उन्होंने बताया कि पोषण अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माताओं व बच्चों के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करना है। अभियान का लक्ष्य मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में कमी लाना भी है। अभियान से कुपोषण की शिकार तथा एनीमिया से पीड़ित महिलाएं लाभांवित हो रही हैं। ये अभियान कुपोषण को समाप्त करने के लिए एक बड़ा कदम है। उपायुक्त ने कहा कि अभियान के तहत किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं पर भी फोकस किया जा रहा है ताकि कुपोषण की समस्या का समग्र रूप से समाधान किया जा सके। उन्होंने बताया कि पोषण अभियान के मुख्य लक्ष्य में जीरो से छह वर्ष आयु समूह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं में कुपोषण स्तर को चरणबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष दो प्रतिशत की कमी लाते हुए तीन वर्षों में छह प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

गोशाला में हरियाली बढ़ाने को हुआ पौधारोपण

बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद रहे मुख्य अतिथि

भविष्य में भी पर्यावरण के प्रति सक्रिय रहेगी एक आवाज संस्था

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम के सेक्टर-9 स्थित श्रीराधा-कृष्ण गोशाला में एक आवाज संस्था की ओर से पौधारोपण करते विधायक राकेश दौलताबाद।

पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए अपने साप्ताहिक पौधारोपण कार्यक्रम के तहत रविवार को भी एक आवाज संस्था ने पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। यहां सेक्टर-9 स्थित श्री राधा-कृष्ण गोशाला में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद पहुंचे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीदुर्गा रामलीला कमेटी के चेयरमैन बनवारी लाल सैनी ने की।

श्री राधा-कृष्ण गोशाला परिसर में पौधारोपण करने के बाद अपने संबोधन में विधायक राकेश दौलताबाद ने कहा कि पर्यावरण में सुधार करना हम सबका दायित्व है। हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने चाहिए। क्योंकि पर्यावरण किसी न किसी रूप में हम इंसानों से भी खराब हुआ है। इसलिए इसमें सुधार की जिम्मेदारी सीधे तौर पर हमारी ही है। उन्होंने एक आवाज संस्था के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं की यह टोली शहर में ना केवल पर्यावरण बल्कि अन्य सामाजिक मुद्दों पर नियमित रूप से जागरुकता कार्यक्रम करती है। उन्होंने सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि इसी तरह पर्यावरण स्वच्छता की दिशा में काम करते रहें।

एक आवाज के चेयरमैन विकास गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से एक आवाज संस्था में शामिल युवाओं ने अपना कर्तव्य समझकर पर्यावरण के लिए अभियान शुरू किया है, ऐसे ही समाज का हर युवा सामाजिक कार्यों में आगे आए। क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है। युवा शक्ति जब तक जागृत और जागरुक नहीं होगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उन्होंने संस्था से जुड़े सभी युवाओं से कहा कि इसी तरह से वे नेक कार्यों में लगे रहें।

एक आवाज संस्था के अध्यक्ष राज सैनी बिसरवाल ने कहा कि संस्था के सभी सदस्यों का यही प्रयास रहता है कि अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर समाज के लिए कुछ किया जाए। यातायात के प्रति जागरुकता, शहर में सड़कों के गड्ढों को स्वयं भरना और समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराना, सफाई समेत कई मुद्दों पर संस्था नियमित तौर पर कार्य करती रहती है।

इस मौके पर गोशाला की संचालिका सरिता कटारिया, एक आवाज के उपाध्यक्ष अमित गोयल, महासचिव आशीष गुप्ता, उप-प्रधान निशांत अहलावत, प्रबंध सचिव अरुण सैनी व विक्रम, कोषाध्यक्ष राजेश सैनी, स्वच्छता कार्यकर्ता मनोज सरहोल, सह-सचिव हितेश, गगन, जय अत्री, राजन चौहान समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

आईटीआई में अब 28 सितंबर तक करें आवेदन

आईटीआई के बाद एक विषय का पेपर देकर प्राप्त कर सकते हैं 12वीं का सर्टिफिकेट

पलवल। विभाग द्वारा आईटीआई संस्थानों में दाखिले की तिथि बढ़ाकर 28 सितंबर कर दी गई है। ये निर्णय विभाग ने आवेदकों को कोरोना संक्रमण के चलते प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही समस्याओं को लेकर लिया गया है, ताकि कोई भी अभ्यर्थी दाखिले से वंचित ना रह जाए। 10वीं कक्षा पास करने के बाद आईटीआई करने वाले छात्र-छात्राएं किसी एक विषय का पेपर देकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से 12वीं का प्रमाण पत्र ले सकते हैं।

प्रधानाचार्य भगत सिंह ने बताया कि दाखिले की विवरण पत्रिका में वर्णित अन्य नियम व शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दाखिले को लेकर मेरिट में सीट एलॉटमेंट जारी होने के बारे में सूचना विभाग की वेबसाइट पर दी जाएगी। सभी आईटीआई संस्थानों में 30 फीसद सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित है। आईटीआई संस्थानों में दाखिला लेने वाली सभी लड़कियों को टूल किट या उनके लिए राशि दी जाती है। इसके अलावा एससी छात्रों को भी टूल किट दिए जाते हैं।

रिहायशी और आय प्रमाणपत्र की शर्तों को हटाया

अब विभाग ने हरियाणा से 10वीं और 8वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए आवेदन करते समय हरियाणा रिहायशी प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र लगाने की शर्त को हटा दिया है। कोरोना के चलते तहसील व नगर कार्यालय बंद चल रहे हैं, इसलिए आय प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र बनवाने में विद्यार्थियों को दिक्कतें आ रही हैं। इसी से राहत दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है इससे आवेदनों की संख्या में तेजी आना संभव है।

शहीद के नाम से बने द्वार के पास गंदगी का अंबार

फर्रुखनगर। खंड के गांव ढ़ाणा में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। कहने को तो गांव को मारुति कम्पनी ने गोद ले रखा है, लेकिन गांव में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। ग्रामीण संतरी से मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं। हर बार मात्र झूठे आश्वासन ही मिलते हैं।

गांव में जगह-जगह लगे कूड़े के ढेर और उनसे उठती बदबू से ग्रामीणों का जीवन नरक बन चुका है। ग्रामीण शिकायत करके थक चुके हैं। समाजसेवी सतेन्द्र उर्फ सिटी धनखड़, इनेलो किसान सैल के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेन्द्र सिंह धनखड़, सरपंच प्रवीण धनखड़, कर्मबीर धनखड़, अशोक पंच, पूर्ण सिंह, बिल्लू धनखड़, लीलू प्रधान आदि ग्रामीणों का कहना है कि ढ़ाणा गांव के शहीद संदीप धनखड़ का गांव है। शहीद के नाम से बनाये गए मुख्य द्वार के पास ही कूड़े के ढेर लगे हैं। गांव को देश की नामी कार निर्माता कंपनी ने गोद लिया हुआ है। फिर भी यहां सुविधाएं नहीं हैं। सफाई के लिए लगाए गये कर्मचारियों की संख्या भी कम कर दी है। कर्मचारी सफाई के नाम पर मात्रा दिखावा ही करते हैं। कूड़ा उठाने के लिए लगाए गए वाहन भी कम हैं। जिसके कारण गंदगी के ढेर लग रहे हैं। गांव की अधिकांश जमीन एचएसआईडीसी ने अधिग्रहण की हुई है। पंचायती भूमि भी नहीं बची है। ऐसे में ग्रामीणों के समक्ष कूड़ा डालना भी चुनौती बना है। हैरत की बात तो यह है कि कम्पनियों से निकलने वाले कूड़े को भी शहीद संदीप धनखड़ के नाम से बने मुख्य द्वार पर डाला जा रहा है।

ताऊ देवीलाल के जन्मदिन को लेकर जजपा की हुई बैठक

जन्म दिन के मौके पर ब्लड कैंप भी लगाएंगे जजपा के कार्यकर्ता और नेता

पायनियर समाचार सेवा। नूंह

बैठक में कार्यकर्ता ने नवनियुक्त जेजेपी के राष्ट्रीय सदस्य बदरुद्दीन चेयरमैन, नवनियुक्त जिला प्रभारी पूर्व मंत्री आजाद मौहम्मद तथा नवनियुक्त जिलाध्यक्ष तैय्यब हुसैन घासेडिया का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया।

जननायक ताऊ देवीलाल के 107वें जन्मदिन को मनाने की तैयारी को लेकर रविवार को नूंह में जेजेपी की जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें ये निश्चित किया गया कि 25 सितंबर को जननायक ताऊ देवीलालजी का 107वां जन्मदिन पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ता श्रद्धा-सुमन अर्पित कर पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल जी को याद करेंगे। मीटिंग के दौरान जजपा नेताओं ने कहा कि सबको मिलकर मेवात में जेजेपी पार्टी को संगठनात्मक तौर पर मजबूत करना है। मेवात के विकास के हर संभव प्रयास करने हैं। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को कोरोना काल में लोगों की मदद हेतु ब्लड डोनेशन कैंप का कार्यक्रम भी किया जाएगा। बैठक में प्रदेश प्रवक्ता योगेश हिलालपुरिया, पूर्व प्रत्याशी इकबाल जैलदार, जिला प्रवक्ता एडवोकेट राहुल जैन, इनसो जिलाध्यक्ष साकिर हुसैन, अल्पसंख्यक जिला प्रधान जान मोहम्मद, युवा हल्का प्रधान वसीम अहमद, नूंह हल्का प्रधान आस मोहम्मद, हल्का प्रधान समसुद्दीन, वरिष्ठ नेता गणेश दास अरोड़ा, पूर्व महिला प्रधान सरोज, सिराजुद्दीन सिराज, जावेद खान, पार्षद आजाद, मोटा सरपंच, जावेद खान, मौलवी उसमान, इरफान कुरैशी सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पीएम ने वैश्विक स्तर पर भारत को बनाया मजबूत: सुरेश भट्ट

गुरुग्राम। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की वैश्विक स्तर पर पहचान बनाते हुए देश को मजबूती दी है। आज विश्व की महाशक्तियां भी नेतृत्व के लिए भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही हैं। यह बात उन्होंने रविवार को यहां बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में डूंडाहेड़ा मंडल के तहत धर्म कालोनी में निशुल्क नेत्र जांच शिविर, गांव चौमा में रक्तदान शिविर और नवीन मंडल स्थित गांव नाथुपुर में रक्तदान शिविर में बोलते हुए कहीं। संगठन महामंत्री सुरेश भट्ट ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का ही कमाल है कि जो भारत ने समय रहते स्थिति को भांप सही निर्णय लेने से महामारी को पैर पसारने से रोकने में अहम भूमिका निभाई।

1413 बच्चों को पल्स पोलियो दवा पिलाई जाएगी

सोहना विधायक संजय सिंह नागरिक अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन किया। स्वास्थ्यकर्मी ने दवा पिलाई।

पायनियर समाचार सेवा। सोहना

स्वास्थ्य विभाग पहली बार सबसे कम 1413 बच्चों को पल्स पोलियो अभियान के तहत दवा पिलाएगा। विभाग ने अधिक संवेदनशील क्षेत्र, झुग्गी-झोंपड़ी, मलीन बस्ती और आवागमन वाले सार्वजनिक स्थानों पर बूथ बनाए हैं। इस बार पल्स पोलियो अभियान में दवा पिलाने के लिए मात्र 12 टीमें ही बनाई हैं।

सोहना के विधायक संजय सिंह ने रविवार को नागरिक अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉ. नवल किशोर, फ मेसिस्ट सुमित कुमार, डॉ. कुलभूषण पल्स पोलियो अभियान के प्रभारी समेत अन्य स्टाफ मौजूद रहा। सोहना विधायक संजय सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के मिशन को सफलता का आशीर्वाद देते हुए कार्य को कर्तव्यता से निभाने की बातें कहीं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कार्य को सराहते हुए डॉक्टर, नर्स व अन्य कर्मचारियों के कार्य को सराहा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में अन्य सुविधाएं जल्द ही पूरी कराई जाएगी। ताकि यहां आने वाला रोगी को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें।

नागरिक अस्पताल के एसएमओ डॉ. नवल किशोर ने बताया कि इस बार पल्स पोलियो अभियान को बहुत सीमित कर दिया है। केवल अधिक संवेदनशील क्षेत्र, झुग्गी-झोंपड़ियां, मलीन बस्तियां और सार्वजनिक स्थानों पर आने व जाने वाले जीरो से पांच वर्ष की उम्र वाले बच्चों को ही दवा पिलाने का कार्य किया जा रहा है।

आगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर्स, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, समाजसेवी की मदद से दवा पिलाने का कार्य किया जा रहा है। शहर में 8 बूथ स्थापित किए गए हैं। चार टीमों को सार्वजनिक स्थानों पर तैनात किया है। ताकि दूसरे शहर व गांव से आने जाने वाले बच्चों को दवा पिलाई जा सके। एसएमओ ने बताया कि टीम के सदस्यों ने कीट पहनकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का कार्य किया। ताकि विभाग का कर्मचारी और दवा पीने वाला बच्चा सुरक्षित रह सके।

शिक्षकों के कोविड-19 टेस्ट को विशेष लैब शुरू

सोहना। सोहना के नागरिक अस्पताल में राजकीय व गैर राजकीय स्कूलों में लगे शिक्षकों का कोविड-19 टेस्ट के लिए विशेष लैब शुरू की है। जहां पर शिक्षक कोविड-19 का टेस्ट निर्धारित फीस देने पर कर सकते हैं। सोमवार से राजकीय व गैर राजकीय स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं की शुरूआत की जा रही है। विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले प्राध्यापकों को कक्षाओं में जाने से पहले कोविड-19 का टेस्ट कराना अनिवार्य है। शिक्षक अपना कोविड-19 का टेस्ट आम लोगों के बीच में जाकर नहीं कर सकते हैं। नागरिक अस्पताल के प्रभारी डॉ. नवल किशोर ने बताया कि प्राध्यापकों को अपना कोविड-19 का टेस्ट कराने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित फीस जमा करानी होगी। जिसके लिए तीन प्रकार के टेस्ट तय किए गए है। तीनों श्रेणी के टेस्टों की फीस अलग-अलग देनी होगी। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 1600 रुपये, रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 650 तथा एलाइज टेस्ट के लिए 250 रुपये की फीस तय की गई है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों अधिक भीड़भाड़ व आम लोगों के बीच में रहकर कोविड-19 का टेस्ट न कराएं।

आइसोलेशन बोर्ड लगाने में मुंह देख टीका का आरोप

तावडू। तावडू में कोरोना के अब तक 300 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। ये आंकड़ा जिले के सातों ब्लॉकों में टॉप पर है। लेकिन यहां के अधिकांश कोरोना संक्रमित होम आइसोलेशन व उनके स्वजन क्वारेंटाइन नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं।

स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले इन लोगों को कई बार चेतावनी दे दी, लेकिन इन लोगों के आगे ये चेतावनी भी बौनी साबित हो रही है। अब विभाग ने ऐसे लोगों को सूचीबद्ध कर लिया है व इनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई को लेकर स्थानीय प्रशासन को लिखित शिकायत देने की बात कही है। विभाग ने होम आइसोलेशन व क्वारेंटाइन लोगों की जो सर्वे कराई है उसमें सामने आया है कि जिन कोरोना संक्रमितों को विभाग ने होम आइसोलेट किया हुआ है उनमें से अधिकांश विभागीय नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

इन आइसोलेट मरीजों के साथ इनके जिन स्वजनों को होम क्वारेंटाइन किया हुआ है वे दो कदम आगे बढ़कर नियमों को दरकिनार कर रहे हैं। क्वारेंटाइन लोग चोरी छुपे अपने प्रतिष्ठान खोल रहे हैं। गांव व शहर की गली हो या बाजार इनका यहां बेरोकटोक आवागमन जारी है। कई मामलों में देखा गया है कि क्वारंटाइन व आइसोलेशन करने वाली विभाग की टीम मुंह देखकर टीका करती है। जो बड़ी शख्सियत या रसूखदार दिखा उसका बोर्ड घर के अंदर या एकतरफ लगा देते हैं जबकि सामान्य श्रेणी के लोगों का गेट के बाहर।

क्या कहते हैं अधिकारी

एसडीएम डा. नरेश कुमार का कहना है कि होम क्वारंटाइन व आइसोलेट लोग विभागीय नियमों का पालन करें। नियमों का पालन न करने वाले ऐसे कई लोगों की जानकारी उन तक पहुंची है। इनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सीएमओ नूंह डा. कृष्ण कुमार का कहना है कि जल्द ही औचक निरीक्षण होगा। जो लोग क्वारंटाइन व आइसोलेशन नियमों की धज्जियां उड़ाते मिले उन पर विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। वहीं जहां बोर्ड लगने में अनियमितता मिली, वहां विभागीय कर्मियों पर भी कार्रवाई तय है।

अमानवीय हरकत : सगे ताऊ ने दो मासूमों को सिगरेट से झुलसाया

बुआ और मां ने लगाया ताऊ पर दागने और प्रताड़ित करने का आरोप

दोनों पिछले 24 घंटे से कुछ बोलने की नही है स्थिति में

कविता। फरीदाबाद

चार व डेढ़ वर्षीय मासूम भाई-बहन के शरीर पर सिगरेट या बीड़ी से जलाने के दर्जनों निशान मिल है। दोनों पिछले 24 घंटे से कुछ बोलने की स्थिति में नही है। वहीं बच्ची का शरीर पूरा पीला पड़ चुका है। दोनों शनिवार की देर शाम बीके अस्पताल के पार्क में बैंच पर पड़े थे। कर्मचारियों ने अपातकालीन कक्ष में भर्ती करवा कर पुलिस को इसकी सूचना दी थी।

पर्ची से मिला नम्बर

बच्चों के पास एक पॉलीथिन में मिली पर्ची पर लिखे नम्बर पर फोन किया तो बच्चों की बुआ ने उठाया और कहा वह आ रही है। उनके पहुंचने से पहले उनकी मां पहुंची। मां बताया कि वह शौचालय गई थी। लेकिन उसके बाद वह फिर से गायब हो गई। बुआ के अस्पताल पहुंचने तक भी बच्चों होश नही आया था।

ताऊ ने अमानवीय हरकत

बच्चों की बुआ सुमन का कहना है कि वह सेक्टर-56 में रहती है। उसका छोटा भाई सेक्टर-18 में रहता था। उसके यह दो बच्चे है, जिसमें बड़ा बेटा चार वर्ष का है और छोटी बेटी डेढ़ वर्ष की है। उसके भाई का गत 28 जुलाई को बीमारी के कारण देहांत हो गया था। उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी ने बच्चों की जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया था। जिस पर दिल्ली के मीठापुर में रहने वाला उसका बड़ा भाई बच्चों को अपने साथ ले गया। लेकिन उसने बच्चों को इस हालत में यहां लाकर पटक दिया। मामले का पता चलने पर वह भाई के घर गई तो वह कमरा खाली कर जा चुका था। बच्चों को दिल्ली में प्रताड़ित किया गया है, इसलिए यहां की पुलिस ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है।

बच्चों की हालत नाजुक

बच्चों की मां बार-बार अपनी बात बदल रही है। उसने पहले तो कहा कि बच्चों को वह छोड़कर शौचालय गई थी। फिर उसने कहा कि बच्चे उसके जेठ के पास थे। जेठ ने बच्चों को जलाकर यहां फेंक दिया है। दोनों बच्चों की हालत नाजुक है, लेकिन वह अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह दोनों बच्चों को पाल सके।

करेंगे पूरी मदद

बच्चों की बुआ ने पुलिस मे मामला दर्ज न होने की स्थिति में चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 पर सूचना दे दी। जिला बाल संरक्षण अधिकारी गरीमा ने पायनियर को बताया कि बच्चों की सूचना और फोटो उन्हें मिली है। होश आने पर बच्चों से पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी।

कोरोना : 2 मौतें, 203 पॉजिटिव से आंकड़ा पहुंचा 17,761

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

शहर में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को 203 पॉजिटिव आने से कोरोना के मरीजों की संख्या का आंकड़ा 17,761 पर पहुंच गया है। वहीं जिले में दो लोगों की मोत होने से मृतकों की संख्या का आंकड़ा 205 पर है। राहत की बात यह है कि रविवार को 295 मरीजों ने कोरोना की जंग जीत ली। जिससे जिले का रिकवरी रेट 89.1 प्रतिशत पर पहुंच गया है।

मृतक और पॉजिटिव

जिले में कोरोना के दो मरीजों ने दम तोड़ दिया। जिसमें सेक्टर-3 निवासी 86 वर्षीय और सेक्टर-15 निवासी 69 वर्षीय दो बुजुर्ग व्यकित शामिल थे। दोनों ही कोरोना के अलावा अन्य कई गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे। वहीं 203 पॉजिटिव में नेहरू ग्राउंड, सुभाष कालोनी, मौजपुर, बड़खल, मुजेसर, यादव कालोनी, प्रतापगढ़, दयालपुर, भाटिया कालोनी, एसी नगर, सेक्टर-91, 16, 49, 2, 15, 48, 11, 58, 21, 23, 65, 81, 86, 77, स्प्रींग फिल्ड कालोनी, प्रहलादपुर, भुपानी, पुरी प्रणायाम, बसंतपुर, चाचा चौक, भूड कालोनी, अजरौंदा, नंगला, गोपी कालोनी, सीही, तजूपुर, खेड़ी कला, श्याम कालोनी, मोहना, सीकरी, विनय नगर, पुलिस लाइन, भगत सिंह कालोनी, नेहरू कालोनी, डबुआ कालोनी, जमाई कालोनी, कृष्णा कालोनी, सूर्या कालोनी, मेवला, सैनिक कालोनी, ब्राह्मणवाड़ा, फतेहपुर तगां, चावला कालोनी, फतेहपुर बिलौच से 1-1 मरीज है। डीपी कालोनी, मुजैड़ी, आदर्श नगर, नवादा, सेक्टर-तीन, 8, 55, 29, 81, 35, 84, 82, 28, जवाहर कालोनी, बड़ौली, तिगांव, ऐतमादपुर, ओल्ड फरीदाबाद, कपड़ा कालोनी से 2-2 मरीज शामिल है। सेक्टर-87, करूणा नगर, तिलपत, ईसमाइलपुर, अमामनगर, शिव दुर्गा बिहार, संजय इंकलेव से 3-3 मरीज है।

यह है आंकड़ा

अब तक कुल सैम्पल	182127
रिपोर्ट नेगेटिव आई	164072
रिपोर्ट आनी है शेष	294
अब तक कुल पॉजिटिव	17761
अब तक कुल ठीक हुए	15821
अब तक कुल मौत	205
गंभीर हालत में भर्ती	53
आईसीयू में भर्ती	09

संक्षिप्त समाचार

मंत्री ने लाइब्रेरी का किया उद्घाटन

फरीदाबाद। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा सेक्टर-8 अपना पार्क में आरडब्लूए द्वारा आयोजित लाइब्रेरी के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। जहां उन्होंने लाइब्रेरी के रिबन काटने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि लाइब्रेरी से सेक्टर वासियों को लाभ मिलेगा। शर्मा ने इंडियन ऑयल द्वारा लाइब्रेरी बनाये जाने के लिए कार्यक्रम में मौजूद इंडियन ऑयल के निदेशक का आभार जताया। मंत्री ने कहा कि आज इंडियन ऑयल देश की तरक्की में काफी योगदान दे रही है। इस अवसर पर विधायक फरीदाबाद नरेंद्र गुप्ता ने भी कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा का अपनी विधानसभा में आने पर स्वागत किया। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहां प्रदेश में जमकर विकास कार्यय हो रहे है। इस मौके पर फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मौजूद रहे। इंडियन ऑयल के कार्पोरेट के सहयोग से अपना पार्क लाइबेरीं बनाई गई। इस मौके पर इंडियन ऑयल के निदेशक डॉ, एसएसवी रामाकुमार,संघसंचालक गंगा मिश्र ,सेक्टर 8 आरडब्ल्यूए के प्रधान वीरेंद्र शर्मा, ग्यालला गुप्ता, तिलकराज, पवन सौरोत, वीएस राना, एन के गर्ग मौजूद रहे।

एकलव्य ने जीता 9 विकेट से मैच

फरीदाबाद। पहला रविन्द्र फागना टी-20 क्रिकेट लीग में एकलव्य क्रिकेट अकादमी (फ़रीदाबाद) ने एफ सी सी (गुरुग्राम) को 9 विकेट से हराया। यह मुकाबला रविंद्र फागना क्रिकेट अकादमी सिथत मैदान पर खेला गया। बीबीसीआई कोच धर्मेंद्र फागना ने बताया कि ये मैच 20-20 ओवर का है। एफसीसी (गुरुग्राम) ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाज़ी करने का निर्यण लिया। एफसीसी (गुरुग्राम) टीम की ओर बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 17.4 ओवर में 10 विकेट पर 99 रन बनाए टीम की और बल्लेबाजी करते हुए राजेश ने 28 रन, बिट्टू गुर्ज़र विकास ने 22 रन और अनिल हरसाना ने 11 रन बनाए। एकलव्य क्रिकेट अकादमी (फ़रीदाबाद) टीम की और से गेंदबाजी करते हुए उज्जवल झा, पारस डोगरा ओर स्वराज ने 2-2 विकेट हर्ष फागना, सिद्धार्थ शर्मा और अभय राजपूत ने 1-1 विकेट लिए। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए एकलव्य क्रिकेट अकादमी (फ़रीदाबाद) टीम ने 11.3 ओवर में 1 विकेट पर 101 रन बनाकर लक्ष्य को हासिल किया। टीम की और से बल्लेबाजी करते हुए हेमंत डोगरा ने 77 रन, पारस डागर ने 17 रन और रेहान राज शर्मा ने 4 रन बनाए। एफसीसी (गुरुग्राम) की और से गेंदबाजी करते हुए प्रदीप देवतवाल ने 1 विकेट लिए। अजय शर्मा और कमल खटाना के द्वारा हेमंत डोगरा (एकलव्य क्रिकेट अकादमी (फ़रीदाबाद)को मैंन ऑफ़ दा मैच का पुरस्कार दिया गया।

रक्तदान शिविर का किया आयोजन

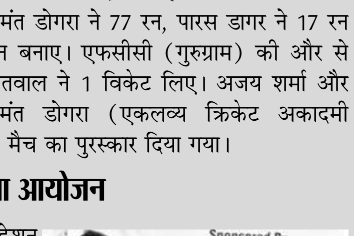

फरीदाबाद। आर्यन्स फाउंडेशन द्वारा रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ सेंट्रल के सहयोग से थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए चावला कॉलोनी, बल्लभगढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 61 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मबीर भड़ाना ने शिरकत की और रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि एक-एक रक्तदाता अपना रक्त देकर कई व्यक्तियों की जान बचा सकता है। इसलिए अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए और सजग नागरिक का फर्ज निभाना चाहिए। भड़ाना ने कहा कि थैलेसेमिक बीमारी से ग्रस्त बच्चों को हर महीने दो से तीन बार खून बदलाना पड़ता है। इसके लिए भारी मात्रा में ब्लड यूनिट की जरूरत पड़ती है।

जिला भाजपा ने विशाल रक्तदान शिविर लगाया

फरीदाबाद। भारत के यशश्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे जनसेवा के दौरान सेक्टर 19 में जिला भाजपा द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके कैबिनेट मंत्री ने उपस्थित लोगो को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत देश को नरेंद्र मोदी जैसे ऊर्जावान प्रधानमंत्री मिले है। जिनके नेतृत्व में देश का नाम पूरी दुनिया में सम्मान से लिया जा रहा है और वो दिन दूर नही जब भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु कहलायेगा। किसान के अध्यादेश पर बोलते हुए कहा कि यह किसान हितेषी है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि आज किसान आंदोलन नहीं कर रहा है बल्कि कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए जा रहे देशहित के निर्णय से बौखला कर प्रदर्शनों पर उतारू है। मंत्री ने कहा कि यह सप्ताह जनसेवा का है। देश भर में जन सेवा के कार्य भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किये जा रहे जिसमे जनता बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। जन सेवा सप्ताह रक्तदान के अलावा पेड़ पौधे लगाकर व साफ सफाई अभियान चलाकर व कपडे के बैग बांटकर कर मना रहे हैं है। इस मौके पर रक्तदान करने वालो को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता, तिगांव के विधायक राजेश नागर, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, फरीदाबाद की मेयर सुमन बाला, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव अजय गौड, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मूलचन्द मित्तल, वजीर सिह डागर, विमल खंडेलवाल, किरण सौरोत, जिला रेडक्रॉस के सचिव सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

रजिस्ट्री समस्या का समाधान कराने पर मंत्री का आभार जताया

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

एस्टेट एजेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन पंजीकृत 1987 एवं ग्रेटर फरीदाबाद बिल्डर एसोसिएशन का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल फीएवा के महासचिव गुरमीत सिंह देओल के नेतृत्व में भू-संपत्तियों के पंजीकरण में नए पोर्टल द्वारा जो समस्याएं आ रही थी, उन्हें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के समक्ष उठाया था। मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा दिया गया आश्वासन व उस पर तुरंत समाधान का जो कार्य किया गया, उसके लिए समस्त सदस्यों ने मिलकर सेक्टर 8 स्थित उनके कार्यालय में उन्हें फूलों का गुलदस्ता व एक पौधा भेंटकर उनका धन्यवाद व आभार प्रकट किया। मंत्री ने भविष्य में भी किसी प्रकार की समस्या आने पर निसंकोच उनके कार्यालय पर आकर बताए जाने और भविष्य में भी समस्याओं का समाधान कराए जाने का पूरा भरोसा दिया। इस अवसर पर शिवकुमार भारद्वाज, अवनीश भसीन, अजय गोयल, साहिल कक्कड़, अनिल भारद्वाज, राजीव सचदेवा व अन्य कई साथी भी उपस्थित रहे।

बहू बेटे ने मां को कमरे में बंद कर पीटा

फरीदाबाद। चंदावली गांव में कलयुगी बेटे ने अपनी बहू के साथ मिलकर 62 वर्षीय मां को कमरे में बंद कर डंडों से पीट-पीटकर घायल कर दिया। पीड़िता की आवाज सुनकर पड़ोस की महिला ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग को बचाया। घायल बुजुर्ग को अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर बेटे व बहू के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना सदर एरिया पुलिस के मुताबिक चंदावली गांव निवासी कृष्णा देवी ने पुलिस को बताया कि उसके पति बादाम सिंह की मौत हो चुकी है। उसके दोनों बेटे अपने परिवार के साथ अलग-अलग रहते हैं। महिला अकेली रहते हुए गुजारा चला रही है। आरोप है कि बड़ा बेटा व उसकी बहू महिला से बात भी नहीं करते और न ही उसे खर्चा देते हैं। कृष्णा देवी का कहना है कि शनिवार को वह अपने घर से पशुओं के वाड़े (नौहरे) में पशुओं की देखभाल करने चली गई थी।

पुलिसकर्मी बन महिलाओं से गहने ठगने वाला गिरोह किया काबू

आरोपियों से थाना सेंट्रल और सेक्टर 17 की 1-1 वारदात सुलझाई

2 सोने के कड़े और 2 सोने के कंगन किए बरामद

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

नकली पुलिस कर्मी बनकर महिलाओं लूटपाट का डर दिखाकर उनसे सोने कंगन और अन्य गहने उतरवाने वाले चार आरोपियों को क्राइम ब्रांच बदरपुर बॉर्डर ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि क्राइम ब्रांच बॉर्डर ने आरोपी साजिद, सनावर अली, यूनुस, अमजद को गिरफ्तार किया है। आरोपी साजिद और सनावर अली हरिद्वार उत्तराखंड के रहने वाले हैं। वहीं आरोपी यूनुस और अमजद, पाटिल नगर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं।

आरोपियों ने फरीदाबाद शहर में जुलाई महीने में एक ही तारीख को थाना सेक्टर 17 और थाना सेंट्रल एरिया में 2 वारदात को अंजाम दिया था। जिस पर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया गया था। पूछताछ पर आरोपियों ने बताया कि वह नकली पुलिस कर्मी बनकर सिविल ड्रेस में रहते थे। महिलाओं को अपने आप को पुलिसकर्मी बताते थे। उन्हें गुमराह कर उनके आभूषण उतरवा लिया करते थे।

मंगलवार को होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जिले में मंगलवार से सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा की कम्पार्टमेंट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसके लिए जिले में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोविड-19 को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों को सेनिटाइज किया गया है। यह परीक्षाएं 22 से 29 सितंबर तक चलेंगी।

जानकारी के मुताबिक सीबीएसई 2020 में 10वीं और 12वीं कक्षा के घोषित परिणाम में जिन विद्यार्थियों की कम्पार्टमेंट आई है, उन विद्यार्थियों के लिए परीक्षा होनी हैं। परीक्षा सुबह साढ़े दस बजे शुरू होगी। इसके चलते सभी विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 10 बजे तक पहुंचने के निर्देश जारी किए है।

यह है निर्देश

सीबीएसई की सिटी कॉओडिनेटर नीलिमा जैन ने बताया कि बोर्ड ने कम्पार्टमेंट की परीक्षा में सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। सभी का सावधान रहना अति आवश्यक है। सभी छात्र पारदर्शी हैंड सेनिटाइजर बॉटल, मास्क, हैंड ग्लब्ज, पारदर्शी पानी की बोतल, विद्यालय का आईडी कार्ड पहन कर आए। आते-जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे। परीक्षा केंद्र पर सभी नियमों का पालन करें। फेस मॉस्क का प्रयोग अनिवार्य है। किसी से भी कोई वस्तु लेने देने से बचे। सभी अभिभावक छात्रों के सुरक्षित आने जाने की व्यवस्था करें। विद्यालय में किसी भी आपात स्थिति से निबटने के लिए डयूटी पर अतिरिक्त स्टॉफ रखा जाएगा। सभी परीक्षा केंद्र प्रबंधक पुलिस प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में रहेंगे। सभी परीक्ष भवन पूरी तरह सेनिटाइज कराए जा चुके हैं।

छह परीक्षा केन्द्र

जिले में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें मॉर्डन स्कूल सेक्टर-17, सेक्टर-14 डीएवी, एनएच तीन डीएवी, सेंट जोसफ स्कूल, ग्रांड कोलंबस और फरीदाबाद मॉडल स्कूल शामिल हैं।

ताऊ देवीलाल के जन्मदिवस पर जजपा करेगी पौधारोपण

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जननायक जनता पार्टी जिला फरीदाबाद के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर (ग्रामीण), अरविंद भारद्वाज (शहरी), राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य धर्मवीर सिंह तेवतिया के सम्मान में जजपा जिला कार्यालय पर मीटिंग का आयोजन किया गया। जिला फरीदाबाद के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा सभी का फूल मालाओं से व मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष तेजपाल डागर ने बताया कि आगामी 25 सितंबर को जन नायक चौधरी देवी लाल का जन्म दिवस जिला स्तर पर बनाया जाएगा सुबह 7 बजे शहर के टाउन पार्क में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा गंगाजल से साफ कर हवन, पुष्प माला अर्पित कर मनाया जाएगा। इसके बाद 11 बजे बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में 107 यूनिट ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर एकत्रित किया जाएगा। जिला अध्यक्ष अरविंद भारद्वाज ने बताया कि चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पर शहर में पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा और शाम को पूर्व में मंत्री रहे चौधरी हर्ष कुमार द्वारा जिला कार्यालय पर नुक्कड़ मीटिंग का आयोजन कर सभी कार्यकर्ताओं से रू-ब-रू होंगे।

इस मौके पर जिला प्रवक्ता अनिल खुटैला, सुरेंद्र अत्रि, नरेंद्र अत्री, विजयपाल तेवतिया, बेगराज नागर, पार्षद दीपक चौधरी, कुलदीप तेवतिया, नागेश तेवतिया, सूरत चौहान, देवेंद्र मान, चित्रा नैन, प्रेम धनखड़, उमेश भाटी, पवन जाखड़ कमल सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

चेक चोरी कर खाते से उड़ाए 6.75 लाख

फरीदाबाद। सेक्टर 65 निवासी एक व्यक्ति ने अपनी पड़ोसी महिला पर चेक चोरी कर बैंक खाते से छह लाख 75 हजार रुपये निकालने का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। थाना आदर्श नगर में दर्ज मामले के मुताबिक सेक्टर 65 निवासी देवेंद्र सिंह ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके बड़े बेटे की हत्या हो गई थी। जिससे पत्नी की मानसिक हालत ठीक नहीं रहती। पीड़ित अपना पुराना का मकान बेच चुका है। अब सेक्टर 65 में किराए पर रहते हैं। उवह सिकंदराबाद में नौकरी करते हैं। घर में उनकी पत्नी रहती है। करीब एक साल पहले जब मकान खाली कर के जा रहे थे तो कुछ कागम व चेक पत्नी रानी को साइन कर दिए थे। ताकि उन्हें कभी भी पैसो की जरूरत पड़े तो निकाल सकें। बेटे के मर्डर के मामले में सामाजिक तौर पर बैठकर उनका फैसला हो गया था। मदद के तौर पर उन्होंने 14 लाख 50 हजार रुपए 17 सितंबर को उनके खाते में भेजे थे। 18 सितंबर को फोन पर मैसेज आया कि खाते से 6 लाख 75 हजार रुपए निकल गये हैं। बैंक जाने पता चला कि यह रकम शांति देवी के खाते में ट्रांसफर हुए हैं। उनका आरोप है कि शांति देवी पड़ोस में रहती थी। जब पीड़ित अपना समान शिफ्ट कर रहे थे तब मौके पर मौजूद थी। उन्होंने पीड़ित के घर से चेक चोरी कर रकम निकाली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

नई शिक्षा नीति पर मंच प्रदेश स्तर पर करेगा मंथन

सभी जिलों में विचार गोष्ठियों का आयोजन करने का लिया है फैसला

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को निजीकरण एवं व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने बाला बताया है। मंच ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं की जानकारी देने के लिए सभी जिलों में विचार गोष्ठियों का आयोजन करने का फैसला लिया है। जिसकी शुरुआत गांधी जयंती 2 अक्टूबर को फरीदाबाद से की जाएगी। यह फैसला रविवार को मंच के जिलाध्यक्ष एडवोकेट शिव कुमार जोशी की अध्यक्षता में सेक्टर10 में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा व संरक्षक सुभाष लांबा ने मंच द्वारा प्रदेश स्तर पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्रदान की। जिला सचिव डाक्टर मनोज शर्मा द्वारा संचालित इस बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार 2 अक्टूबर को सुबह 11बजे एनआईटी 3 स्थित चिमनीबाई धर्मशाला में विचार गोष्ठी आयोजित की जाएगी। जिसमें जाने माने शिक्षाविद् व आइपा के प्रदेशाध्यक्ष वजीर सिंह बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करेंगे और आइपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि विचार गोष्ठी में शामिल होंगे। गोष्ठी के बाद आयोजित जिला सम्मेलन में नई जिला कमेटी का चुनाव भी करवाया जाएगा। बैठक में सर्व सम्मति से पारित किए प्रस्ताव में पूरी फीस वसूलने के बावजूद प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों द्वारा कोरोना का फायदा उठाकर 30 से 40 प्रतिशत टीचरों को छंटनी करने, बेरोजगारी एवं उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर बकाया बचे टीचरों को आधा वेतन देने और कटौती किए गए वेतन का भुगतान करने का आश्वासन न देने की घोर निन्दा की गई। इस मामले में शीध्र मंच चेयरमैन एफएफआरसी को ज्ञापन सौप कर शिकायत भी करेगा।

महासचिव कैलाश शर्मा व संरक्षक सुभाष लांबा ने कहा कि नेताओं व अधिकारियों के संरक्षण में प्राइवेट स्कूल संचालक सभी नियम कानूनों का उल्लंघन करके छात्र,अभिभावकों व अपने टीचरों का भारी आर्थिक व मानसिक शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए बनाई गई फीस एंड फंडस रेगुलेटरी कमेटी (एफएफआरसी) भी स्कूलों के दबाव में अभिभावकों की कोई मदद नहीं कर पा रही है। हरियाणा सरकार द्वारा 21 सितंबर से स्कूल खोलने के निर्णय का विरोध किया गया। मंच ने अभिभावकों से कहा है कि लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए वे अपने बच्चों के भविष्य व स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न करें, अपने बच्चों को स्कूल न भेजें।

हाईरिस्क में 53 प्रतिशत बच्चों ने पी दवा

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

कोरोना महामारी के चलते इस बार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हाईरिस्क इलाके में ही पोलियों अभियान चलाया गया। जिसमें प्रथम दिन मात्र 53 प्रतिशत बच्चों ने ही पोलियों की खुराक पी। डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. रमेश ने बताया कि इस महामारी के कारण इस बार प्लस पोलियों अभियान हाईरिस्क एरियों में ही चलाया जा रहा है। इसके लिए 840 बुथ रविवार को बनाये गए थे। वहीं 14 मोबाइल टीमों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान विभाग की तरफ से दो लाख तीन हजार 233 बच्चों को पोलियों की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन पहले दिन टीमें एक लाख सात हजार 849 बच्चों को ही पोलियों की खुराक पिला सकी। जिसमें पहले दिन 53 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि शेष 43 प्रतिशत लक्ष्य को दो दिनों में पूरा किया जाएगा। जिसमें फिल्ड वर्कर व टीमे डोर टू डोर जाकर पोलियों अभियान को पूरा करेंगी। उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधाओं के लिए उनके घरों के निकट मौजूद सभी डिस्पेसरियों पर पोलियों बुथ बनाये गए है। एक बुथ बीके अस्पताल के पीपीई सेंटर में मौजूद है। पूरे जिले में बने इन 45 बुथों पर लोग घरों से आकर अपने शुन्य से 5 साल के बच्चों को पोलियों की खुराक पिला सकते है।

ये हैं हाईरिस्क एरिया

डॉ. रमेश ने बताया कि जिले में मौजूद झुग्गिया, मुख्य कालोनियों के निकट बने छोटे इलाके, डबुआ कालोनी, जवाहर कालोनी, राहुल कालोनी, एसी नगर प्रमुख हैं। वहीं बल्लभगढ़ में सुभाष कालोनी, हरी बिहार, सेक्टर-तीन के आसपास बसी कालोनियों का कुछ एरिया। वहीं प्रह्लादपुर, पल्ला के आसपास का स्लम एरिया और सभी पीएचसी के निकट बने स्लम एरिया हाईरिस्क में शामिल किए गए है।

कृषि संबंधी विधेयक

खेती का संभावित निगमीकरण

अमेरिका में खेती के निगमीकरण ने फैक्ट्री-फार्मिंग से 'खेत से प्लेट' तक अबाधित श्रृंखला तैयार हुई है। लेकिन इसने ग्रामीण समुदायों, उनकी आर्गेनिक विधियों, उनके खास उत्पाद, उनकी प्रासांगिकता और स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में विश्व खाद्य बाजार पर औद्योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कब्जा करने तथा जमीनों को उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार फसलें पैदा करने से हुई। लेकिन थोड़े ही समय में अति-उत्पादन के कारण किसानों को उचित दाम नहीं मिल सके और वे कर्ज में डूब गए। उनके पास खेती बंद कर अपनी जमीनें बेचने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा। अब किसान कुल अमेरिकी कृषि उत्पाद में एक चौथाई उत्पादन भी नहीं करते हैं और वे विशाल खाद्य कंपनियों के एक प्रकार से गुलाम बन गए हैं। इसी परिदृश्य की आशंका से अनेक भारतीय किसान कृषि संबंधी विधेयक पास करने का विरोध कर रहे हैं। हालांकि, इनसे कृषि संबंधी प्रक्रियायें तेज व सुचारु हो सकती हैं, पर किसान अपनी शर्तों पर जीने का अपना अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उनको डर है कि इससे राज्य के लिए एफसीआई द्वारा खरीद की वर्तमान व्यवस्था अंततः कमजोर हो सकती है। हालांकि, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इन विधेयकों से किसान 'सशक्त' होंगे, उनको बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा। लेकिन किसानों में बढ़ती बेचैनी के कारण ग्रामीण वोटबैंकों पर निर्भर क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे शिरोमणि अकाली दल-शिअद व जननायक जनता पार्टी-जेजेपी पर सत्तारूढ़ भाजपा से अलग होने का भारी दबाव है। इसी कारण शिअद की मंत्री हरसिमरत सिंह बादल ने केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। संसद में सुखवीर सिंह बादल ने चेतावनी दी कि प्रस्तावित कानून कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पंजाब की अनेक सरकारों का पचास साल का काम

'नष्ट' कर देंगे। सरकार जोर दे रही है कि नए कानून 'एक देश एक बाजार' बनाने में सहायक होंगे तथा किसान अपने उत्पाद वर्तमान अनाज मंडियों से बाहर भी बेच सकेंगे। लेकिन किसानों के बड़े हिस्से को खुले व प्रतियोगी बाजार से डर लगता है और वे सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करना जारी रखना चाहते हैं। उनको डर है कि निगमों से अनुबंध की स्थिति में निर्णय लेने में किसानों की स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। भले ही पुरानी व्यवस्था कमजोर विकल्प के रूप में जारी रहे, पर अंततः यह उभरती एकाधिकारी कंपनियों के सामने ध्वस्त हो जाएगी। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कामर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, 2020 घोषित कृषि उत्पाद बाजार समिति-एपीएमसी मंडियों से बाहर खरीद व बिक्री की अनुमति देता है। यह राज्य सरकारों को एपीएमसी बाजारों के बाहर व्यापार पर कोई फीस, चुंगी या लेवी लगाने पर प्रतिबंध लगाता है। कृषि उत्पादों में व्यापार करने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी तथा पैन कार्ड रखने वाला कोई भी व्यक्ति सीधे किसानों से खरीद कर सकता है। ऐसे में पंजाब जैसी राज्य सरकारों को चिन्ता है कि एपीएमसी मंडियों से मिलने वाला उनका राजस्व कम हो सकता है और यह एक प्रकार से राज्यों पर संघ का नियंत्रण होगा। फार्मर्स इम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट आन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज़ बिल, 2020 राज्य एपीएमसी कानूनों व ठेका खेती कानूनों में एकरूपता लाना चाहता है। इससे किसान परस्पर सहमत कीमत के आधार पर कार्पोरेट उद्यम से अनुबंध कर सकता है। एशेंसियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल, 2020 दालों, अनाजों, तिलहनों, खाद्य तेलों, प्याज व आलू को नियंत्रित सूची से बाहर करता है। इससे गरीबों की खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ सकती है। हालांकि, कृषि क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सा बहुत कम है, पर किसान देश की जनसंख्या का 60 प्रतिशत हैं। इस मतदाता आधार को कोई राजनीतिक पार्टी नाराज नहीं करना चाहती है। किसान समर्थक शिअद व जेजेपी के अलावा बाकी विपक्ष भी भाजपा के खिलाफ किसानों की नाराजी को मुद्दा बना सकता है।

कोविड-19 को लेकर सभी अंधेरे में

दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लिए गए दो उदाहरणों से कुछ ऐसा जाहिर होता है जो लगातार स्पष्ट होता जा रहा है कि : कोविड-19 के विरुद्ध जारी सार्वभौमिक लड़ाई में कोई सार्वभौमिक स्थापित नियम नहीं हैं।

स्वपन दासगुप्ता
(लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हैं)

दुनिया के विभिन्न हिस्सों पर दृष्टि डालें तो कभी-कभी यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि सारा विश्व एक घातक और प्रायः मृत्युकारी वायरसजनित व्याधि के विरुद्ध साझा लड़ाई लड़ रहा है जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। एक मामला है यूनाइटेड किंग्डम का। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो सुगमतापूर्वक बोलने वाले दिलकश आदमी हैं, कोविड-19 के प्रभावों को क्षीण करने के लिए उनकी सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदमों के विरुद्ध जन असंतोष व अपनी ही पार्टी के भीतर हो रही बगावत से जूझ रहे हैं। हाल ही में उठाए गए कदमों में शामिल है उन इलाकों के लोगों के मिलने पर रोक लगना जो एक परिवार में नहीं रहते हैं। अन्य इलाकों में एक छत के नीचे छह से अधिक लोगों के खड़े होने पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।

उम्मीद की जा रही है कि ये प्रतिबंध नववर्ष आने तक लागू रहेंगे। परिणामतः, जॉनसन को भय है कि ओलिवर क्रोमवेल के बाद ब्रिटेनवासियों को क्रिसमस का त्यौहार मनाने से रोकने वाले पहले शासक होंगे। दूसरा उदाहरण अपने ही देश का है जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कोविड-19 निरोधक रणनीतियों पर केंद्रित है, एक साहसी महिला जिसने कभी कोलकाता को एक और लंदन में रूपांतरित करने का इरादा घोषित किया था। महालय पर, मुबारक मौसम की शुरुआत, इस वर्ष आगामी अवसरों के प्रकाशन में इसे लगभग एक महीने का माना गया है, परम्परागत रूप से 10 दिनों के विपरीत, जिसका चरम परिणिति विजयदशमी पर देवी दुर्गा के मूर्तियों के विसर्जन के रूप में होती है, ममता बनर्जी से एक यादगार घोषणा की है। बंगालियों के भय को दरकिनार करते हुए कि इस वर्ष दुर्गा पूजा अत्यंत हल्के तरीके से मनाई जाएगी, और कुछ जगहों पर तो आयोजित ही नहीं होगी, ममता ने ट्वीट किया है कि उन पांच दिनों के दौरान जीवन त्यौहारमय रहेगा जब संपूर्ण पश्चिम बंगाल आनंदोत्सव में सराबोर हो जाता है।

दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लिए गए दो उदाहरणों से कुछ ऐसा जाहिर होता है जो लगातार स्पष्ट होता जा रहा है : कोविड-19 के विरुद्ध जारी सार्वभौमिक लड़ाई में कोई सार्वभौमिक स्थापित नियम नहीं हैं। एक साझा उम्मीद हो सकती है, राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर, कि वैज्ञानिकों के विभिन्न समूहों के बीच जारी तीव्र प्रतिस्पर्धा के चलते कोई चमत्कारी वैक्सीन ईजाद हो जाएगी जो दुनिया को इस बीमारी से बचाकर सामान्य स्थितियां वापस लाएगी। मगर इस वुहान वायरस से बचने के लिए विज्ञान की सामान्य प्रतीक्षा को छोड़कर और कुछ भी साझा नहीं है।

यहां तक कि देशों के भीतर भी, कोई सामान्य मतैक्य नजर नहीं आता। अब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव हेतु प्रचार की शैली को ही देख लीजिए। डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी, जो बिडेन, सावधानी बरत रहे हैं, सामाजिक दूरी बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं और अपने प्रचारकों को मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। प्रतिद्वंद्वी रिपब्लिकन खेमा एवं वर्तमान पदासीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैसा करते नजर नहीं आते। वे जन रैलियां कर रहे हैं और बड़ी संख्या में उनके समर्थक मास्क

> **एक साझा उम्मीद हो सकती है, राष्ट्रीय सीमाओं से ऊपर उठकर, कि वैज्ञानिकों के विभिन्न समूहों के बीच जारी तीव्र प्रतिस्पर्धा के चलते कोई चमत्कारी वैक्सीन ईजाद हो जाएगी जो दुनिया को इस बीमारी से बचाकर सामान्य स्थितियां वापस लाएगी। मगर इस वुहान वायरस से बचने के लिए विज्ञान की सामान्य प्रतीक्षा को छोड़कर और कुछ भी साझा नहीं है।**

पहनने या सामाजिक दूरी की चिंता नहीं करते हैं। इस बीच, अमेरिका कोविड-19 संक्रमितों की संख्या के मामले में शीर्ष पर है। यह भी एक प्रकार का नियंत्रण है जिसने महामारी के विरुद्ध राष्ट्र की रणनीति के विचार को परिलक्षित किया है। देश में तीव्र व्यक्तिवाद को अपनाए जाने की प्रवृत्ति सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी छाई हुई प्रतीत होती है। जिस समय महामारी को अत्यधिक प्रभावी होते देखा जा रहा है, वैयक्तिक स्वतंत्रता का दमन करने के सभी प्रयास गैर-अमेरिकी माने जा रहे हैं।

शुक्र है, भारत में ऐसा संविधान नहीं है जहां 1.3 अरब लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हों, यद्यपि यह चीन नहीं है जहां 1.4 अरनब जनसंख्या से केवल एक ही चीज करने की उम्मीद की जाती है। हमारा संविधान नागरिकों को वैज्ञानिक अभिवृत्ति अपनाने की सलाह देता है। छैनिक समझ में इसका अर्थ होता है कि किसी गंभीर स्वास्थ्य संबंधी चुनौती का सामना करते हुए हमसे विशेषज्ञ आधारित वैज्ञानिक सलाह मानने की अपेक्षा की जाती है और चीजों को व्यक्तिगत रूप से मनमाने ढंग से काम करने के लिए नहीं छोड़ना है। मगर दुर्भाग्य से, यह कहना सरल है, करना कठिन।

राष्ट्रीय स्तर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। देश में लाकडाउन खुले जाने की स्थिति के बावजूद, उन्होंने बाद-बार सामाजिक दूरी कायम रखने तथा चेहरे पर मास्क लगाए रखने की सलाह दी है। संसद के वर्तमान में जारी सत्र के दौरान लोकसभा व राज्यसभा में बैठने की सांतरित व्यवस्था की गई है तथा सांसद संसदीय भवन के अलग-अलग खंडों में बैठते हैं। बिहार में, जहां विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार हिचकिचाहट के साथ प्रारम्भ हुआ है, सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आभासी रैलियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की असमान प्रकृति के बावजूद।

पश्चिम बंगाल में, जहां दैनिक मामलों की संख्या लगभग 3,200 है और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा उद्देश्य के अनुरूप बेहतर नहीं है, वहां बीच-बीच में लाकडाउन किया जाता है जिसकी तिथियां कुछ इस तरह चुनी जाती हैं जैसे कि यह कोई चक्के वाला रूसी खेल हो। संसद में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने बताया कि राज्य सरकार अर्थशास्त्र में नोबल पुरस्कार विजेता की अध्यक्षता वाली वैश्विक परामर्शकारी परिषद के मार्गदर्शन में काम कर रही है।

ऐसे में तो यह माना जाए कि उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया है कि समय-समय पर लाकडाउन करने से वायरस पूर्ण रूप से भ्रमित हो जाएगा। यह भी मान सकते हैं कि उन्होंने यह भी सुझाव दिया होगा कि युवा छात्रों के लिए सम्मिलित प्रवेश परीक्षा में बैठना खतरनाक है, मगर बाहर निकलकर दुर्गा पूजा में भाग लेना सुरक्षित है। यह सबकुछ बहुत भ्रमित करने वाला है।

यहां पर अजीबोगरीब किस्म की वास्तविकता यह है कि वर्तमान समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी रणनीतियों के पीछे कोई विज्ञान नहीं है। लगता है कि हर कोई अंधेरे में ही भटक रहा है, रणनीतियां विकसित की जा रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि तब तक चीजें ऐसे ही बनी रहेंगी जब तक कोई नई दवा, चाहे व्लादिमीर पुतिन के रूस की प्रयोगशाला में खोजी जाए अथवा जॉनसन के अल्मा आक्सफोर्ड में, हर किसी को इस अनिश्चितता से बचा लेगी। महामारी विज्ञानियों की गणितीय मॉडलिंग की तरह जो बताती है कि लगभग 70 प्रतिशत भारत की जनसंख्या का कोविड-19 संक्रमित होना निश्चित है अथवा उन लोगों का जो नहीं हो सकते क्योंकि गोमूत्र घातक वासरस नाशक है, सबकुछ अनिश्चितता का खेल है। जीवन की इस लॉटरी में कोई विज्ञान नहीं होता, सिर्फ भाग्य की बात है।

न्यायिक सीमाओं का विस्तार

> **पिछले वर्षों में अदालतों ने भारत में न्याय का चेहरा बदल दिया है और उन मुद्दों पर ध्यान दिया है जहां कार्यपालिका अपना दायित्व निभाने में विफल रही है।**

वी के बहुगुणा
(लेखक सेवानिवृत्त सिविल सेवक हैं)

प्रशासन की किसी व्यवस्था में न्यायपालिका हमेशा सभ्य जीवन का एक हिस्सा रही है। भारतीय इतिहास में पहले राजा न्याय देने का काम करते थे। उन दिनों जनसंख्या कम थी, अपराध कम थे, अधिकांश लोग कानून का पालन करते थे, संसाधन प्रचुर थे और आज की तरह न्याय व्यवस्था पर ज्यादा दबाव नहीं था। कुल मिला कर न्याय व्यवस्था शासकों की इच्छानुसार चलती थी और यह काफी थी। लेकिन लोकतंत्र के उदय के साथ आधुनिक न्यायशास्त्र का विकास हुआ। स्वतंत्र न्यायशास्त्र को 1215 में ब्रिटेन के राजा द्वारा मैग्ना कार्टा घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद बहुत महत्व मिला। अब दुनिया के अधिकांश देशों में लोग न्यायपालिका को सरकार का स्वतंत्र स्तंभ मानते हैं। यह कार्यपालिका और विधायिका की पूरक होने के बावजूद सरकार की अन्य शाखाओं से स्वतंत्र है क्योंकि न्यायिक जवाबदेही में निष्पक्षता का सिद्धान्त अंतर्निहित है।

भारत में कामन ला की शुरुआत 1726 से हुई जब मद्रास, बंबई और कलकत्ता में मेयर्स कोर्ट की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। भारत में अदालतों का चेहरा लगातार बदलता रहा है और उन्होंने ऐसे मुद्दों पर ध्यान दिया है जहां कार्यपालिका अपना कर्तव्य निभाने में विफल रही है। केशवानंद भारती मामले से न्यायिक सक्रियता की शुरुआत हुई जब उसने फैसला दिया था कि संविधान का मूल चरित्र नहीं बदला जा सकता है। जनहित मामलों के सिद्धान्त की अवधारणा जस्टिस पी.एन. भगवती ने शुरू की। उन्होंने लोकस स्टैंडाई की परंपरागत भूमिका में परिवर्तन करते हुए अदालतों को समाज के वंचित तबकों के लिए काम करने तथा कार्यपालिका की गलतियां सुधारने के लिए खोल दिया।

निकट अतीत में पर्यावरण के संबंध में अनेक उल्लेखनीय फैसलों ने जजों को देश की जनता का प्रिय बना दिया है। इनमें जस्टिस कुलदीप सिंह व जस्टिस ए.एन. वर्मा शामिल हैं। 1996 के गोडावर्मन मामले ने भारत में वन एवं वन्यजीव प्रबंधन का रास्ता बदल दिया। वन संरक्षण कानून, 1980 व वन्यजीव संरक्षण कानून, 1972 लागू होने

के बावजूद केन्द्र व राज्य सरकारों की ढिलाई के कारण वनों और जैव-विविधता को भारी खतरा था। पिछले 24 सालों में अदालतों ने हस्तक्षेप कर कार्यकारी एजेंसियों को संरक्षण प्राविधानों के सुचारु क्रियान्वयन तथा वनों व वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण के लिए मजबूर किया है। भारत टिकाऊ वन प्रबंधन प्राविधान लागू करने वाले ट्रापिकल दुनिया के सबसे पहले देशों में था। लेकिन कार्ययोजनाओं में इसे भुला दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हस्तक्षेपों से देश में वन प्रबंधन को सुचारु बनाया है तथा संबंधित सरकारों को कार्यकारी योजनाओं के माध्यम से वन प्रबंधन नियमन के लिए मजबूर किया। आज इसके परिणाम जमीन पर दिख रहे हैं।

इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने वन क्षेत्रों में बेलगाम खनन पर नजर रखी है। इससे कार्यपालिका को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता मिली है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा गंगा नदी को जीवित प्राणी घोषित करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसने करोड़ों नागरिकों को खुशी से भर दिया है। इसमें पेड़ों, जानवरों व नदियों के अधिकारों को मान्यता दी गई है जो अपने लिए बोल नहीं सकते हैं। देश में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से कंपंसेटरी एफारेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथारिटी-कैम्पा का गठन महत्वपूर्ण है। इसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपये एकत्र हुए हैं।

एक अन्य उल्लेखनीय हस्तक्षेप में सर्वोच्च न्यायालय ने नोयडा में रियल स्टेट-राजनेता-नौकरशाह गठजोड़ पर प्रहार किया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेशों के माध्यम से आम्रपाली आवास योजना में शामिल लोगों को कठोर संदेश दिया है। राजनेताओं व नोयडा अथारिटी के अधिकारियों से मिलीभगत कर बिल्डर अनिल शर्मा ने घर खरीदारों का 8,000 करोड़ रुपया हड़प लिया था। यह अपराध उन लोगों की नाक के नीचे जारी था जिनसे जनता के हित संरक्षण की उम्मीद की जाती है। विडंबना है कि हमारा प्रशासन अपराधियों व भ्रष्ट लोगों के हाथों जनता की पीड़ा पर आंखें बंद कर लेता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अथक रूप से 40,000 से अधिक घर खरीदारों में कानून के शासन का विश्वास मजबूत किया है। अदालत ने मामले में रिसीवर नियुक्त कर बैंकों का फंड उसके आधीन कर नेशनल बिल्डिंग कार्पोरेशन को परियोजनायें पूरी करने का निर्देश दिया है। पिछले 6 महीने से आम्रपाली के प्रमोटर जेल में हैं और उनकी संपत्तियों की नीलामी हो रही है।

सवाल यह है कि हमारी कार्यपालिका अपना दायित्व निभाने में विफल क्यों होती है और अंततः न्यायपालिका को अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर हस्तक्षेप क्यों करना पड़ता है? इसका जवाब लोकतंत्र की विकृति, केवल वोट पाने की इच्छा तथा सरकार बनाना व जनता के हितों को पीछे धकेलने की राजनेताओं की आदत है। इसके कारण न्यायपालिका की सीमायें पुनः परिभाषित हो रही हैं। लेकिन न्यायपालिका को कुछ मुद्दों पर ध्यान देना होगा जिनका संबंध जनता को सस्ता न्याय दिलाने से है। यह इसलिए जरूरी है कि न्यायपालिका भी कार्यपालिका जैसी न हो जाए।

आप की बात

विश्लेषण से सीख

हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी की गई ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट में भारत 116 स्थान पर रहा जो कि पिछले साल से एक स्थान कम है। एक स्थान में कम होना कहीं ना कहीं इस कोरोना का हाल में बढ़ रही बेरोजगारी और कई समस्याएं भी हैं। इन तमाम समस्याओं से ही हम इसमें एक रैंक कम पाए हैं। महामारी के दौरान हमने कहीं चुनौतियां का सामना किया है और उन चुनौतियों से पार पाने के लिए हमने बहुत से प्रयास किए हैं और उनमें से बहुत प्रयासों में हम सफल भी हुए हैं। लेकिन परिस्थितियां बेहद विषम हैं और विश्वभर में कोरोना महामारी थमने का नाम नहीं ले रही है। विश्लेषण से पता लगता है कि महामारी से पहले अधिकांश देशों ने बच्चों की मानव पूंजी के निर्माण में लगातार प्रगति की है। हालांकि इस प्रवृत्ति के बावजूद औसत देश में शिक्षा और कई स्वास्थ्य मानकों के सापेक्ष कोई बच्चा अपनी संभावित मानव विकास क्षमता का मात्र आधा प्रतिशत ही हासिल करने की उम्मीद कर सकता है।हमें अब विकास को नाले का समावेशी विकास की ओर देखना होगा। जो कि हमारी तरक्की में भी मदद करेगा और आगे चलकर जो नए ढांचे अलग-अलग क्षेत्र में बनेंगे उन में मदद करेगा।

– **सुदर्शन सोराड़ी**, नैनीताल

अब बैक्टीरिया से खतरा

कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंच रही है, कारोबार चौपट हो गए हैं। लोगों की नौकरी भी उनसे छिन रही है। बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। यह वायरस पूरे विश्व में तांडव मचा रहा है और तो और कोरोना संकट ने मानवता के समक्ष रोजी-रोटी की बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। उल्लेखनीय है कि, कोरोना वायरस का हमला सबसे पहले झेलने के बाद अब उत्तरपूर्व चीन में हजारों लोग एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। जो बैक्टीरिया वैक्सीन बनाने वाले सरकारी बायोफार्मासूटिकल प्लांट में लीक होने के बाद फैला है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि, करीब तीस लाख लोगों की आबादी वाले लांझू में 3,245 लोगों को ब्रूसेलोसिस हो गया है। वैसे माल्टा और मेडिटरेनियन फीवर कही जाने वाली यह बीमारी इन्फेक्शन का शिकार हुए जानवरों या जानवरों के उत्पाद के उपयोग से हो सकती है। इसमें बुखार, जोड़ों में और सिर में दर्द होता है। तथा अभी तक इस इन्फेक्शन से किसी की मौत तो नहीं हुई है पर 22,000 लोगों की स्क्रीनिंग के बाद 1,401 लोगों के टेस्ट किए गए हैं। चीनी अधिकारियों का कहना है कि यह इन्फेक्शन इंसानों से इंसानों में नहीं फैल रहा है परन्तु फिर भी यह चिंता पूर्ण विषय है। – **निधि जैन,** गाजियाबाद

ट्रंप की लापरवाही

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की गूंज है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं तो जो बिडेन भी पीछे नहीं हैं। प्रतिदिन दोनों के बीच होने वाले वाद-विवाद अखबारों की सुर्खियां बटोर रहे हैं।लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच अमेरिका अभी सुधर नहीं पाया है। ट्रंप जिस तरह से प्रचार-प्रसार में जान झोंक रहे हैं वह चिंता पैदा करने वाला है, क्योंकि कहीं भी भीड़ नियंत्रित नहीं है और ना ही सोशल डिस्टेंस का कोई पालन हो रहा है। मास्क तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं।खुद ट्रंप कोरोना से बचने और इसके प्रसार को रोकने की बात जरूर कह रहे हैं मगर मास्क हो तो उनके मुंह से भी नदारद नजर आता है। लगातार भीड़ और नियमों के विरुद्ध हो रही रैलियों और प्रचार प्रसार से संक्रमण को दुगनी गति मिलेगी। अमेरिका जैसे सुशिक्षित देश में तो वर्चुअल रैली और प्रचार-प्रसार भी किया जा सकता है मगर अपनी जीत के प्रति चिंतित ट्रंप पुराने तौर-तरीकों से ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं इससे संक्रमण ही बढ़ेगा।

– **अमृतलाल मारू,** दसई, मप्र

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

फरमाया

खेती पंजाब की आत्मा है। शरीर पर घाव सहन किए जा सकते हैं लेकिन आत्मा पर घाव लगाना सहन तथा क्षमा नहीं किया जाएगा।

– **नवजोत सिद्धू**
कांग्रेस नेता

आप अन्य देशों को देखिए। आस्ट्रिया में वे वनों में रहते हैं और उनके पास आग नहीं है। उने पास अधिक विस्फोटक पेड़ होते हैं।

–**डोनाल्ड ट्रंप**
अमेरिकी राष्ट्रपति

आस्ट्रिया वह देश है जहां लोग वनों में नहीं रहते, लेकिन वन के साथ रहते हैं और प्रकृति के साथ एक नजदीकी टिकाऊ रिश्ता बनाकर रखते हैं।

– **एलिजाबेथ कोस्टिंगर**
आस्ट्रियाई कृषि मंत्री

खेती के क्षेत्र में नये युग की शुरुआत: योगी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कृषि क्षेत्र के लिये केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये दो विधेयक का विपक्षी दलों तथा कुछ राज्यों में किसानों के विरोध के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आए हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार के दोनों विधेयकों को किसानों के हित का बताते हुये कहा है कि दोनों विधेयकों से खेती के क्षेत्र में नये युग की शुरुआत होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में कृषि सुधार के दो महत्वपूर्ण विधेयकों कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 तथा कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह विधेयक कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने वाले सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों में प्रधानमंत्री के संकल्पों का प्रतिबिंब देखा जा सकता है।

● कृषि विधेयक के समर्थन में उतरे यूपी के मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दोनों विधेयक पूर्ण रूप से कृषि और कृषकों के हित में हैं। यह किसानों की आय में कई गुना वृद्धि करने वाली सिद्ध होंगे। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक एवं अभिनव कदम भी बताया।

योगी ने कहा कि अब किसानों को कानूनी बंधनों से आजादी मिलेगी, कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा, खेती-किसानी में निजी निवेश होने से तेज विकास होगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होने से देश की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान केंद्र व राज्य सरकार किसान हितों के संरक्षण के लिए कृतसंकल्पित है। किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत प्राप्त होगी। वहीं

इन विधेयकों के विरोध में कतिपय राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही टिप्पणियों को मुख्यमंत्री ने भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास बताया है। उन्होंने किसान बहनों-भाइयों से अपील की है कि वह किसी के बहकावे में न आएं। कुछ लोगों को कृषकों की उन्नति रास नहीं आती। यह वही लोग हैं जिन्होंने बीते छह-सात दशकों तक किसानों को महज वोट बैंक समझा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण और उनकी आय को दोगुना करने के लिए संकल्पित है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में लगातार प्रयास कर रही है। कृषि और किसान कल्याण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अनेक नीतिगत कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोविड महामारी के दृष्टिगत लागू लाकडाउन के दौरान ही राज्य सरकार द्वारा फल व सब्जी में 45 जिंसों को मण्डी शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जिसका किसानों को सीधा लाभ मिला। कृषक अब अपने फल या सब्जी की राज्य में कहीं से भी बिक्री करने के लिए स्वतंत्र हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा किये गये सुधारों का व्यापक तथा सकारात्मक लाभ मिलेगा। किसानों को अपनी उपज को मण्डी परिसरों में विक्रय करने में बाध्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब वे प्रदेश के अधिसूचित मण्डी के अतिरिक्त किसी और स्थान जैसे भण्डार गृह, कोल्ड स्टोरेज या खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में अपनी उपज विक्रय कर सकेंगे। फार्म गेट पर ही व्यापारियों, निर्यातकों या खाद्य प्रसस्करण इकाइयों को उचित दाम लेकर विक्रय कर सकेंगे। इससे किसानों का यातायात एवं ढुलान पर व्यय बचेगा और हानि को बचाया जा सकेगा।

कान्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिलने से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां निर्यातक तथा अन्य व्यापारी, कृषकों से व्यक्तिगत स्तर पर या संगठित तरीके से समझौता कर सकेंगे। इससे कृषकों को खाद, बीज व अन्य इनपुट्स को कम दरों पर उपलब्ध कराने, आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर कृषि कार्य कराने एवं उनकी उपज को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने में सुविधा होगी। कृषकों को राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुसार कृषि कार्य करने के अवसर भी प्राप्त होंगे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बाहर से आने वाले कृषि उत्पाद पर मण्डी शुल्क समाप्त होने पर जहां एक ओर उपभोक्ताओं का भी लाभ मिलेगा, वहीं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को भी निर्बाध रूप से कच्चा माल प्राप्त हो सकेगा। इससे ईज आफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार किसानों की उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य हेतु कटिबद्ध है। कोविड काल में भी प्रदेश के किसानों का 35.77 लाख टन गेहूं क्रय किया गया। साथ ही दलहन व तिलहन फसलों की भी खरीद की गई।

धान खरीद की तैयारियां पूरी करने के निर्देश

लखनऊ। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की खरीद पहली अक्टूबर से होनी है। इसके मद्देनजर सभी तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि धान क्रय केन्द्र सुचारु रूप से संचालित किए जाएं। यह देखा जाए कि किसानों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने धान क्रय के सम्बन्ध में राइस मिलर्स के साथ बैठक किए जाने के निर्देश कृषि उत्पादन आयुक्त को दिए।

गंगा नदी में डूबने से युवतियों की मौत पर सीएम ने जताया शोक

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशाम्बी में गंगा नदी में डूबने से हुई युवतियों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शान्ति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को इस दुर्घटना में प्रभावित परिवारों को समुचित सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

अयोध्या सड़क दुर्घटना पर सीएम दुखी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शान्ति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने सभी घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं।

28 सितंबर से सूबे के 28 जिलों में खिलाई जाएगी पेट के कीड़े की दवा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश के 28 जनपदों में बच्चों को कृमि मुक्त की दवा खिलाई जाएगी। प्रदेश में एक से 19 साल तक के बच्चों में कृमि संक्रमण की व्यापकता 76 प्रतिशत तक है। हालांकि बीते 10 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीडी अभियान का शुभारंभ कर दिया था। इसके बाद प्रदेश के 11 जनपदों में कृमि मुक्ति का अभियान चलाया गया था।

अभियान में एक से 19 साल तक के बच्चों को कृमि के संक्रमण से बचाने के पेट के कीड़ों की गोली एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी। इसके तहत अब अम्बेडकरनगर समेत 45 और जिलों में अभियान 28 सितम्बर से चलेगा। डीसीपीएम प्रीतम विक्रम ने बताया कि अभियान 28 सितंबर से सात अक्तूबर तक चलेगा। अभियान में एक से दो साल के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली 200 मिलीग्राम (आधी गोली) और दो से 19 साल की आयु वालों को एल्बेंडाजोल की गोली 400 मिलीग्राम (एक गोली) खिलाई जाएगी। जिन जिलों में यह अभियान संचालित किया जाएगा उनमें मथुरा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, हमीरपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, वाराणसी, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्धनगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, बदायूं, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, संभल, मैनपुरी, जौनपुर, भदोही, आगरा, अलीगढ़, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, बस्ती, कुशीनगर, लखनऊ, मऊ और संत कबीरनगर शामिल हैं।

कोरोना के इलाज के लिए आईसीयू के बेड बढ़ाएं: सीएम

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड.19 के लिए आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। सभी अस्पतालों में दवाई और आक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश देते हुये सीएम ने कहा है कि प्रयागराज, कानपुर नगर, लखनऊ और गोरखपुर में विशेष सतर्कता अपनाए जाने की आवश्यकता है। इन जनपदों में कान्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जाए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अपने सरकारी आवास पर अनलाक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर की कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा इससे बचाव व उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी जनपदों में इनकी सेवाओं को और बेहतर बनाते हुए संचालित किया जाए। उन्होंने इसके लिए मुख्य सचिव को समन्वय किए जाने निर्देश दिए।

● सीएम ने किया एकीकृत कोविड-19 पोर्टल एप्लीकेशन लांच, घर बैठे पता चलेंगे जांच के परिणाम

मुख्यमंत्री ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड.19 तथा यातायात के नियमों के सम्बन्ध में लोगों को व्यापक रूप से जागरूक किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सतर्कता, बचाव व जागरूकता जरूरी है। इसके लिए प्रमुख स्थानों और चौराहों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम निरन्तर एक्टिव मोड में रहें।

इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने एकीकृत कोविड.19 पोर्टल एप्लीकेशन लान्च किया। उन्होंने इस एप के शुभारम्भ पर कहा कि वैश्विक महामारी कोविड.19 के संक्रमण के दौरान प्रदेशवासियों को इस सुविधा से लाभ मिलेगा। इससे कोविड.19 के परिणामों की जानकारी सुलभ कराने की सुविधा होगी। यह लोगों के लिए अत्यन्त उपयोगी होगा तथा लोगों की जांच के उपरान्त परिणाम शीघ्र मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से ऐसी व्यवस्था विकसित की गई है कि टेस्ट करवाने वाला व्यक्ति अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नम्बर पर ओटीपी प्राप्त करके अपने कोविड.19 टेस्ट के परिणाम को स्वयं देख सकेगा तथा इसे डाउनलोड भी कर सकेगा। यह एप कोविड वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकारी संस्थानों को सहयोग एवं चिकित्सा के लिए लोगों की मदद करने में सहायक होगा।

इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक हितेश सी अवस्थी, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह तथा सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

डिजिटल पहल से जनता को स्टाम्प खरीदने का मिलेगा सुलभ विकल्प: मित्तल

● एसबीआई में हुआ ई-स्टाम्प विक्रय का शुभारंभ

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की ई-स्टाम्प विक्रय का शुभारंभ संजीव कुमार मित्तल अपर मुख्य सचिव वित्त के कर कमलों द्वारा अजय कुमार खन्ना मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ मण्डल एवं सुश्री मिनिस्थी एस महानिरीक्षक स्टाम्प एवं निबंधन की गरिमामयी उपस्थिति में आरएसीपीसी लखनऊ में सम्पन्न हुआ।

इस अवसर पर श्री मित्तल ने कहा कि इस डिजिटल पहल के द्वारा आम जनता को स्टैम्प क्रय करने का एक सुलभ विकल्प मिलेगा जिसके अंतर्गत स्टैम्प खरीदने का इच्छुक व्यक्ति स्टेट बैंक की चयनित शाखा मे जाकर विभिन्न माध्यम जैसे की नकद जमा, आरटीजीएस, नेफ्ट, चेक, द्वारा धनराशि जमा करने के उपरांत तुरंत स्टाम्प प्राप्त कर सकते हैं।

इस अवसर पर अजय कुमार खन्ना मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ मण्डल ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक आम जनता का बैंक है। लगभग 46 करोड़ खाताधारक बैंक से जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बैंक की 1700 से अधिक शाखाओ के द्वारा आम जनता को समस्त बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में लखनऊ मे ई स्टैम्प जारी करने की सुविधा, सरकारी व्यवसाय शाखा एवं आरएसीपीसी लखनऊ में प्रारम्भ की गयी है तथा शीघ्र ही यह सुविधा अन्य शाखाओं में भी उपलब्ध करायी जाएगी। बैंक हमेशा से केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के साथ उनके प्रत्येक डिजिटल पहल मे साथ रहा है एवं यह डिजिटल पहल आम जनता, राज्य सरकार एवं स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन सबके लिए सुविधाजनक है। स्टेट बैंक लखनऊ मण्डल के महाप्रबंधक नेटवर्क प्रथम दिग्विजय सिंह रावत ने इस अवसर पर सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

बीजेपी महानगर में ई-बुक का विमोचन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बीजेपी लखनऊ महानगर के मंडलों की ई-बुक का मंडल प्रभारियों द्वारा विमोचन किया गया। महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी प्रारंभ के दौरान हुए लॉकडाउन में बीजेपी लखनऊ महानगर मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी चिंता किए बगैर जरूरतमंदों को भोजन पैकेट और भोजन सामग्री किट तथा अन्य आवश्यक जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति की गई। इसके साथ साथ प्रवासी मजदूरों को भी भोजन, पानी, चप्पल आदि सहयोग एवं उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचाने सहित विभिन्न प्रकार के जो सेवा कार्य किए गए थे उन कार्यों का एक संकलन ई बुक में समाहित है। मंडल प्रभारियों द्वारा विमोचन किया गया।

निजीकरण के विरोध में ज्ञापन दो अभियान शुरू करेंगे बिजली कर्मी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिन से महात्मा गांधी के जन्मदिन तक ज्ञापन दो अभियान चलाने का निर्णय लिया है। 25 सितंबर से प्रारंभ हो रहे ज्ञापन दो अभियान के अंतर्गत बिजली कर्मी पूरे प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों व विधान सभा तथा विधान परिषद के सदस्यों को निजीकरण के विरोध में ज्ञापन देंगे। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने ऊर्जा निगमों के शीर्ष प्रबंधन की विफलता की ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यानाकर्षण करते हुए उनसे अपील की है कि महामारी के दौरान कोरोना योद्धा की तरह निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने वाले बिजली कर्मियों पर भरोसा रखा जाए और निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त किया जाए। संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों के 21 सितंबर से प्रांतव्यापी दौरे प्रारंभ हो रहे हैं।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों वीपी सिंह, प्रभात सिंह, जीवी पटेल और सुहेल आबिद ने पुन: चेतावनी दी है कि यदि पूर्वांचल विद्युत् वितरण निगम के विघटन व निजीकरण की दिशा में एक भी और कदम उठाया गया तो बिना और कोई नोटिस दिए सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मी उसी क्षण अनिश्चितकालीन आंदोलन जिसमे पूर्ण हड़ताल भी होगी, प्रारम्भ कर देंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन व सरकार की होगी। संघर्ष समिति ने बिजली कर्मियों से अनिश्चितकालीन हड़ताल और सामूहिक जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार रहने का अवाहन किया है।

संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि ऊर्जा निगमों का प्रबंधन बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं को हड़ताल के रास्ते पर धकेल रहा है। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का विघटन कर तीन छोटे निगम बनाए जाएंगे और उनका निजीकरण किया जाएगा। विघटन और निजीकरण दोनों की ही विफलता पर सवाल खड़ा करते हुए संघर्ष समिति का कहना है कि जब वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का विघटन किया गया था तब सालाना घाटा मात्र 77 करोड़ रूपए था। विघटन के बाद कुप्रबंधन और सरकार की गलत नीतियों के चलते यह घाटा अब बढ़कर 95000 करोड़ रूपए से अधिक हो गया है। इसी प्रकार ग्रेटर नोएडा में निजीकरण और आगरा में फ्रेंचाइजीकरण के प्रयोग भी पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन्हीं विफल प्रयोगों को एक बार फिर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम पर क्यों थोपा जा रहा है।

भाजपा ने कृषि बिल नहीं, अपना पतन-पत्र पारित कराया: अखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कृषि विधेयकों को किसान विरोधी करार देते हुए समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में विधेयक पारित कराए जाने की निंदा की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक कपट कर भाजपा ने कृषि बिल नहीं, अपना पतनपत्र पारित कराया है।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कृषि बिल पारित कराने के लिए ध्वनि मत की आड़ में राज्यसभा में किसानों और विपक्ष की आवाज का गला दबाया है। सरकार ने अपने कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों और धन्नासेठों के लिए भारत की दो तिहाई जनसंख्या को धोखा दिया है। लोकतांत्रिक कपट कर भाजपा ने कृषि बिल नहीं अपना पतनपत्र पारित कराया है। भाजपा की शोषणकारी साजिशों का विरोध करने का एलान करते हुए सपा अध्यक्ष ने कल सोमवार को सभी तहसील मुख्यालयों पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन करने व ज्ञापन सौंपने का एलान किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकारों को विफलताओं पर कोसा। रविवार को उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों से छात्र छात्राओं की पढ़ाई बंद है। ऑनलाइन शिक्षण कार्य केवल दिखावा सिद्ध हो रहा है। मंहगाई चरम पर है। सब्जियों व अन्य खाद्य पदार्थो के आसमान छूते भाव से जनता की थाली और थैली दोनों पर मार पड़ रही है। उन्होंने भाजपा की शोषणकारी साजिशों का विरोध करने का एलान करते हुए सोमवार को सभी तहसील मुख्यालयों पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन करने व ज्ञापन देंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी कार्यकर्ता कोरोना से बचाव नियमों का पालन करते हुए अपनी बात मजबूती से रखेंगे। सपा अध्यक्ष ने अपराध वृद्धि व बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक ओर कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है दूसरी ओर भाजपा सरकार की मनमानी कार्यशैली व दमनकारी नीतियों से जनता त्रस्त है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार उचित चिकित्सा के अभाव व लापरवाही के लिए जानी जाएगी। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कोरोना किट खरीदने में महाघोटाला हुआ है। रोजगार की मांग कर रहे नौजवानों पर लाठियां चलाकर सरकार अच्छा नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री रोजगार के झूठे आंकड़े पेश करके युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

● विरोधस्वरूप सपा आज सभी तहसील मुख्यालयों पर करेगी प्रदर्शन

बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के अंतरजनपदीय तबादलों पर लगी रोक हटी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पर 31,661 युवाओं की भर्ती के आदेश के एक दिन बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापकों तथा सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में अंतरजनपदीय तबादलों पर लगी रोक को हटा दिया है। इससे सूबे के करीब 54,120 शिक्षकों को लाभ मिलेगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को तबादलों को मंजूरी प्रदान की। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने से तबादलों की प्रक्रिया रुकी थी। बेसिक शिक्षा विभाग के 54,120 शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण को मंजूरी दी है। इसमें 25,814 पुरुष और 28,306 महिलाएं हैं। बीमारी से पीड़ित 2186, दिव्यांग 2285 और सैन्य सेवाओं से जुड़े 917 शिक्षकों ने तबादला के लिए अपना आवेदन किया था।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग में 4500 शिक्षकों का अंतर जिला का तबादला आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत विशेष लाभ महिला, दिव्यांग, बीमार व सैनिक परिवार के शिक्षकों को मिला है। इसमें भी पारदर्शिता के लिए प्रक्रिया पूरी तरह से आनलाइन की गई है। रविवार को पहले ही दिन 4500 शिक्षकों का तबादला आदेश जारी किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में अंतर जनपदीय तबादला के लिए ऑनलाइन 45000 से अधिक आवेदन आये थे। प्रदेश में कोविड.19 के संक्रमण के कारण इनकी तबादला प्रक्रिया रुकी हुई थी। अब प्रदेश में शिक्षक एक जिले से दूसरे जिला में तबादले पर जा सकेंगे।

प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में तबादले के इच्छुक प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक काफी समय से सरकार से अंतरजनपदीय तबादलों को खोले जाने की उम्मीद लगाये थे।

अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया तेज, सीएम अगले हफ्ते बांटेंगे नियुक्ति पत्र

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ निर्देशों के बाद राज्य में 31, 661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक हफ्ते में ही इनमें से कुछ को अपने हाथ से नियुक्ति पत्र देंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश मे 31661 पद पर सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को गति प्रदान कर दी है। यह 31661 पद 69000 सहायक शित्रकों के पद में से हैं, जिनकी नियुक्ति करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 69000 में से 31,661 शिक्षकों की भर्ती का निर्देश करीब चार महीने पहले दिया था। इसके बाद कोरोना वायरस संक्रमण के कारण चार महीने बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के रोजगार को लेकर पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। इसको लेकर हमारी तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

आज से नहीं खुलेंगे निजी स्कूल जारी रहेंगी ऑनलाइन क्लास

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली सरकार द्वारा 21 सितम्बर से स्कूल न खोलने के निर्णय को देखते हुए राजधानी के निजी स्कूल संचालक सोमवार से स्कूल खोलने के मूड में नहीं हैं। उनका कहना है कि बच्चों व स्टाफ के जीवन के साथ सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई बढ़िया चल रही है। ऐसे में वह कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं।

उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत 21 सितंबर से स्कूल खोलने की छूट दी गई है। कई राज्यों में इसे हरी झंडी भी दी जा चुकी है। इसके बावजूद लखनऊ समेत प्रदेशभर के स्कूल संचालक विद्यालय खोलने को तैयार नहीं हैं। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि व्यवस्थित प्लानिंग के बाद ही स्कूल खोले जाना उचित होगा। वहीं

● अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा जल्द ही उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के समक्ष इसको लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे

एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल का कहना है कि स्कूल खोलने के संबंध में जल्द ही उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। इस माह में कोरोना की स्थिति का आकलन कर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह स्कूल खोलने की तैयारी का प्रस्ताव है। अगर हालात सुधरते हैं तो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह से स्कूल खोल दिए जाएंगे। वहीं राजकीय व एडेड स्कूलों ने भी अपना मत स्पष्ट कर दिया है। इन स्कूलों का कहना है कि जब तक सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश नहीं मिल जाते हैं, तब तक बच्चों के लिए स्कूल खोलने पर कोई विचार नहीं है।

उत्तराखंड विस अध्यक्ष भी कोरोना संक्रमित

● 23 को केवल एक दिन का होगा सत्र

भाषा। देहरादून

उत्तराखंड विधानसभा के 23 सितंबर से होने वाले मानसून सत्र के ठीक पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश सहित कुछ अन्य विधायकों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने की वजह से सत्र को एक दिन के लिए सीमित करने का निर्णय रविवार को लिया गया। सत्र से पहले होने वाली सर्वदलीय बैठक और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि सदन एक ही दिन चलेगा और उसमें प्रश्नकाल नहीं होगा। कार्यस्थगन में जनहित के मुद्दों को उठाया जाएगा। पहले तीन दिन का सत्र प्रस्तावित किया गया था।

बैठक की अध्यक्षता करने वाले विधानसभा के उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने बताया कि कोरोना काल की विकट परिस्थितियों के मद्देनजर सभी सदस्यों ने इस बात पर सहमति जताई कि सदन की कार्यवाही एक दिन ही चलाई जाए।

उन्होंने बताया कि सदन में प्रश्नकाल न रखे जाने तथा कार्यस्थगन प्रस्तावों के जरिए जनहित के मुद्दे उठाने पर भी सहमति बनी। चौहान ने बताया कि सत्र के दौरान कार्यवाही विधानसभा में ही होगी और मंडप के अलावा दर्शक और प्रेस दीर्घाओं में भी विधायकों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा में एक मनोनीत विधायक सहित कुल 71 सदस्य हैं।

उत्तराखंड में 878 और लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि, 13 की मौत

देहरादून (भाषा)। उत्तराखंड में रविवार को कोरोना वायरस से 878 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई जिन्हें मिलकार राज्य में इस महामारी की चपेट में आने वाले कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 40,963 हो गई है। इसके अलावा इस अवधि में 13 और मरीजों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। यहां प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, रविवार को सबसे अधिक 408 नए मामले देहरादून जिले में सामने आए हैं जबकि हरिद्वार में 176, पौडी गढ़वाल में 55 और टिहरी और नैनीताल में 48-48 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। बुलेटिन के मुताबिक रविवार को कोरोना वायरस के संक्रमण ने प्रदेश में 13 और मरीजों की जान ले ली। एम्स ऋषिकेश और हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में छह-छह मरीजों की मौत हुई जबकि एक अन्य ने दून मेडिकल कालेज में दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक कुल 27,828 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और उपचाराधीन मामलों की संख्या 12,455 है।

एनईपी लागू कर जम्मू व कश्मीर को ज्ञान एवं नवोन्मेष का केंद्र बनाएं : कोविंद

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को कहा कि नई शिक्षा नीति (एनईपी) को अक्षरश: लागू कर जम्मू कश्मीर को ज्ञान, नवोन्मेष और अध्ययन का केंद्र बनाने की प्रतिबद्ध कोशिश की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और नवोन्मेषी बच्चों की कमी नहीं है तथा नई शिक्षा नीति से प्रखर बुद्धि के साथ विद्यार्थी सामने आएंगे। कोविंद ने कहा, एनईएपी को अक्षरश: लागू कर जम्मू कश्मीर को ज्ञान, नवोन्मेष और अध्ययन का केंद्र बनाने की प्रतिबद्ध कोशिश की जानी चाहिए। ये कदम जम्मू-कश्मीर को एक बार फिर धरती का फिरदौस और मां भारती के ताज का जगमगाता रत्न बना देंगे जैसा कि मध्यकाल में इसका उल्लेख होता था। राष्ट्रपति ने यह टिप्पणी जम्मू-कश्मीर में एनईपी के क्रियान्वयन को लेकर हुए सम्मेलन के दौरान की। भारत के पास अद्वितीय जनसांख्यिकी लाभ है लेकिन इसका सकारात्मक इस्तेमाल तभी किया जा सकता है।

कोलकाता में दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए मां दुर्गा की मूर्तियां बनाती हुई एक महिला कलाकार

छह राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत नौ लाख से अधिक कार्य दिवस सृजित किए गए

नई दिल्ली। रेलवे ने 18 सितंबर तक बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 9,79,557 कार्य दिवस सृजित किए हैं। रेलवे ने रविवार को यह जानकारी दी। इन राज्यों में लगभग 164 रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं पर काम चल रहा है। रेलवे ने कहा कि 18 सितंबर तक 12,276 कर्मचारियों को इस योजना में लगाया जा चुका है और इन परियोजनाओं के लिए 2056.97 करोड़ रुपए का भुगतान ठेकेदारों को किया गया है। रेलवे ने प्रत्एक जिले के साथ-साथ राज्यों में भी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है ताकि राज्य सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित हो सके।

भारतीय रेलवे ने कई कार्यों की पहचान की है, जिन्हें इस योजना के तहत निष्पादित किया जा रहा है। समपार के लिए संपर्क मार्गों के निर्माण और रखरखाव, पटरी के पास जलमार्गों, खाइयों और नालों की सफाई, रेलवे स्टेशनों के लिए संपर्क मार्गों का निर्माण और रखरखाव, मौजूदा रेलवे बांधों या उपमार्गों की मरम्मत और चौड़ीकरण समेत अन्य कई तरह के कार्य इस योजना से जुड़े हुए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से बड़ी संख्या में प्रभावित हुए प्रवासी कामगारों को उनके क्षेत्रों और गांवों में आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए 20 जून, 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान नाम से बड़े पैमाने पर रोजगार-सह-ग्रामीण सार्वजनिक कार्य अभियान शुरू किया था। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि इस योजना के तहत मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

कोरोना संकट के समय बड़ी संख्या में पहुंचकर सांसदों ने सकारात्मक संदेश दिया: बिरला

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोरोना महामारी के दौरान सदन के सदस्यों की ओर से किए गए कार्यों की सराहना करते हुए रविवार को कहा कि इस संकट के समय भी सदन की बैठक में बड़ी संख्या में पहुंचकर सांसदों ने देश को सकारात्मक संदेश दिया है। उन्होंने सदन में नियम 193 के तहत कोविड-19 वैश्विक महामारी पर चर्चा की शुरुआत से पहले सांसदों से यह अपील भी की कि वे अपनी बात रखने के साथ रचनात्मक सुझाव दें। बिरला ने कहा, इस सदन ने देश को राह दिखाई है। स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े खतरे के बीच भी बड़ी संख्या में आकर आप सबने सकारात्मक संदेश दिया है। आज कोविड जैसे गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो यह चर्चा रचनात्मक और सकारात्मक हो। उन्होंने जोर दिश कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कैसे देशवासियों को इस संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं। सदस्य जो भी बातें करें तो उसमें सुझाव दें ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ने में मदद मिले। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान मैंने सभी सदस्यों से संपर्क किया। हर सदस्य ने गरीबों और समाज की मदद के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। आप लोग अपनी ओर से किए गए अच्छे प्रयासों को भी बताएं ताकि प्रेरणा मिले।

ड्रोनों से हथियारों का गिराया जाना नई चुनौती: बीएसएफ

● पाक मे आतंकवादी ढांचे जस के तस

जम्मू। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक शीर्ष अधिकारी ने रविवार को कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे यथावत बने हुए हैं तथा अब जम्मू कश्मीर में ड्रोनों के माध्यम से हथियारों को गिराया जाना एवं विभिन्न भारत विरोधी तत्वों का एकजुट होना एक नई चुनौती है। बल के महानिरीक्षक (जम्मू सीमा) एन एस जामवाल ने कहा कि सभी सुरक्षा एजेंसियां नई सुरक्षा चुनौतियों से वाकिफ हैं तथा वे दुश्मनों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए कड़ी चौकसी बरत रही हैं।

वह आर एस पुरा सेक्टर के अरनिया में दो पिस्तौल, तीन मैगजीन एवं 100 कारतूसों के साथ साथ करोड़ों रूपए मूल्य की हेरोईन बरामद किए जाने के बाद यहां संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। अधिकारी ने कहा, (पाकिस्तान में) आतंकवादी ढांचे जस के तस हैं जो हथियारों एवं मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गतिविधियों और सीमा पर गोलीबारी की घटनाओं में इजाफे से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि आकाश मार्ग से हथियारों को गिराने के लिए ड्रोनों के इस्तेमाल का नया खतरा उभरकर सामने आया है।

उन्होंने कहा, हम चौकस हैं और इससे निपटने का काम चल रहा है। जामवाल ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधि सर्वप्रथम पंजाब में और फिर जम्मू कश्मीर में भी नजर आई। उन्होंने कहा कि बीएसएफ इस खतरे के प्रति चौकस है और उसने पिछले कुछ महीनों में दो ऐसे प्रयास विफल किए हैं।

बीस जून को कठुआ जिले के रठुआ गांव में सीमा सुरक्षा बल ने एक हेक्सा कॉप्टर ड्रोन को मार गिराया था जिस पर अमेरिकी एम 4 अर्धस्वचालित कार्बाइन और सात ग्रेनेड समेत साढ़े पांच किलोग्राम सामान लदा था। पिछले सप्ताह राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के समीप लश्कर -ए-तैयबा के तीन आतंकवादियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था, ए हथियार आकाश मार्ग से गिराए गए थे।

जब जामवाल का ध्यान इन खबरों की ओर आकृष्ट किया गया कि आतंकवादी संगठन आपस में हाथ मिला रहे हैं तथा खालिस्तानी हैंडलर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलीजेंस की मदद से मादक पदार्थों की तस्करी करवा रहे हैं तो उन्होंने कहा, सभी भारत विरोधी तत्वों को जहां भी मौका मिलता है तो एकजुट हो जाते हैं। उन्होंने कहा, सुरक्षा एजेंसियां इससे वाकिफ हैं और इस चुनौती से निपटने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं।

क्विक न्यूज

केंद्रीय मंत्री बाल्यान ने मुजफ्फरनगर हत्याकांड में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया

मुजफ्फरनगर। केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान ने उस दवा दुकान के मालिक के परिवार से मुलाकात की जिसकी कुछ दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उन्हें मामले में व्यापक जांच का आश्वासन दिया। अनुज करनवाल के परिवार ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है और उन्होने अपना गांव छोड़ने की योजना बनाई थी। बाल्यान ने परिवार के सदस्यो से शनिवार को मुलाकात की थी और उन्हे मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। सत्रह सितंबर को मोरना गांव में कुछ हथियारबंद लोग करनवाल के घर में घुसे और उन्हें गोली मार दी। जख्मी हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरो ने उन्हे मृत घोषित कर दिया। इस बीच, वरिष्ठ अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि पुलिस ने तीन आरोपियों की पहचान की है और उन्हें गिरफ्तार किए जाने की कोशिश की जा रही है।

नगालैंड के लोकायुक्त ने उपमुख्यमंत्री के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज किया

कोहिमा। नगालैंड के लोकायुक्त न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह ने उपमुख्यमंत्री वाई पैटॉन के खिलाफ दर्ज कराई गई उस शिकायत को खारिज कर दिया है जिसमे छात्र संघ के एक पूर्व नेता ने आरोप लगाया था कि उपमुख्यमंत्री ने एनपीएससी परीक्षा के परिणामों को प्रभावित करने के लिए अधिकारों का दुरुपयोग किया है। न्यायमूर्ति सिंह ने अपने आदेश मे कहा कि आरोपो के संबंध मे पैटॉन के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई सबूत नही मिले है। लिहाजा इस मामले मे लोकायुक्त द्वारा आगे ध्यान दिए जाने की जरूरत नही है। आदेश मे कहा गया है कि शिकायत जल्दबाजी में दर्ज कराई गई और इसमे तथ्यो की कमी है। लिहाजा शिकायत खारिज की जाती है। लोकायुक्त का यह आदेश 18 सितंबर का है जिसे शनिवार रात पत्रकारों को उपलब्ध कराया गया। छात्र संघ के पूर्व नेता वी एस आए ने इस साल फरवरी में पैटॉन के खिलाफ लोकायुक्त मे शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया गया था कि पैटॉन ने नगालैड लोक सेवा आयोग (एनपीएससी) की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियो से साक्षात्कार चरण मे मदद के लिए उनसे संपर्क करने को कहा था।

ममता ने उत्तर बंगाल की यात्रा आठ दिनों के लिए स्थगित की

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल मे अपनी समीक्षा बैठकों को आठ दिनो के लिए स्थगित कर दिया है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनो मे राज्य के कई हिस्सो मे भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार यह जानकारी सामने आई है। बनर्जी 21 सितंबर को सिलीगुड़ी की यात्रा करने वाली थी, लेकिन अब उनकी यात्रा आठ दिन बाद 29 सितंबर को होगी। वह पांच उत्तरी जिलो की प्रशासनिक समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता करने वाली है, जो सिलीगुड़ी के शाखा सचिवालय उत्तरकन्या मे आयोजित की जाएंगी। अधिसूचना मे कहा गया है, अगले कुछ दिनो मे प. बंगाल मे मौसम के खराब होने के पूर्वानुमान के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री की उत्तर बंगाल के जिला में होने वाली समीक्षा बैठकें स्थगित की जा रही है, जो अब 29 और 30 सितंबर को होगी। मार्च मे कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से यह बनर्जी की उत्तरी जिलो की पहली यात्रा होगी। वह उस महीने के पहले सप्ताह के दौरान मालदा गई थी।

दूसरे देशों की तुलना में भारत में प्रति दस लाख की आबादी पर कोविड-19 से कम मौतें: सरकार

नई दिल्ली। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को बताया कि दूसरे देशो की तुलना मे भारत मे कोविड-19 से मौत के आंकड़े कम है। राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर मे चौबे ने बताया कि फिलहाल ऐसी कोई दवा या टीका नही है जो कोरोना वायरस के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ सके। उन्होने कहा कि फिलहाल लगातार हाथ धोते रहने, मास्क और फेस कवर पहनने, भीड़ वाली जगहो मे जाने से बचने और सुरक्षित दूरी रखने जैसे उपायो से ही कोरोना वायरस के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे है। चौबे ने कहा कि इसके साथ ही सामुदायिक जागरूकता पर भी जोर देना होगा। उन्होने कहा कोविड-19 अत्यंत संक्रामक रोग है। इससे जुड़े कई पहलुओं पर अनुसंधान जारी है।

सड़क हादसे में ईंट भट्ठे में काम करने वाले चार श्रमिकों की मौत

मुजफ्फरनगर (उप्र)। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले मे गंगोह तितरो मार्ग पर एक सड़क हादसे मे ईंट भट्ठे मे काम करने वाले चार श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 30 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। घटना शनिवार देर रात की है। घायलो को पास के अस्पताल मे भर्ती कराया गया है, जिनमे से कुछ की हालत नाजुक है। श्रमिक डीसीएम वाहन मे सवार होकर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के पीपलहेरा गांव से पंजाब जा रहे थे। सहारनपुर जिले मे एक ट्रक ने वाहन को टक्कर मार दी। दुर्घटना मे मरने वाले सभी लोग मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले है।

ठाणे (महाराष्ट्र) में मराठा क्रान्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा और रोजगार में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करते हुए किया प्रदर्शन

इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेन्स नेटवर्क रखेगा कोविड-19 की दवा पर नजर

नई दिल्ली। सरकार ने रविवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में देश भर में कोविड-19 की दवा की जरूरत, उसके भंडार, भंडारण तापमान एवं उपलब्धता आदि के बारे में इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेन्स नेटवर्क के जरिए नजर रखी जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेन्स नेटवर्क वास्तव में इंटरनेट आधारित एक डिजिटल प्रणाली है जो नियमित टीकाकरण, दवा के भंडार, भंडारण तापमान आदि को लेकर निगरानी करेगी। कोविड-19 के दवा पर विशेषज्ञों का एक राष्ट्रीय समूह बनाया गया है जो सरकार को दवा के लिए आबादी समूहों की प्राथमिकता, लोगों का चयन, दवा की आपूर्ति व्यवस्था तथा संबद्ध अवसंरचना के बारे में सरकार को परामर्श देगा। चौबे ने स्पष्ट किया कि सरकार ने इस संबंध में किसी भी विदेशी फर्मास्यूटिकल कंपनी के साथ कोई करार नहीं किया है।

बायोमेडिकल अपशिष्ट का निपटान बड़ी चुनौती: सरकार

नई दिल्ली। सरकार ने रविवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के इस दौर में पीपीई किट सहित बायोमेडिकल अपशिष्ट का निपटान एक बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया है कि स्वास्थ्य पेशेवरों और आम लोगों द्वारा पहने जाने वाले पीपीई किट सहित बायोमेडिकल अपशिष्ट का निपटान कोविड-19 के दौरान बड़ी चुनौती बन गया है। कचरा संग्रह एवं उसका निपटान करने वालों में कोविड-19 के संक्रमण के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है।

बिहार चुनाव में बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र को कारोबारी घरानों को सौंपने जैसे मुद्दे होंगे: तेजस्वी

भाषा। नई दिल्ली

विधानसभा चुनाव के पहले बिहार के लिए केंद्र द्वारा कई विकास परियोजनाओं की घोषणा किए जाने के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि दिखावटी प्रचार कवायद शासन के लिए खराब विकल्प है और चुनाव में बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र को कारोबारी घरानों के हाथ में सौंपने, कोविड-19 महामारी से निपटने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता यादव ने कहा कि यह निर्विवाद और सिद्ध है कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) महागठबंधन का स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता है और जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा।तीन कृषि विधेयकों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए यादव ने कहा कि राजद ने हमेशा किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और कृषि क्षेत्र को कारोबारी घरानों के हाथ में सौंपने के खिलाफ पूरी ताकत से पार्टी लड़ेगी। उन्होंने कहा, इन विधेयकों से किसानों का वित्तीय सुरक्षा कवच खत्म हो जाएगा जो कि उन्हें सरकारी खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जैसे प्रावधानों से मिल रहा था। अगर विधेयक किसान विरोधी नहीं हैं तो एक केंद्रीय मंत्री ने क्यों इस्तीफा दे दिया। कृषि विधेयक के मुद्दे पर शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।

यादव ने जोर दिया कि उनकी पार्टी लोगों के मुद्दों के आधार पर बिहार चुनाव में लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं, लोकतंत्र और संविधान समर्थक ताकतों के विरूद्ध निरंकुश, विभाजनकारी और संविधान विरोधी शासन की लड़ाई होगी। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा, बिहार चंपारण सत्याग्रह जैसे राजनीतिक आंदोलन की भूमि है और मैं आश्वस्त हूं कि यह चुनाव मौजूदा राजनीतिक विमर्श में ऐतिहासिक क्षण होगा। क्या बिहार चुनाव में सुशांत सिंह राजपूत मामला भी चुनावी मुद्दा होगा, यह पूछे जाने पर यादव ने कहा, सुशांत की मौत के मामले में सबसे पहले हमने सीबीआई जांच की मांग की थी और

अब जांच शुरू हो गई है तो हमारा इसमें भरोसा है और परिणाम का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा, हमने कभी इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया और ना ही इसे बनाना चाहिए। बिहार में बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र को कारोबारी घरानों को सौंपने, बेलगाम भ्रष्टाचार, बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं, कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति, शिक्षा, निरंकुश नौकरशाही जैसे बड़े मुद्दे हैं।

यादव ने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने और प्रवासी मजदूरों से किया गया बर्ताव भी महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। यादव ने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 15 साल के कार्यकाल में इन सभी मोर्चे पर बुरी तरह नाकाम रहे हैं। राजद सुनिश्चित करेगा कि बिहारी लोगों की जिंदगी और भविष्य से संबंधित असली मुद्दों को उठाया जाए। क्या वह विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और महागठबंधन में राजद की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर यादव ने कहा कि यह निर्विवाद और सिद्ध है कि महागठबंधन में राजद स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता है और अब भी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा, मेरे पास जो भी जिम्मेदारी है, मैं ईमानदारी से उसे निभा रहा हूं और भविष्य में भी ऐसा ही करूंगा। फिलहाल मैं बिहार में सबसे भ्रष्ट और जन विरोधी सरकार को हटाने के लिए अथक प्रयास कर रहा हूं।

यादव ने जोर दिया कि देश और बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है जिसका समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा, लंबे समय से 4.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं और मैंने बिहार के युवाओं को आश्वस्त किया है कि हमारी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इन रिक्तियों को भरने का काम शुरू होगा और निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति को भी लागू किया जाएगा। केंद्र द्वारा बिहार के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरूआत करने के बारे में पूछे जाने पर यादव ने आरोप लगाया कि ऐन चुनाव के पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए परियोजनाओं की घोषणा करना मुख्यमंत्री कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजमाया हुआ तरीका है। राजद नेता ने कहा कि बिहार जानना चाहता है कि 1.65 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का क्या हुआ, जिसकी घोषणा मोदी ने 2015 के प्रचार अभियान के दौरान की थी। बिहारी जानते हैं कि बढ-चढ़कर किए गए दावों का क्या हुआ। बिहार को विशेष दर्जा के वादों का क्या हुआ।

यादव ने कहा, दिखावटी प्रचार कवायद शासन के लिए खराब विकल्प है। नीतीश जी बिहार से दोबारा छल नहीं कर सकते।

रांची में विभिन्न जनजाति के लोग राज्य सरकार से एक समानता का कानून लागू करने की मांग करते हुए।

भारी बारिश से कर्नाटक के कई हिस्सों में तबाही

● उडुपी सबसे ज्यादा प्रभावित

भाषा। बेंगलुरु

कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश की वजह से काफी तबाही हुई है। खास तौर पर तटीय उडुपी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है जहां घर तथा फसलें पानी में डूब गई हैं, जिसके बाद सरकार ने रविवार को आपदा मोचन बल के कर्मियों को बचाव कार्य में लगाया है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र (केएसएनडीएमसी) के अधिकारियों ने बताया कि मलनाड, तटीय क्षेत्र और कुछ आंतरिक और उत्तरी जिलों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किए गए हैं। कर्नाटक में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दूसरी लहर राज्य से टकराई है जबकि कोविड-19 महामारी के बीच उत्तरी कर्नाटक में आई बाढ़ से राज्य अब तक ठीक से उबरा भी नहीं था। केएसएनडीएमसी ने रविवार को बताया कि उडुपी में स्थिति गंभीर है क्योंकि कुछ गांव पानी में डूब चुके हैं, घर गिर गए हैं, सड़कें बह गई हैं और खेतों में लगी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उडुपी में जिला मुख्यालय नगर में भी कई घर, चार-पहिया वाहन और सड़कें पानी की चपेट में आई हैं। राज्य गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने रविवार को कहा कि उन्होंने उडुपी जिला प्रशासन को तत्काल राहत कदम उठाने का निर्देश दिया है। मंत्री ने कहा कि वह राजस्व मंत्री आर अशोक से बचाव कार्य में वायु सेना का एक हेलीकॉप्टर लगाने का आग्रह करेंगे। वहीं कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिकारी के अनुसार बचाव कार्य के लिए वहां एक हेलीकॉप्टर को तैयार रखा गया है।

कोच्चि के इडाथला में रविवार को भारी बारिश के बाद सड़क पर लटका हुआ एक बिजली का खंभा

फीस न भरने पर स्कूल ने काटा झारखंड के शिक्षा मंत्री का नातिन का नाम

बोकारो/रांची। झारखंड के बोकारो स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल ने समय पर फीस न भरने पर राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की नातिन का नाम काट दिया। मंत्री स्वयं फीस जमा करने स्कूल पहुंचे तब कहीं जाकर उनकी नातिन का नाम स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में वापस लिखा गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नाम कटने की जानकारी मिलने पर वह शनिवार को बोकारो के चास स्थित डीपीएस स्कूल पहुँचे और नियमों के अनुसार अपनी नातिन की फीस जमा की। महतो ने कहा कि उन्होंने फीस जमा की और निजी विद्यालयों की स्थिति का जायजा लिया। वहीं, इस घटना पर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने तंज करते हुए कहा कि निजी स्कूलों की मनमानी का आलम सरकार को आईना दिखाने के लिए पर्याप्त है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने कहा कि चास के दिल्ली पब्लिक स्कूल की घटना तो बस एक उदाहरण मात्र है। चूंकि यह मामला सूबे के शिक्षा मंत्री के घर से संबंधित था, इसलिए मंत्री आनन-फानन में स्कूल पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हर दिन राज्य के सैकड़ों-हजारों अभिभावक निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान हैं, लेकिन प्रदेश का शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार इन स्कूलों के सामने असहाय हैं।

पिछले 10 वर्ष में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान 631 लोगों की मौत

भाषा। नई दिल्ली

देश में पिछले 10 वर्षों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान 631 लोगों की जान गई है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) ने सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान 2010 से मार्च 2020 के बीच हुई मौतों के संबंध में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना के जवाब में यह जानकारी दी है। आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में 631 लोगों की मौत हुई। इनमें से सबसे ज्यादा 115 लोगों की मौत 2019 में हुई।

वहीं, पिछले 10 वर्षों में इस वजह से सबसे ज्यादा 122 लोगों की मौत तमिलनाडु में हुई। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 85, दिल्ली और कर्नाटक में 63-63 तथा गुजरात में 61 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में 50 लोगों की मौत हुई। इस साल 31 मार्च तक सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान दो लोगों की मौत हुई है। 2018 में इस वजह से 73 तो 2017 में 93 लोगों की मौत हुई। आंकड़ों के अनुसार 2016 में 55 लोगों की मौत हुई जबकि 2015 में 62 और 2014 में 52 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 2013 में 68 तथा 2012 में 47 और 2011 में 37 लोगों की मौत हुई। 2010 में 27 लोगों की मौत हुई थी। एनसीएसके ने बताया कि आंकड़े विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर है और वास्तविक आंकड़े अलग हो सकते हैं। आरटीआई आवेदन के तहत दी गई जानकारी में कहा गया कि अद्यतन होने पर ये आंकड़े बदलते रहते हैं।

इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा कि सफाई राज्यों का विषय है और एनसीएसके के पास राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से मिला आंकड़ा होता है। हालांकि सफाईकर्मियों के अधिकारों के लिए काम करनेवाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि मैला ढोना रोजगार निषेध व पुनर्वास अधिनियम को सही से लागू नहीं करने की वजह से इससे जुड़ी मौतें हो रही हैं। मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने की दिशा में काम करनेवाले संगठन सफाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक बेजवाड़ा विल्सन ने कहा कि कानून सही तरीके से लागू नहीं होने से सफाई कर्मी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। मैगसायसाय पुरस्कार से सम्मानित कार्यकर्ता ने कहा, मैला ढोना रोजगार निषेध व पुनर्वास अधिनियम के तहत किसी एक भी व्यक्ति को अब तक सजा नहीं मिली है। अधिनियम चुनावी घोषणा पत्र के वादों की तरह झूठे वादे नहीं होने चाहिए। दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच के सचिव संजीव कुमार का कहना है कि कानून का क्रियान्वयन सबसे बड़ी चुनौती है।

उन्होंने कहा कि सीवर या सेप्टिक टैंक के भीतर किसी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए और इस काम में मशीन को लगाया जाना चाहिए। वैसे भी मामले सामने आए हैं जब इन टैंकों के भीतर जहरीली गैस के सांस में जाने से सफाई कर्मचारियों को बाद में तकलीफों का सामना करना पड़ा है और वे अपनी ऊर्जा जुटाने में बाद में सक्षम नहीं हो पाते। जो लोग जिंदा बचते हैं, उन्हें काफी दर्द में जीवन गुजारना पड़ता है। कुमार ने कहा कि ज्यादातर मामलों में उन्हें न तो उचित प्रशिक्षण मिला होता है और न ही उनके पास उचित उपकरण होते हैं।

सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय द्वारा फरवरी में संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 17 राज्यों में मैला ढोनेवाले 63,246 लोगों की पहचान की गई है जिनमें से 35,308 उत्तर प्रदेश में हैं। छह दिसंबर, 2013 को रोजगार के रूप में मैला ढोने पर रोक एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 प्रभाव में आया था। यह अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि बिना रक्षात्मक उपकरणों के सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई खतरनाक सफाई की श्रेणी में है और इसमें दंडात्मक कार्वाई हो सकती है।

पांच राज्यों में कोविड-19 के 60 फीसदी सक्रिय मामले

● 52 प्रतिशत नए मामले

भाषा। नई दिल्ली

देश में बीते 24 घंटे में 94,612 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हुए हैं। संक्रमण से उबरने वाले मरीजों की संख्या 43,03,043 हो गई है और ठीक होने की दर 79.68 फीसदी पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि संक्रमण से ठीक हुए नए मरीजों में से 60 फीसदी पांच राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु से हैं। वहीं 52 प्रतिशत नए मामले में भी इन्हीं पांच राज्यों से हैं।

मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 23,000 मरीज महाराष्ट्र में ठीक हुए हैं, जबकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 10-10 हजार मरीज संक्रमण से उबरे हैं। उसने बताया कि लगातार दूसरे दिन 94,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। बीते 24 घंटे में 92,605 मामले सामने आए हैं। इसके बाद पुष्ट मामलों की संख्या 54,00,619 हो गए हैं। नए मामलों में महाराष्ट्र के 20,000 से ज्यादा (22.16 प्रतिशत) मरीज हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में आठ-आठ से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के कारण 1,113 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद मृतक संख्या 86,752 पहुंच गई है।

शाह ने असम से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर की बैठक, सोनोवाल ने की शिरकत

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर रविवार को चर्चा की। इसके तहत एनआरसी, छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग और असम समझौते की महत्वपूर्ण उपधारा के कार्यान्वयन के लिए गठित समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों की टीम ने शाह के आवास पर हुई बैठक में शिरकत की। यह बैठक करीब दो घंटे चली। एम्स से लौटने के बाद गृह मंत्री ने यह पहली बड़ी बैठक की। शाह चिकित्सकीय जांच के लिए एम्स में भर्ती हुए थे। रविवार शाम को हुई बैठक में असम-केन्द्रित एनआरसी, छह जातीय समुदायों कोच-राजबोंगशी, ताइ-अहोम, मताक, मरोन, चुटिया तथा चाय बागानों से संबंधित जनजातियों को अनूसूचित जनजाति का दर्जा देने और असम समझौते की छठी उपधारा को लागू करने को लेकर समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की गई।

महामारी के लिए तैयारी नहीं थी: कांग्रेस

● विपक्षी दल ने कोविड-19 को लेकर सरकार पर साधा निशाना

भाषा। नई दिल्ली

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कोरोना वायरस संकट से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि इस महामारी को लेकर सरकार के स्तर पर कोई तैयारी नहीं थी और सिर्फ कुप्रबंधन देखने को मिला। लोकसभा में नियम 193 के तहत कोविड-19 वैश्विक महामारी पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यह भी कहा कि सरकार को कोरोना वायरस की जांच और इससे निपटने के उपायों को लेकर अधिक पारदर्शिता का परिचय देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया, इस बीमारी के कारण सरकार के लिए एक अच्छी बात हो गई कि उसे मुंह छिपाने का बहाना मिल गया। तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य ने आरोप लगाया कि देश में रोजाना सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं और सबसे अधिक मौतें हो रही हैं। यह चिंता का विषय है। सरकार की तरफ से कुप्रबंधन देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में निवार्चित सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। हमने देखा कि सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले कदमों के संदर्भ में स्पष्टता और तैयारियों की कमी देखने को मिली। थरूर ने कहा कि जनवरी में यह संकेत मिल गया था कि यह वायरस खतरनाक है। जनवरी महीने में भारत पहला मामला आया। इसके बाद राहुल गांधी ने सरकार को आगाह किया था कि कोरोना वायरस संकट खतरनाक है और सरकार को समय रहते कदम उठाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी की चेतावनी को सुन लिया गया होता तो स्थिति कुछ और होती। लेकिन यह सरकार मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में लगी थी। सरकार ने इस समस्या को नजरअंदाज किया। कांग्रेस सांसद के अनुसार, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देश को विश्वास में ले, न कि लोगों को अंधेरे में रखे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ 21 दिनों में लड़ाई जीती जाएगी। लेकिन पिछले छह महीने से स्थिति खराब होती है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, हम यह नहीं कहते थे कि महामारी नहीं थी, हम यह बता रहे हैं कि तैयारी नहीं थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि कोरोना संकट के खिलाफ सरकार के प्रयास गुमराह करने वाले थे और वे विफल रहे। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिना तैयारी के लॉकडाउन लगाकर कारोबारी गतिविधियों को रोक दिया गया। अर्थव्यवस्था पहले से खराब स्थिति में थी जो और खराब हो गई। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी 24 फीसदी गिर गई। उन्होंने दावा किया कि 2.1 करोड़ वेतनभोगी लोगों ने अप्रैल-जुलाई के दौरान अपनी नौकरी गंवा दी। थरूर ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से कई रचनात्मक सुझाव दिए गए थे, लेकिन सरकार ने इन पर अमल नहीं किया। इन सुझावों में लोगों के खातों में पैसे डाले जाने का सुझाव प्रमुख था, लेकिन इसको भी क्रियान्वित नहीं किया गया।

सांसद का आंध्रप्रदेश में हिंदू मंदिरों में नियमों में बदलाव का आरोप

नई दिल्ली। लोकसभा में वाईएसआर कांग्रेस के असंतुष्ट सदस्य के रघुराम कृष्ण राजू ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिरों को लेकर नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं और उन्होंने इस विषय पर ध्यान देने के लिए एक धार्मिक आयोग के गठन की मांग की। राजू ने शनिवार को शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में इस समय हिंदू मंदिरों के संबंध में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस विषय को देखने के लिए ईसाई आयोग या मुस्लिम आयोग की तरह एक धार्मिक आयोग या हिंदू आयोग होना चाहिए। राजू ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि केवल एक कर्मयोगी ही इस मुद्दे को देख सकते हैं। उन्होंने कहा, अन्यथा हमारे राज्य में अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन हमें अल्पसंख्यक की तरह देखा जा रहा है। राजू ने आरोप लगाया कि तिरुपति के पास तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर में सदियों पुराने नियमों को केवल एक व्यक्ति के लिए बदलने का प्रयास किया जा रहा है। समझा जाता है कि उनका परोक्ष इशारा तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष वाई वी सुब्बा रेड्डी के बयान की ओर था कि मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी को मंदिर के दौरे के समय भगवान वेंकटेश्वर में आस्था जताते हुए अनिवार्य घोषणापत्र पर दस्तखत करने की जरूरत नहीं है। नियम के अनुसार मंदिर दौरे पर आए किसी गैर-हिंदू को घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं।

एलओसी के पास के गांवों में सात दशक से बिजली का इंतजार हुआ खत्म

कुपवाड़ा (जम्मू कश्मीर)। नियंत्रण रेखा (एलओसी) से लगे सुदूर उत्तर कश्मीर में केरन और माछिल सेक्टर के तीन गांवों को राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जोड़ दिया गया है। इस तरह, इन इलाकों में रहने वाले लोगों का सात दशक लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। बिजली आपूर्ति शुरू होते ही ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। साथ ही, कुपवाड़ा के उपायुक्त अंशुल गर्ग के चेहरे पर भी खुशी झलक रही थी, जिन्होंने इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। गर्ग ने कहा कि जब मैंने देश के इस सबसे उत्तरी जिले के उपायुक्त का पद संभाला, मैंने दूर-दूराज के इलाकों में रहने वाले आम लोगों से बातचीत करनी शुरू की, खासकर नियंत्रण रेखा के पास बसे गांवों के लोगों के साथ बातचीत की। फरवरी 2019 में उपायुक्त पदभार संभालने वाले गर्ग ने अपने शुरुआती दिनों में ग्रामीणों के साथ हुई बैठकों को याद करते हुए कहा, क्या हमें बिजली मिल सकती है सर? यह सवाल केरन और माछिल क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल ने किया और इस सवाल ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। देश को स्वतंत्रता मिलने के सात दशक बाद, ए लोग मुझसे बिजली की सुविधा को लेकर सवाल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिजली उपलब्ध कराने से संबंधित फाइलों को निकाला गया और इस पर बेहद तेजी से काम शुरू किया गया। गर्ग ने कहा, सरकारी विभाग फाइलों को एक से दूसरी जगह भेज रहे थे। तब मैंने खुद से यह वादा किया कि इन गांवों को किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड से जोड़ कर रहूंगा। उन्होंने कहा कि महीनों तक जमी रहने वाली बर्फ, अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के बाद श्रमिकों की कमी और कोविड-19 महामारी के हालात के बावजूद जिला प्रशासन ने एलओसी के करीब स्थित केरन और माछिल सेक्टर के तीन गांवों को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने में सफलता प्राप्त की, जिसके बाद इन ग्रामीणों का सात दशक लंबा इंतजार समाप्त हुआ।

उत्तर कश्मीर में कुपवाड़ा में रविवार को नियंत्रण रेखा के पास इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सात दशक बाद राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जुड़ने का लंबा इंतजार समाप्त होने पर स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते हुए उपायुक्त अंशुल गर्ग

पेज एक का शेष

रास में...

पारित होने के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य विरोध में धरने पर बैठ गए और सदन के दिन भर के लिए स्थगित होने के बावजूद वे जमे रहे। सदन की बैठक अपराह्न 1 बजे समाप्त हुई तथा राज्यसभा चेंबर को 3 बजे सेनेटाइज किया गया जब लोकसभा सत्र के लिए बैठती है। लोकसभा और राज्यसभा के दोनों चेबरों को प्रत्येक सदन इस्तेमाल करता है जिससे कि सदस्य सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। परिणामस्वरूप लोकसभा को 4 बजे तक स्थगित करना पड़ा क्योंकि कांग्रेस के सदस्यों की मांग थी कि जब तक धरनारत ऊपरी सदन के सदस्यों को राज्यसभा की गैलरी से नहीं हटाया जाता तब तक सदन की कार्यवाही नहीं हो सकती। विधेयकों के पारित होने के तुरंत बाद शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से इसको मंजूरी न देने तथा इसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेजने का आग्रह किया। इससे पहले बादल की पार्टी ने विधेयकों के विरोध में हरसिमरत कौर को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवा दिया था। तीन क्षेत्रीय पार्टियां-सबसे पुराने सहयोगी पंजाब का शिरोमणि अकाली दल (शिअद) तथा ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजद और तेलंगाना की टीआरएस जिन पर अपने महत्वपूर्ण बिलों पर समर्थन के लिए भाजपा भरोसा करती थी, ने इन विधेयकों का विरोध किया। ऊपरी सदन में इन तीनों पार्टियों के 19 सांसद हैं। अन्य दलों ने विधेयकों के खिलाफ अपनी पार्टियों का रुख साफ कर दिया था। इनमें कांग्रेस भी शामिल थी, जिसके 40 सांसद हैं। इसके अलावा ऊपरी सदन में सपा के 8, टीएमसी के 13, द्रमुक के 7, आप के 3, एनसीपी के 4, राजद के 5 तथा भाकपा और माकपा दोनों के 6 सांसद शामिल थे। पार्टी जिन्होंने बिल का स्पष्ट रूप से समर्थन किया, उनमें भाजपा (86), वाईएसआर कांग्रेस (6), अन्नाद्रमुक (9) तथा बीपीएफ (1) शामिल थे। शिवसेना और बसपा के नेताओं ने कुछ एतराज जताया लेकिन उन्होंने विधेयकों को योग्य भी पाया। शिअद के विपरीत मोदी के एक और सहयोगी दल जदयू ने विधेयकों का समर्थन किया। राज्यसभा में उसके सदस्य रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि काफी समय बाद पहली बार कि एक किसान नीति आई है। उन्होंने कहा कि 1991 में जब देश में उदारवाद आया था तो उस समय कृषि सुधार नीति नहीं आई थी। राजग के सबसे पुराने सहयोगी शिअद ने कहा कि केंद्र से तब तक बातचीत नहीं होगी जब तक कि कृषि विधेयकों को वापस नहीं लिया जाएगा। राजग की सहयोगी अन्नाद्रमुक ने बिलों का विरोध करते हुए कहा कि यह कारपोरेट घरानों के पक्ष में है। आप ने भी इसका विरोध किया। इसी तरह टीआरएस ने आरोप लगाया कि इन विधेयकों से देश के किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पार्टी ने बिल का समर्थन करने का ऐलान किया था। वाईएसआरसीपी सांसद विजयसाई रेड्डी ने कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि कृषि संबंधी विधेयकों के विरोध का कोई कारण नहीं है।

किसानों को...

है, क्योंकि इससे मेहनतकश किसानों को मदद मिलेगी।' इस बीच, राज्यसभा में कृषि संबंधी दो विधेयकों को पारित किये जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों के 'अमर्यादित आचरण' को लेकर केंद्र सरकार के वरिष्ठ नेताओं ने रविवार को उनकी आलोचना करते हुए इसे 'शर्मनाक' और संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व करार दिया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, प्रह्लाद जोशी, पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत और मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षी सदस्यों पर निशाना साधने के लिये यहां एक संवाददाता सम्मेलन किया। सिंह ने कहा कि स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे आचरण की उम्मीद नहीं की जाती। सिंह ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने नियम पुस्तिका फाड़ दी, आसन पर मौजूद राज्य सभा के उप सभापति हरिवंश की डेस्क पर कागज फेंके और आधिकारियों की टेबल पर चढ़ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। हरिवंश की मूल्यों में आस्था रखने वाले व्यक्ति के तौर पर प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों का उनके प्रति 'दुर्व्यवहार' अभूतपूर्व था। उन्होंने पूछा, अगर विपक्ष सहमत नहीं भी था तो क्या यह उन्हें 'हिंसक' होने, आसन पर हमला करने की अनुमति देता है? कृषि विधेयक के विरोध में भाजपा के सहयोगी शिरोमणि अकाली दल द्वारा मोदी सरकार छोड़ने के फैसले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कुछ फैसलों के पीछे 'राजनीतिक कारण' होते हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और एपीएमसी जारी रहेंगे। यह किसी भी कीमत पर कभी नहीं हटाए जाएंगे।'

कांग्रेस में...

हुई हैं। हालांकि, निर्वाचन आयोग ने अभी इन सीटों पर उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है लेकिन सिंधिया एपिसोड के चलते सत्ता गंवाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और इस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने जीत के लक्ष्य के साथ युद्धस्तर पर प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। दो दिन पहले उनके रोड शो में उमड़ी जबर्दस्त भीड़ से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद हो गया है और, कमलनाथ का यह विश्वास और पुख्ता हुआ है कि वे 28 में से कांग्रेस के पास रहीं 27 सीटों पर फिर कब्जा जमाने में कामयाब होंगे। जिताऊ रणनीति के तहत ही सिंधिया जो विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद अब भाजपा के टिकट पर राज्यसभा सांसद हैं, के प्रभाव वाले इलाके में पार्टी के प्रचार के लिए पायलट को चुना गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने राजस्थान के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट से खासकर ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने का अनुरोध किया। पायलट ने इसके लिए तुरंत अपनी सहमति भी दे दी है। गुप्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान पड़ोसी राज्य हैं इसलिए पायलट राजस्थान के साथ-साथ यहां की राजनीति से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं। पायलट ने नवंबर 2015 में रतलाम-झाबुआ लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के लिए प्रचार किया था। तब भूरिया ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। प्रवक्ता के मुताबिक, सचिन पायलट गुज्जर समुदाय से हैं जिन्हें मध्य प्रदेश में गुर्जर कहा जाता है। जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 16 सीटें ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में हैं। इन सोलह सीटों पर गुर्जर मतदाताओं की भारी संख्या है जो हार-जीत में निर्णायकबनते हैं। जाहिर है कि इस क्षेत्र में पायलट के चुनाव प्रचार करने से कांग्रेस को गुर्जर समुदाय के वोटरों को अपने पाले में खींचने में मदद मिलेगी। मार्च में सिंधिया समर्थक 22 विधायकों और अन्य तीन ने कांग्रेस छोड़ दी थी और भाजपा में शामिल हो गए थे। उनकी बगावत से कमलनाथ नीत कांग्रेस सरकार गिर गई थी और शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में फिर भाजपा की सरकार बनी थी। सिंधिया समर्थक 22 में से अधिकांश पूर्व कांग्रेसी विधायक शिवराज सरकार में मंत्री हैं।

कृषि विधेयकों...

राजमार्गों सहित अन्य सड़कों पर किसानों ने जाम लगा दिया। पंजाब में भी कई जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए गए। कृषि बिलों के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने काले गुब्बारे भी छोड़े। अंबाला के रास्ते हरियाणा में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान पंजाब के कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा रोके जाने पर ट्रैक्टर में आग लगाने का प्रयास किया और बैरिकेड तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ा। कांग्रेस कार्यकर्ता चंडीगढ़-दिल्ली राजमार्ग के जरिए दिल्ली जा रहे थे। किसानों ने नारायण गढ़ के पास अंबाला-नाहन राष्ट्रीय राजमार्ग, जींद-पटियाला और जींद-दिल्ली सड़कों पर जुलाना में और सोनीपत-गोहाना राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर भी यातायात बुरी तरह बाधित हो गया, लेकिन अंबाला-दिल्ली रोड पर कोई नाकाबंदी नहीं थी। पंचकूला में पंचकूला-बरवाला-नाहन राष्ट्रीय राजमार्ग को किसानों ने तीन घंटे तक बाधित रखा और राष्ट्रीय राजमार्ग-9 (दिल्ली-हिसार) रोहतक में मेहम के पास जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारी अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर रैलियों में आगे बढ़ रहे थे और कृषि बिलों व मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मोहाली, लुधियाना, फिरोजपुर, नवाशहर, संगरूर और बरनाला में भी ट्रैक्टर रैली निकाली गई। अंबाला में मुलाना से कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी और मेहम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कृषि बिलों को कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने वाला बताया। हिसार, कैथल, सिरसा, करनाल, जींद, जुलाना, चरखी दादरी, कनीना आदि में भी किसानों ने सड़कें जाम कर दीं।

एफसीआरए कानून...

लिए संशोधन किया जाना जरूरी है। मसौदा विधेयक में कहा गया है कि एफसीआरए के तहत पूर्व अनुमति या पंजीकरण अथवा एफसीआरए के लाइसेंस नवीकरण का अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को अब अपने सभी पदाधिकारियों या निदेशकों के आधार नंबर देने होंगे, विदेशी नागरिक होने की स्थिति में पासपोर्ट की एक प्रति या ओसीआई कार्ड की प्रति देना जरूरी होगा। इसमें लोक सेवक और सरकार या इसके नियंत्रण वाले निगम को ऐसी इकाइयों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है, जो विदेशी अनुदान हासिल करने के योग्य नहीं होंगे। एफसीआरए के तहत पंजीकृत एनजीओ को 2016-17 और 2018-19 के बीच 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी कोष मिला। देश में करीब 22,400 एनजीओ हैं।

क्रिस्टल पैलेस ने मैनचेस्टर यूनाईटेड को हराया

लंदन। मैनचेस्टर यूनाईटेड ने इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ शनिवार को।-3 की हार के साथ किया। मैनचेस्टर यूनाईटेड की हार हालांकि हैरानी भरी नही है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के कारण मैनेजर ओले गुनार सोल्सकर के पास अधिकांश खिलाड़ी एक हफ्ते से अधिक समय तक उपलब्ध नही थे।

त्वेसा ओपन डि फ्रांस में संयुक्त 10 वें स्थान पर

बारडॉक्स (फ्रांस)। भारत की त्वेसा मलिक रविवार को अंतिम दौर मे चार ओवर 75 के लचर प्रदर्शन के साथ रविवार को यहां लाकोस्टे ओपन डि फ्रांस गोल्फ टूर्नामेंट में संयुक्त 10वे स्थान पर रही। भारत के बाहर लेडीज यूरोपीय टूर मे यह त्वेसा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। त्वेसा ने अंतिम दौर में चार बोगी की और एक भी बर्डी नही कर सकी जिससे उनका स्कोर चार ओवर रहा। इस प्रदर्शन के साथ उनका कुल स्कोर चार अंडर से ईवन पार हो गया और वह संयुक्त दूसरे से संयुक्त 10वे स्थान पर खिसक गई।

विलारीयाल के कोच के रूप में एमेरी की पहली जीत

बार्सीलोना। आर्सेनल द्वारा बर्खास्त किए जाने के 10 महीने बाद उनाई एमेरी ने स्पेनिश फुटबॉल लीग में विलारीयाल के कोच के रूप मे पहली जीत दर्ज की जब उनकी टीम ने शनिवार को ऐबार को 2-। से हराया।गेरार्ड मोरेनो ने एक गोल करने के अलावा पैको एलकासर के गोल में मदद की जिससे विलारीयाल ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जीत दर्ज की।ऐबार की तरफ से एकमात्र गोल किके गार्सिया ने किया।

बार्सीलोना के अध्यक्ष अपने खिलाफ हस्ताक्षर के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे

बार्सीलोना। स्पेन के बार्सीलोना फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष जोसेफ बारटोम्यू ने कहा कि उनका अपने पद से इस्तीफा देना का कोई इरादा नही है। बारटोम्यू और उनके बोर्ड को मतदान का सामना करने की याचिका पर क्लब के 20,000 से अधिक सदस्यो ने हस्ताक्षर किए है। बारटोम्यू ने स्थानीय चैनल टीवी3 से कहा, कोई भी अपने पद से इस्तीफा नही दे रहा है

मुंबई में मुश्ताक अली टूर्नामेंट कराने का आग्रह किया

मुंबई। मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) की शीर्ष परिषद के सदस्य और मशहूर क्यूरेटर नदीम मेमन ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) से यहां सैयद मुश्ताक अली ट्राफी आयोजित करने का आग्रह किया और कहा कि शहर में इस घरेलू टी20 टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए काफी मैदान हैं। बीसीसीआई प्रमुख सौरव गांगुली को लिखे ईमेल में मेमन ने कहा, मुंबई को मुश्ताक अली टूर्नामेंट आयोजित करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। हम मुंबई मे बीसीसीआई के साथ मुश्ताक अली टूर्नामेंट सत्र शुरू कर सक्ते है।

दिल्ली का शीर्षक्रम लड़खड़ाया, स्टोइनिस ने संभाला

● शमी का कमाल, किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ आठ विकेट पर 157 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर

भाषा। दुबई

पंत ने 31 रन बनाए

मोहम्मद शमी की अगुवाई की शानदार गेंदबाजी के सामने शीर्ष क्रम लड़खड़ाने के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स ने मार्कस स्टोइनिस के अंतिम ओवरों की धुआंधार बल्लेबाजी से किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग में आज यहां आठ विकेट पर 157 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया।

दिल्ली अंतिम तीन ओवरों में 57 रन जुटाने में सफल रहा जिसमें स्टोइनिस का योगदान अहम रहा। उन्होंने 21 गेंदों पर 53 रन बनाए जिसमें सात चौके और तीन छक्के शामिल हैं। इससे पहले कप्तान श्रेयस अय्यर (32 गेंदों पर 39, तीन छक्के) और ऋषभ पंत (29 गेंदों पर 31, चार चौके) ने चौथे विकेट के लिए 73 रन जोड़े थे। शमी ने 15 रन देकर चार विकेट लिए जबकि आईपीएल में पदार्पण कर रहे लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने भी प्रभाव छोड़ा और 22 रन देकर एक विकेट लिया। शेल्डन कोटरेल (24 रन देकर दो) ने भी पहले तीन ओवरों में प्रभावशाली गेंदबाजी की। स्टोइनिस ने जोर्डन को निशाने पर रखा और उन पर 18वें ओवर में छक्का और चौका जड़ने के बाद इस गेंदबाज के पारी के आखिरी ओवर में दो छक्के और तीन चौके लगाए तथा केवल 20 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। जोर्डन के इस ओवर में 30 रन बने। दिल्ली ने टास गंवाया और इसके बाद शमी की घातक गेंदबाजी और लापरवाह बल्लेबाजी के कारण जल्द ही उसका स्कोर तीन विकेट पर 13 रन हो गया। पिच से असमान उछाल मिल रही थी और किंग्स इलेवन के गेंदबाजों ने इसका फायदा उठाया। शमी की लॉकडाउन के दिनों में अपने गांव में की गई तैयारियों का असर उनकी गेंदबाजी पर साफ दिख रहा था। पहले ओवर में भाग्य उनके साथ नहीं था। शिखर धवन का कैच विकेटकीपर केएल राहुल ने छोड़ा लेकिन वह बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को रन आउट करने में सफल रहे। इसी ओवर में के गौतम ने शिमरोन हेटमायर का हवा में लहराता कैच छोड़ दिया।

स्कोरबोर्ड

दिल्ली कैपिटल्स : पृथ्वी का जोर्डन बो शमी 05, धवन रन आउट 00, हेटमायर का अग्रवाल बो शमी 07, अय्यर का जोर्डन बो शमी 39, पंत बो बिश्नोई 31, स्टोइनिस रन आउट 53, पटेल का राहुल बो कोटरेल 06, अश्विन का शमी बो कोटरेल 04, रबाडा नाबाद 00, नोर्जे नाबाद 03, **अतिरिक्त** (बाई 01, नोबाल 02, वाइड 06) 09, **कुल** (20 ओवर मे, आठ विकेट पर) 157, विकेट पतन :।-6, 2-9, 3-13, 4-86, 5-87, 6-96, 7-127, 8-154, गेंदबाजी:कोटरेल 4-0-24-2, शमी 4-0-15-3, जोर्डन 4-0-56-0, गौतम 4-0-39-0, बिश्नोई 4-0-22-।

शमी ने अगले ओवर में हालांकि पृथ्वी साव (पांच) और हेटमायर (सात) को पवेलियन भेज दिया। पावरप्ले में दिल्ली तीन विकेट पर 23 रन ही बना पाया। पंत और अय्यर दस ओवर तक स्कोर 49 रन तक ही पहुंचा पाए थे। इनमें अय्यर का गौतम पर लांग ऑन पर लगाया गया दर्शनीय छक्का शामिल था। इसी गेंदबाज पर उन्होंने बाद में लगातार दो छक्के लगाकर रन गति बढ़ाई लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के तीन गेंद के अंदर आउट होने से दिल्ली फिर बैकफुट पर चला गया।

कोहली आईपीएल खिताब के सपने को पूरा करने को उतरेंगे

● सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी आज शुरू करेंगे अभियान

भाषा। दुबई

विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) खिताब के जीतने के सपने को पूरा करने का अभियान सोमवार से शुरू करेंगे जब उनकी अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) का मुकाबला टूर्नामेंट में निरंतर प्रदर्शन करने वाली टीम सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) से होगा। दोनों टीमों में ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो अपने दम पर मैच का रूख पलट सकते हैं। कोहली ने पिछले कुछ सत्र में हमेशा शानदार प्रदर्शन किया है लेकिन पहली बार खिताब जीतने का उनका सपना तभी पूरा होगा जब टीम हर विभाग में अच्छा प्रदर्शन करेगी। पहले से ही बड़े खिलाड़ियों से भरी टीम में ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के कप्तान आरोन फिंच के आने से बल्लेबाजी और मजबूत हुई है। युवा सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडीक्कल से भी उम्मीदें काफी हैं। वहीं दूसरी तरफ वार्नर ने तीन बार टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप (सत्र में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले) हासिल की है और उनकी कप्तानी में टीम 2016 में चैम्पियन बनी थी। वार्नर और जॉनी बेयरस्टॉ टूर्नामेंट के सबसे खतरनाक सलामी जोड़ियों में से एक है। पिछले सत्र में आरसीबी के खिलाफ इस जोड़ी ने पहले विकेट के लिए रिकार्ड (आईपीएल) रनों की साझेदारी की थी। वे उस लय को यहां बरकरार रखना चाहेंगे। सनराइजर्स के पास केन विलियमसन, मनीष पांडे, मिशेल मार्श और फेबियन एलेन जैसे शानदार बल्लेबाज है। पिछले सत्र में आखिरी स्थान पर रहने वाली आरसीरबी की टीम इस सत्र में काफी संतुलित लग रही है लेकिन उसका आकलन मैदान पर ही होगा। सनराइजर्स के लिए निचले क्रम की बल्लेबाजी कमजोर कड़ी सबित हो सकती है। फ्रेंचाइजी ने विराट सिंह, अभिषेक शर्मा, प्रियम गर्ग और अब्दुल समद जैसे युवा बल्लेबाजों पर भरोसा जताया है और उम्मीद है कि इनमें से कोई खिलाड़ी मध्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन करेगा। टीम की गेंदबाजी इकाई में हालांकि ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है और भुवनेश्वर कुमार तेज गेंदबाजी की अगुवाई करेंगे जहां उन्हें संदीप शर्मा, सिद्दार्थ कौल और बासिल थम्पी जैसे गेंदबाजों का साथ मिलेगा।

उम्मीद है कि युवा खिलाड़ी प्रतिभा को प्रदर्शन में बदलेंगे: वार्नर

दुबई। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर को उम्मीद है कि उनकी टीम के युवा खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सत्र में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन में बदलने में सफल रहेंगे। उन्होंने कहा कि ए खिलाड़ी अगर सत्र की शुरूआत में लय हासिल करने में सफल रहे तो चीजें आसान होगी। सनराइजर्स हैदराबाद विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ सोमवार को आईपीएल के इस सत्र में अपने अभियान को शुरू करेगा। वार्नर ने टीम के खिलाड़ियों से कहा है कि जीत-हार की चिंता किए बिना खुल कर खेलें।

बटलर पृथकवास अवधि के कारण राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच नहीं खेल पाएंगे

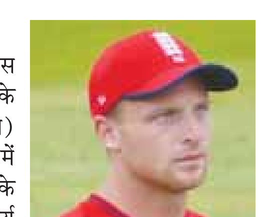

दुबई। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के पहले मैच में नहीं खेल पाएंगे। वह यहां अपने परिवार के साथ आए है और फिलहाल अनिवार्य पृथकवास अवधि में है। उन्होंने रॉयल्स के इंस्टाग्राम लाइव में कहा, मैं दुर्भाग्य से राजस्थान रॉयल्स के लिए पहला मैच नहीं खेल पाउंगा क्योंकि मैं अनिवार्य पृथकवास अवधि में हूं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मैं यहां अपने परिवार के साथ हूं। रॉयल्स से परिवार के साथ रहने की अनुमति मिलना शानदार है। लॉकडाउन के दौरान मुझे अपने परिवार के साथ रहने से काफी मदद मिलेगी।

सात महीने में पहला टूर्नामेंट खेले रहे नडाल हारे

● इटैलियन ओपन

भाषा। रोम

सात महीने बाद पहला टूर्नामेंट खेल रहे दुनिया के पूर्व नंबर एक टेनिस खिलाड़ी रफेल नडाल को इटैलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में यहां डिएगो श्वार्ट्जमैन के खिलाफ सीधे सेटों में हार का सामना करना पड़ा। रोम में नौ बार के चैंपियन स्पेन के नडाल ने दुनिया के 15वें नंबर के खिलाड़ी श्वार्ट्जमैन को पिछले नौ मैचों में हराया था लेकिन शनिवार को अर्जेन्टीना के खिलाड़ी ने 6-2, 7-5 से जीत दर्ज की। श्वार्ट्जमैन ने क्वार्टर फाइनल में बेसलाइन रैली और ड्रॉप शॉट्स से दबदबा बनाया जबकि नडाल ने कई सहज गलतियां की और उनकी पहली सर्विस भी उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। नडाल ने कहा कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान दो महीने टेनिस रैकेट को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने श्वार्ट्जमैन के 17 के मुकाबले 30 सहज गलतियां की जबकि अपनी सर्विस पर 63 में से 29 अंक ही जुटा पाए जिससे उन्होंने पांच बार अपनी सर्विस गंवाई। इससे पहले दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जर्मनी के क्वालीफायर डोमीनिक कोफर के खिलाफ 6-3, 4-6, 6-3 की जीत के दौरान एक बार फिर आपा को दिया। इसी कारण से दो हफ्ते से भी कम समय पहले उन्हें अमेरिकी ओपन के मुकाबले से बाहर कर दिया गया था। दूसरे सेट में 3-3 के स्कोर पर जब उनकी सर्विस टूटी तो उन्होंने नाराजगी में अपना रैकेट लाल बजरी पर जोर से मारा। उनका रैकेट टूट गया और उन्हें नए रैकेट से खेलना पड़ा। इसके लिए चेयर अंपायर ने उन्हें चेतावनी दी। रोम में पांचवां खिताब जीतने की कोशिश में जुटे जोकोविच सेमीफाइनल में कैस्पर रूड से भिड़ेंगे जिन्होंने स्थानीय दावेदार मातियो बेरेटिनी को 4-6, 6-3, 7-6 से हराया। श्वार्ट्जमैन का अंतिम चार में मुकाबला डेनिस शापोवालोव से होगा जिन्होंने ग्रिगोर दिमित्रोव को 6-2, 3-6, 6-2 से हराया। टूर्नामेंट अब तक खाली स्टेडियम में खेला गया है लेकिन इटली के खेल मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि सेमीफाइनल और फाइनल में 1000 दर्शकों को स्टेडियम में आने की इजाजत दी जाएगी।

हरिकृष्णा सातवें स्थान पर रहे, कार्लसन और सो को खिताब

चेन्नई। भारतीय ग्रैंडमास्टर पी हरिकृष्णा ब्लिट्ज-2 में नौ दौर में सिर्फ तीन अंक जुटाकर सेंट लुई रेपिड एवं ब्लिट्ज आनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में संयुक्त सातवें स्थान पर रहे। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी कार्लसन और अमेरिका के वेस्ली सो टूर्नामेंट के संयुक्त विजेता रहे। टूर्नामेंट

के अंतिम दिन हरिकृष्णा ने एकमात्र जीत अमेरिका के जेफ्रे शियोंग के खिलाफ दर्ज की जो टूर्नामेंट में सबसे कम रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं। हरिकृष्णा ने चार मुकाबले गंवाए जबकि तीन बाजी ड्रॉ रही। वह शियोंग के साथ संयुक्त सातवें स्थान पर रहे। भारत के दूसरे नंबर के खिलाड़ी हरिकृष्णा ने ब्लिट्ज-। में कार्लसन को हराकर उलटफेर किया था लेकिन वे इस प्रदर्शन को बरकरार नहीं रख पाए और ब्लिट्ज-2 में उन्हें नार्वे के विश्व चैंपियन के खिलाफ 47 चाल में हार का सामना करना पड़ा।

ऐसी स्थिति में वनडे अंतरराष्ट्रीय मैचों का अनुभव काम आता है : धोनी

भाषा। अबुधाबी

चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पहले मैच में गत चैंपियन मुंबई इंडियन्स के खिलाफ पांच विकेट की जीत में उनकी टीम का अनुभव अहम साबित हुआ।अंबाती रायुडू और फाफ डुप्लेसिस ने तीसरे विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी की जबकि पीयूष चावला ने शानदार गेंदबाजी की और उन्हें सैम कुरेन, दीपक चाहर और लुंगी एनगिडी जैसे गेंदबाजों का अच्छा साथ मिला।

फ्लेमिंग ने कहा, कुछ और मैचों में नहीं खेल पाएंगे ब्रावो

अबुधाबी। चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने पुष्टि की है कि टीम के स्टार आलराउंडर ड्वेन ब्रावो इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 13वें सत्र के कुछ और मैचों में नहीं खेल पाएंगे। चोट से उबर रहे वेस्टइंडीज के इस अनुभवी खिलाड़ी की गैरमौजूदगी के बावजूद तीन बार के चैंपियन सीएसके ने अपने अभियान का आगाज शनिवार को यहां मुंबई इंडियन्स पर पांच विकेट की जीत के साथ किया।

बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजने के धोनी के कदम से कुरेन हैरान

अबुधाबी। इंग्लैंड के आलराउंडर सैम कुरेन ने कहा है कि वह यहां मुंबई इंडियन्स के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग के पहले मैच में उन्हें अपने से पहले बल्लेबाजी के लिए भेजने के चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के कप्तान जीनियस महेंद्र सिंह धोनी के फैसले से हैरान थे।टूर्नामेंट के पहले मैच में 22 साल के इस आलराउंडर ने सीएसके की पांच विकेट की जीत में अहम भूमिका निभाई। प्रभावी गेंदबाजी करने के बाद कुरेन ने सिर्फ छह गेंद में 18 रन की पारी खेलकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद की।कुरेन ने मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान कहा, ईमानदारी से कहूं तो मैं हैरान था कि मुझे बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। वह (धोनी) जीनियस है और बेशक उसने कुछ सोचकर ही ऐसा किया होगा।

सरकारी बैंकों में अप्रैल-जून तिमाही में आए 19,964 करोड़ की धोखाधड़ी के 2,867 मामले

नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में 19,964 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 2,867 मामले सामने आए। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी से यह खुलासा हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्र शेखर गौड़ ने सूचना के अधिकार के तहत रिजर्व बैंक से यह जानकारी मांगी थी। देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में संख्या के हिसाब से धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा मामले आए। वहीं मूल्य के हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) धोखाधड़ी से सबसे अधिक प्रभावित रहा। आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून, 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंको में एसबीआई में सबसे अधिक 2,050 धोखाधड़ी के मामले सामने आए। इन मामलों से जुड़ी राशि 2,325.88 करोड़ रुपए है। मूल्य के हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया को धोखाधड़ी से सबसे अधिक चोट पहुंची। इस दौरान बैंक ऑफ इंडिया में 5,124.87 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 47 मामलों का पता चला। इसके अलावा केनरा बैंक में 3,885.26 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 33, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2,842.94 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 60, इंडियन बैंक में।,469.79 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 45, इंडियन ओवरसीज बैंक में।,207.65 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 37 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में।,140.37 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 9 मामले सामने आए।

भारत ने मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी

माले। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद के लिए मालदीव को 25 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। भारतीय दूतावास ने रविवार को यह जानकारी दी। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश की कठिन आर्थिक स्थिति से पार पाने में मदद के आग्रह के बाद यह सहायता दी गई है। यह वित्तीय सहायता सर्वाधिक अनुकूल शर्तों पर उपलब्ध कराई गई है। दूतावास ने एक बयान में कहा कि रविवार को विदेश मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में वित्तीय सहायता अनुदान सौंपा गया। इस मौके पर विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद, वित्त मंत्री इब्राहिम अमीर, उच्चायुक्त संजय सुधीर और एसबीआई-माले के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भारत मिश्रा मौजूद थे।

देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या मार्च में समाप्त तिमाही में 3.4 प्रतिशत बढ़कर 74.3 करोड़ पर

नई दिल्ली। देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही में 3.4 प्रतिशत बढ़कर 74.3 करोड़ पहुंच गई। दूरसंचार नियामक ट्राई के क्षेत्र के तिमाही प्रदर्शन पर जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही में 52.3 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ रिलायंस जियो पहले स्थान पर जबकि 23.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ भारतीय एयरटेल दूसरे स्थान पर रही। आलोच्य अवधि में वोडाफोन आइडिया तीसरे स्थान पर रही। उसके इंटरनेट ग्राहकों की संख्या के आधार पर बाजार हिस्ससेदारी 18.7 प्रतिशत रही। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 71.874 करोड़ थी, जो मार्च, 2020 में 3.40 प्रतिशत बढ़कर 74.319 करोड़ पहुंच गई।

जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए 21 राज्यों ने किया कर्ज प्रस्ताव का समर्थन

● 97,000 करोड़ रुपए की धनराशि लेंगे

भाषा। नई दिल्ली

जीएसटी संग्रह में कमी की क्षतिपूर्ति के लिए कुल 21 राज्यों ने 97,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने के केंद्र के विकल्प का समर्थन किया है। ये राज्य मुख्य रूप से भाजपा शासित और उन दलों की सरकार वाले हैं जो विभिन्न मुद्दों पर केंद्र की नीतियों का समर्थन करते रहे हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी।

जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र को अपने निर्णय के बारे में सूचना दी है, उनमें आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, ओड़िशा, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश हैं। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल को जीएसटी परिषद को अपने विकल्प के बारे में सूचना देनी है। सूत्रों ने कहा कि जो राज्य निर्धारित तारीख पांच अक्टूबर, 2020 तक कर्ज विकल्प के बारे में परिषद को सूचना नहीं देंगे, उन्हें क्षतिपूर्ति बकाया प्राप्त करने के लिए जून 2022 तक इंतजार करना होगा। यह भी इस बात पर निर्भर है कि जीएसटी परिषद उपकर संग्रह की अवधि 2022 के बाद बढ़ाता है या नहीं। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की मौजूदगी में जीएसटी परिषद को कोई प्रस्ताव अगर मतदान के लिए आता है तो उसे पारित करने के लिए केवल 20 राज्यों की जरूरत है। चालू वित्त वर्ष में राज्यों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में 2.35 करोड़ रुपए के राजस्व की कमी का अनुमान है। केंद्र के आकलन के अनुसार करीब 97,000 करोड़ रुपए की कमी जीएसटी क्रियान्वयन के कारण है, जबकि शेष 1.38 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की वजह कोविड-19 है। इस महामारी के कारण राज्यों के राजस्व पर प्रतिकूल असर पड़ा है। केंद्र ने पिछले महीने राज्यों को दो विकल्प दिए थे। इसके तहत 97,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधा से या पूरा 2.35 लाख करोड़ रुपए बाजार से लेने का विकल्प दिया गया था। साथ ही आरामदायक और समाज के नजरिए से अहितकर वस्तुओं पर 2022 के बाद भी उपकर लगाने का प्रस्ताव किया गया था। कुछ और राज्य कर्ज के विकल्प के बारे में एक-दो दिन में सूचना दे देंगे। उसने कहा कि मणिपुर ने शुरू में बाजार से 2.35 लाख करोड़ रुपए के कर्ज लेने का विकल्प चुना था। बाद में उसने 97,000 करोड़ रुपए के कर्ज का विकल्प चुना। हालांकि गैर-भाजपा शासित राज्य जीएसटी राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए कर्ज के विकल्प का विरोध कर रहे हैं।

दूसरी छमाही के लिए कर्ज समयसारणी सितंबर के आखिरी सप्ताह में तय करेगा वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ परामर्श के बाद वित्त मंत्रालय इस महीने के आखिरी सप्ताह मे चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के लिए कर्ज समयसारणी पर निर्णय लेगा। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। मई में की गई घोषणा के अनुसार, सरकार का कर संग्रह मे गिरावट के बीच कोविड-19 संकट से निपटने के लिए बढ़ते खर्च को पूरा करने को लेकर अक्टूबर-मार्च की अवधि के दौरान 12 लाख करोड़ रुपए मे से 5.02 लाख करोड़ रुपए का शेष ऋण लेने का इरादा है। सूत्रों ने कहा कि उधार समयसारणी तय करने की बैठक के लिए सही तारीख अभी तय नही है, लेकिन इस महीने के आखिरी सप्ताह मे इसके होने की संभावना है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही मे दिनांकित प्रतिभूतियो से 6.98 लाख करोड़ रुपए के कुल उधार लक्ष्य का 58 प्रतिशत जुटाने का विचार किया था। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान केंद्र सरकार ने 3,46,000 करोड़ रुपए की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी की, जबकि एक साल पहले इसी अवधि मे 2,21,000 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां जारी की गई थी। दूसरी तिमाही में, दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधार 18 सितंबर तक 3.60 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच चुका है।

बड़े बंदरगाहों पर तापीय, कोकिंग कोयला आयात 28 प्रतिशत घटकर 4.6 करोड़ टन रहा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के बीच देश के 12 बंदरगाहो पर तापीय और कोकिंग कोयले का आयात चालू वित्त वर्ष मे अप्रैल-अगस्त के दौरान इससे पूर्व वित्त वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 27.93 प्रतिशत घटकर 4.577 करोड़ टन रहा। बंदरगाहो के संगठन इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन (आईपीए) ने यह कहा। आलोच्य अवधि मे तापीय कोयला आयात 25.42 प्रतिशत घटकर 2.893 करोड़ टन, जबकि कोकिंग कोयले का आयात 31.87 प्रतिशत घटकर 1.684 करोड़ टन रहा।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given on behalf of **Mrs. Reeta Devi** who is purchasing the **Plot bearing No. 6, land area measuring 120 sq. yrds., out of Khasra No. 1013, situated in the Residential colony known as Subhash Park of Village Makanpur, Pargana-Loni, Tehsil Dadri Distt. Ghaziabad, U.P.** from **Mrs. Bala Devi** and further will be mortgaging against the financial assistance from **VASTU HOUSING FINANCE CORPORATION LTD.** To comply the requirements of bank/NBFC, we give this public notice that if any person(s) having any objection regarding ownership and/ or creating mortgage of the said property is/are hereby requested to intimate in writing to the undersigned within 07days from the date of this notice, at below address. **Lucem Legal LLP**
269, Rama House, Ground Floor, Masjid Moth ,Opp. Uday Park, South Ext.II, New Delhi-49, Contact #011-40046316

निजी अस्पतालों को दिख रहे उबरने के संकेत

नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी से वित्तीय तौर पर गंभीर रूप से प्रभावित हेल्थकेयर क्षेत्र की निजी कंपनियों को लॉकडाउन की पाबंदियां हटाए जाने के बाद उबरने के संकेत दिख रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा देने वाली निजी कंपनियों ने ऐसी राय व्यक्त की है। अपोलो हॉस्पिटल्स की प्रबंध निदेशक (एमडी) सुनीता रेड्डी ने पीटीआई-भाषा से कहा, जैसे ही देश में अनलॉक की शुरुआत हुई, हम लॉकडाउन के कारण लगे शुरुआती झटकों के दूर होने के बारे में आश्वस्त थे।

लॉकडाउन के दौरान मोबाइल के जरिए शेयर कारोबार में आया जोरदार उछाल

भाषा। नई दिल्ली

कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में खुदरा निवेशकों ने शेयर बाजारों का रुख किया। ब्रोकरेज कंपनियों के अनुसार लॉकडाउन में मोबाइल फोन के जरिए शेयर कारोबार में अच्छा-खासा इजाफा हुआ। उनका मानना है कि आगे मोबाइल के जरिए शेयरों की खरीद-फरोख्त और बढ़ेगी, क्योंकि स्मार्टफोन के जरिए ग्राहकों को कारोबार और निवेश से जुड़े घटनाक्रमों की तत्काल जानकारी मिल जाती है। फायर्स के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं सह-संस्थापक तेजस खोड़े ने कहा, लॉकडाउन के दौरान शेयर कारोबार से जुड़ी गतिविधियों में काफी बदलाव आया। कारोबारी गतिविधियों का रुख डेस्कटॉप से मोबाइल उपकरणों की तरफ हो गया। ज्यादातर युवा निवेशकों के बीच मोबाइल के जरिए शेयरों का कारोबार बढ़ रहा है। ए पहली बार के निवेशक भी हैं।

SBFC SMALL BUSINESS FINCREDIT
SBFC Finance Pvt. Ltd.
(Erstwhile Small Business Fincredit India Pvt. Ltd.)
Address Unit No. 103, First Floor C&B Square, Sangam Complex, 127, Andheri-Kurla Road, Village Chakala, Andheri (East), Mumbai 400059 | Telephone: +91 22 67875300
Fax: +91 22 67875334 | www.sbfc.com|
Corporate Identity Number: U67190MH2008PTC178270

PUBLIC NOTICE

जनता को यह सूचित किया जाता है कि उपयोग किये गए सोने के गहनों की नीलामी स्मॉल बिजनेस फिनक्रेडिट इंडिया प्रा.लि. (रिस्टव्हाइल मैप फिनसर्व प्रा. लि.) द्वारा दिनांक 24 सितंबर 2020 को या उसके बाद 10 बजे क्षेत्रीय कार्यालय लाजपत नगर O-7, ऊपर लुक सलून, लाजपत नगर -II, नई दिल्ली - 110024, नई दिल्ली-110024., फरीदाबाद शाखा D-2, पहली मंजिल, नजदीक 1-2 चौक फरीदाबाद हरियाणा और गुरूग्राम शाखापहली मंजिल, प्रोपर्टी नं. 342/9, सुभाष नगर, नई रेलवे रोड, गुरुग्राम 122001 हरियाणा पर की जाएगी। ।नीलाम किए जाने वाल सोने के गहने उन सभी अतिदेय ग्राहक खातों से संबंधित है जो अपना बकाया देने में अस्मर्थ है। उधारकर्ताओं को नीलाम की नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा विधिवत् जारी की गई है।नीलाम किए जाने वाले सोने के गहने नीचे दिये गये शाखा के अतिदेय ग्राहक खातों से संबंधित है।

फरीदाबाद शाखा, PR00674653 PR00678233/GLDS138254, लाजपत नगर शाखा: PR00636531/GLDS85286,, रोहिणी शाखा:PR00719810/GLDS0141021,उत्तम नगर शाखा: PR00717103/GLDS143226, PR00673517/GLDS123149, PR00698809/ GLDS143131,PR00624154/SEC-IC01-GLDS91524,

अधिक जानकारी के लिए, कृपया
एसबीएफसी फायनैन्स प्रा.लि.(रिस्टव्हाइल स्मॉल बिजनेस फिनक्रेडिट इंडिया प्रा.लि.)
संपर्क सं.: लाजपत नगर 1800-102-8012 / 011- 40305228 / 207,
फरीदाबाद 01294314725/4104450, और गुरूग्राम शाखा 0124-4276037
एसबीएफसी फायनैन्स प्रा.लि. (रिस्टव्हाइल स्मॉल बिजनेस फिनक्रेडिट इंडिया प्रा.लि.) को बिना किसीपूर्व सूचना के नीलाम किए जाने वाले खातों की संख्या में परिवर्तन/निलंबन/निरस्तीकरण करने का अधिकार है)
KARVY FINANCE Retail is now SBFC

शरीफ ने फौज व इमरान खान सरकार पर बोला जोरदार हमला

भाषा। इस्लामाबाद

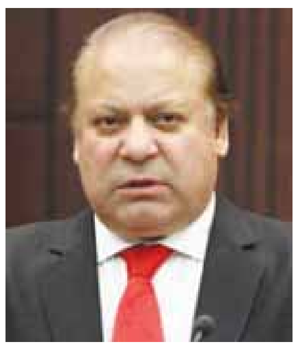

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ ने देश में ताकतवर फौज की आलोचना करते हुए सियासत में वापस आने के लिए रास्ता तैयार किया और कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ है जो" अक्षम" व्यक्ति को सत्ता में लेकर आए हैं।पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) द्वारा आहूत सर्व दलीय सम्मेलन को वीडियो लिंक के जरिए संबोधित करते हुए तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे शरीफ ने लोगों की बुनियादी परेशानियां हल करने में नाकाम रहने पर सत्तारूढ़ पार्टी पर जोरदार हमला बोला। इस सर्व दलीय सम्मेलन का मकसद खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख शरीफ (70) पिछले साल नवंबर से लंदन में रह रहे हैं। लाहौर उच्च न्यायालय ने उन्हें इलाज के वास्ते चार हफ्तों के लिए विदेश जाने की इजाजत दी थी। पीपीपी के प्रमुख आसिफ अली ज़रदारी ने शुक्रवार को शरीफ से फोन पर बातचीत की थी और उन्हें रविवार को ऑनलाइन होने वाली विपक्ष की अगुवाई वाले सर्व दलीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। सम्मेलन में शरीफ ने खान का कथित रूप से समर्थन करने के लिए देश की ताकतवर फौज की आलोचना की। उन्होंने कहा, हमारा संघर्ष इमरान खान के खिलाफ नहीं है। आज, हमारा संघर्ष उन लोगों के खिलाफ है, जिन्होंने इमरान खान को बैठाया है और जिन्होंने उन जैसे अक्षम व्यक्ति को लाने के लिए (2018) के चुनाव को प्रभावित किया और मुल्क को तबाह किया"पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी प्राथमिकता इस चयनित सरकार और इस व्यवस्थौ को हटाने की होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर बदलाव नहीं होते हैं तो मुल्क को अपूरणीय क्षति होगी।उन्होंने कहा कि सेना को सियासत से दूर रहना चाहिए और संविधान एवं राष्ट्रपिता कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दृष्टि का अनुसरण करना चाहिए तथा लोगों की पसंद में दखल नहीं देनी चाहिए।शरीफ ने कहा,"हमने इस देश को अपनी नजर में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मजाक बना दिया है। शरीफ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी ने एक बार कहा था कि पाकिस्तान में राज्य के अंदर एक राज्य है" उन्होंने कहा, यह दुखद है कि स्थिति बदतर हो गई है और राज्य के ऊपर एक राज्य हो गया है। यह समानांतर सरकार की बीमारी हमारी परेशानी की मूल वजह है।

अफगान सेना के हवाई हमले में 24 की मौत

एपी। काबुल

अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में अफगान सेना के हवाई हमले में 24 लोग मारे गए और छह अन्य घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदशियों ने रविवार को यह जानकारी दी। दो प्रत्यक्षदर्शियों ने समाचार एजेंसी एपी को बताया कि शनिवार को उत्तरी कुंदुज प्रांत के सैयद रमजान गांव पर हवाई हमले किए गए, जिनमें मारे गए लोग आम आदमी हैं। यह गांव इस प्रांत के खनबाद नामक जिले में है और इस जिले पर तालिबान का नियंत्रण है।

हालांकि, अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हवाई हमले में 30 तालिबान लड़ाके मारे गए। उसने यह भी कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि मारे गए लोगों में आम आदमी तो नहीं हैं। ये हवाई हमले ऐसे वक्त किए गए हैं, जब तालिबान और सरकार के वार्ताकार अफगानिस्तान के भविष्य पर और युद्ध एवं संघर्ष समाप्ति पर चर्चा करने के लिए कतर में पहली बार बैठक कर रहे हैं।

बैंकाक में हो रहे प्रदर्शन को रोकने के लिए ग्रांड पैलेस के चारों तरफ मास्क पहने तैनात पुलिस अधिकारी

गोर-टेक्स कपड़ा बनाने वाले रॉबर्ड डब्ल्यू गोर का निधन

नेवार्क। पानी में गीले होने से बचाने और भीतर हवा का प्रवाह बनाए रखने में सक्षम गोर टेक्स कपड़े का निर्माण करने वाले रॉबर्ट डब्ल्यू गोर का निधन हो गया। वह 83 साल के थे। इस कपड़े के निर्माण ने कपड़े के क्षेत्र में क्रांति ला दी और कई क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल भी होने लगा। गोर का निधन बृहस्पतिवार को मेरिलैंड स्थित अपने घर में हुआ। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गोर, डब्ल्यू एल गोर एसोसिएट्स के करीब 25 साल तक अध्यक्ष और 30 साल तक वह कंपनी के प्रमुख रहे। उन्होंने डेलावेयर में कंपनी की एक प्रयोगशाला में 1969 में पॉलीमर के एक नए रूप की पहचान की थी। विलमिंग्टन के न्यूज जर्नल की खबर के मुताबिक कंपनी की शुरुआत करने वाले उनके पिता ने सस्ते पल्बंर टेप के निर्माण के लिए नया तरीका तलाशने के लिए अनुसंधान करने को कहा था जिसमें पीटीएफई का इस्तेमाल करना था। इसके बाद उनके बेटे ने पाया कि पीटीएफई को अचानक झटके से खीचने पर पॉलीमर।,000 फीसदी तक खिंच सकता है।

अमेरिका ने ईरान के खिलाफ संरा पाबदियां बहाल की

भाषा। वाशिंगटन

ट्रंप प्रशासन ने शनिवार को घोषणा की कि ईरान पर संयुक्त राष्ट्र की सभी पाबंदियां बहाल कर दी गई हैं। उसके इस कदम को बाकी दुनिया ने खारिज कर दिया है और संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक से पहले इस वैश्विक निकाय में जबर्दस्त जोर-आजमाईश के आसार पैदा हो गए हैं। यह कदम तब उठाया गया है जब एक महीने पहले विदेश मंत्री माईक पोम्पियो ने सुरक्षा परिषद को बताया कि ईरान ज्वायंट कंप्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या जेसीपीओए (2015 के ईरान परमाणु करार) के तहत अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। उन्होंने स्थानीय समयानुसार शाम आठ बजे एक बयान में कहा, अमेरिका ने यह कार्वाई इसलिए की है क्योंकि ईरान के जेसीपीओए दायित्वों का पालन करने में विफल रहने के साथ ही सुरक्षा परिषद भी ईरान पर हथियार पाबंदियों का विस्तार करने में विफल रही जो उस पर 13 सालों से थी। उन्होंने कहा, अपने अधिकारों के तहत हमने हथियार पाबंदी समेत संयुक्त राष्ट्र के हटा लिए गए प्रतिबंधों को बहाल करने की अपनी स्नैपबैक (एक प्रकार की कानूनी) प्रक्रिया शुरु की है। फलस्वरूप दुनिया सुरक्षित रहेगी। लेकिन अमेरिका के इस कदम का सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्यों देशों ने जबर्दस्त विरोध किया है और उन्होंने उसको नजरअंदाज करने की ठानी है। उनका कहना है कि अमेरिका इसका कानूनी हक गवां चुका है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2018 में इस परमाणु करार से हट गए और ईरान पर अमेरिकी पाबंदियां लगा दी। स्नैपबैक का तात्पर्य है कि परमाणु करार के तहत दी गई ढील या हटा ली गई पाबंदियों को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा दोबारा लगाया जा सकता है।

चीन आक्रामकता का सहारा ले रहा : अमेरिकी सांसद

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के एक शीर्ष भारतीय-अमेरिकी सांसद ने कहा है कि भारत को सीमा क्षेत्र में रक्षा ढांचा निर्माण से रोकने के लिए चीन आक्रामक रुख अपना रहा है क्योंकि इस निर्माण के बिना बीजिंग को वहां रणनीतिक बढ़त हासिल होती है।

भारतीय सेना और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के बीच मई की शुरुआत से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से लगे कई इलाकों में गतिरोध जारी है। भारतीय-अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने पीटीआई-भाषा के साथ एक साक्षात्कार में कहा, यह एक गंभीर स्थिति है। मुख्य तौर पर यह तब शुरू हुआ जब भारत सरकार ने चीन से लगते सीमा क्षेत्र में पूरी तरह से अपने इलााके में रक्षा तंत्र की मजबूती के लिए ढांचागत निर्माण किया। चीन को प्रत्यक्ष तौर पर यह बुरा लगा और उसने इसके बाद गलवान क्षेत्र में बेहद उकसावे वाला कदम उठाया। कृष्णमूर्ति को लगातार तीसरी बार इलिनोइस से प्रतिनिधि सभा में निर्वाचन की उम्मीद है। वह खुफिया विषय पर सदन की स्थाई प्रवर समिति में शामिल पहले और एकमात्र भारतीय-अमेरिकी सांसद हैं। भारत के खिलाफ चीनी आक्रामकता और सीमा पर स्थिति को लेकर पिछले सप्ताह इस समिति को गुप्त जानकारी उपलब्ध कराई गई। कृष्णमूर्ति ने उस जानकारी के बारे में विस्तृत रूप से बताने से इनकार किया लेकिन उन्होंने चीन के कदमों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, विडंबना यह है कि चीन सीमा क्षेत्र में अपनी तरफ पहले ही ढांचागत निर्माण कार्य पूरा कर चुका है। और इसलिए मैं इस बारे में बहुत चिंतित हूं कि चीन सीमा विवाद या तनाव से जुड़े वैसे ही कदम उठा रहा

● भारत को सीमा क्षेत्र में रक्षा ढांचा निर्माण से रोकने पर अमेरिका के एक शीर्ष भारतीय-अमेरिकी सांसद ने उठाए सवाल

है जैसा कि वह ताइवान, जापान, वियतनाम और दक्षिण चीन सागर में फिलीपीन के साथ कर चुका है। गलवान घाटी में 15 जून को चीनी सैनिकों के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव काफी बढ़ चुका है। इस झड़प में चीनी पक्ष के जवान भी मारे गए थे लेकिन चीन ने इस बारे में विस्तृत जानकारी जाहिर नहीं की थी। कृष्णमूर्ति ने कहा कि चीन अच्छे पड़ोसी की तरह व्यवहार नहीं कर रहा है। यह समय चीन के पड़ोसियों के लिए आपस में हाथ मिलाने का है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के देशों और अन्य के आपसी गठजोड़ से यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि जब आपसी विवादों को सुलझाने के लिए हमेशा ही कूटनीतिक दरवाजे का इस्तेमाल होना चाहिए तो चीन सरकार अपने रास्ते बनाने के लिए सैन्य कदम नहीं अपना सकती है। कृष्णमूर्ति ने कहा कि चीन के पड़ोसी देश तेजी से इस पर बातचीत कर रहे हैं कि कैसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के हिसाब से नियम बनाए जाएं। उन्होंने कहा, इसलिए अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अन्य इस पर चर्चा करने के लिए साथ आए हैं कि कैसे आक्रामकता और सैन्य कदम से बचा जाए क्योंकि इससे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा हो सकती है।

चीन द्वारा भारत को रक्षा ढांचागत निर्माण से रोके जाने पर उन्होंने कहा कि बीजिंग इस क्षेत्र में हासिल रणनीतिक बढ़त को छोड़ना नहीं चाहता है। उन्होंने अमेरिका और भारत के बीच गहरे संबंध का उल्लेख करते हुए कहा कि अमेरिका को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अगर कोई अंतरराष्ट्रीय नियम या समझौते का उल्लंघन करेगा तो अमेरिका इन नियमों का पालन करनेवाले देश के साथ खड़ा होगा, जैसा कि भारत इस मामले में अंतरराष्ट्रीय समझौतों के साथ है। कृष्णमूर्ति ने चीन के खिलाफ और भारत के समर्थन में एक द्विदलीय प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन की शक्ल में है, जिसे सदन में बड़े समर्थन के साथ पारित किया गया। उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द कूटनीतिक तरीके से हल किया जाए।

रोम में इटली के प्रधानमंत्री अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए

व्हाइट हाउस के पते पर आए एक लिफाफे में जहर होने की पुष्टि

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका में संघीय अधिकारियों ने व्हाइट हाउस के पते पर आए एक लिफाफे में जहर रिसिन होने का पता लगाया है। एक अधिकारी ने एसोसिएट प्रेस को शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पत्र उस सरकारी प्रतिष्ठान में पकड़ा गया जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के लिए आने वाली डाक की जांच करता है। अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में इसमें रिसिन होने की पुष्टि हुई है। यह कैस्टर सीड (अरण्डी के बीज) में स्वाभाविक रूप से पाया जाने वाला विषैला पदार्थ है।

अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर यह जानकारी दी। संघीय जांचकर्ता यह पता लगा रहे हैं कि यह लिफाफा कहां से आया है और इसे किसने भेजा है। एफबीआई, सीक्रेट सर्विस और अमेरिकी डाक निरीक्षण सेवा जांच का नेतृत्व कर रहे हैं।

ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के लिए करेंगे किसी महिला न्यायाधीश को नामित

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश रूथ बदेर गिन्सबर्ग के निधन के बाद रिक्त हुए पद के लिए किसी महिला उम्मीदवार को नामित करेंगे।ट्रंप ने शनिवार को नॉर्थ कैरोलाइना में एक चुनावी रैली में समर्थकों से कहा, मैं अगले सप्ताह किसी को नामित करूंगा। मैं कह सकता हूं कि वह एक महिला होंगी। कोई अगर मुझसे अभी पूछे तो मैं कहूंगा कि एक महिला पहले स्थान पर होंगी। गिन्सबर्ग का कैंसर से शुक्रवार को निधन हो गया। वह 87 वर्ष की थीं। अमेरिका की शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाली गिन्सबर्ग दूसरी महिला थीं। उन्होंने पूरी जिदंगी लैंगिक समानता की वकालत की और न्यायाधीश के तौर पर प्रतिष्ठा हासिल की। ट्रंप ने कहा, इस पूरी प्रक्रिया को ले कर हमारे मन में बेहद सम्मान है। यह अनेक बार हो चुका है और आप जानते हैं कि हर बार किसी को नामित किया गया है, और कई बार ऐसा हुआ कि यह राष्ट्रपति चुनाव वाले वर्ष में हुआ। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि हम जल्द ही प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। जल्द ही हम नामित करेंगे। ट्रंप ने कहा कि उनकी सूची में 45 लोगों के नाम हैं लेकिन संभावित उम्मीदवारों की वह जल्द ही संक्षिप्त सूची बनाएंगे।चुनाव रैली में ट्रंप ने अपने समर्थकों से पूछा, नामित सदस्य पुरूष होना चाहिए या महिला। इस पर भीड़ ने जवाब दिया महिला।बहरहाल, डेमोक्रेटिक पार्टी ने तीन नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के पहले न्यायाधीश का नाम नामित किए जाने का विरोध किया है। राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने जोर दिया है कि गिन्सबर्ग के स्थान पर न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए चुनाव तक इंतजार करना चाहिए।बाइडेन ने कहा, मतदाता राष्ट्रपति को चुनेंगे और नए राष्ट्रपति को ही न्यायाधीश चुनने के बारे में फैसला करना चाहिए।

भयावह गोलीबारी ने बढ़ाई रोचेस्टर शहर की पीड़ा

रोचेस्टर (अमेरिका)। डेनियल प्रूड की पुलिस कार्वाई में दम घुटने से हुई मौत का इसी माह खुलासा होने से आक्रोशित न्यूयार्क का रोचेस्टर शहर शनिवार को स्तब्ध रह गया जब एक पार्टी में गोलीबारी होने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि 14 अन्य घायल हो गए। रोचेस्टर सिटी काउंसिल के उपाध्यक्ष विल्ली लाईटफुड ने कहा, हमारा समुदाय पहले से ही पीड़ा से गुजर रहा है। इन सभी के ऊपर एक और मुसीबत आ गई। रात साढे बारह बजे गोलीबारी हुई। वैसे इसका प्रूड की मौत से कोई लेना-देना नहीं है। उस मौत का सारा ब्योरा छह माह बाद सामने आया है। शहर के कार्यवाहक पुलिस प्रमुख मार्क साइमन्स ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह वाकई बहुत बड़ी त्रासदी है। मेरा मतलब है कि 16 लोगों के हताहत होने के बारे में नहीं सुना गया होगा और हमारे समुदाय, जो पहले से इतनी चीजों से गुजर रहा था, को ऐसी त्रासदी से अनावश्यक रूप से जूझना पड़ा और वह भी इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने हिंसक तरीके से बर्ताव करने की ठान ली। यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं शर्मनाक है। डेनियल प्रूड की मौत का मामला सामने आने के बाद पश्चिमी न्यूयॉर्क के रोचेस्टर में पिछले दिनों जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था। लोग प्रूड की मौत को लेकर महापौर के इस्तीफे और संबंधित अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे है।

कोविड-19 संकट के बाद शायद दो करोड़ लड़कियां स्कूल नहीं लौट पाएंगी:मलाला

भाषा। इस्लामाबाद

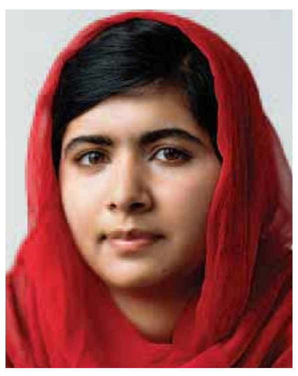

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई ने कहा है कि कोविड-19 संकट खत्म होने के बाद भी दो करोड़ लड़कियां शायद स्कूल नहीं पहुंच पाएंगी। डॉन अखबार के मुताबिक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर शुक्रवार को मलाला (23) ने माना कि कोविड-19 ने महिलाओं को शिक्षित करने के हमारे सामूहिक लक्ष्य को नुकसान पहुंचाया है।उन्होंने कहा, शिक्षा के मोर्चे पर महामारी खत्म होने के बाद भी दो करोड़ लड़कियां स्कूलों में नहीं लौट पाएंगी। वैश्विक स्तर पर कोष जुटाने के प्रयासों को भी धक्का लगेगा। पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए मुहिम के दौरान पाकिस्तान तालिबान के आतंकियों ने मलाला को गोली मार दी थी।मलाला ने वैश्विक समुदाय को याद दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पांच साल पहले निर्धारित सतत वैश्विक लक्ष्य में लाखों लड़कियों के सुनहरे भविष्य की कल्पना की गई थी जो शिक्षित होना चाहती हैं और गैर बराबरी से मुकाबला करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत कम प्रयास हुए हैं। उन्होंने वैश्विक संस्था से सवाल किया, आप कब काम पूरा करने का विचार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हमें इस मौजूदा संकट से आगे देखना होगा और दूरदर्शिता दिखानी होगी। बदलाव संभव है और यह हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने अमीर देशों से विकासशील देशों की जरूरतों के लिए मदद करने का आह्वान किया।

पाक के पंजाब प्रांत में सिख लड़की लापता अज्ञात अपहर्ता के खिलाफ मामला दर्ज

भाषा। इस्लामाबाद

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 22 वर्षीय सिख लड़की लापता हो गई और पुलिस ने अज्ञात अपहर्ता के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। मीडिया में आई एक खबर के मुताबिक यह घटना हाल में अटक जिले के हसनअब्दाल शहर में हुई। इसी शहर में सिखों का पवित्र धर्मस्थल प्रसिद्ध गुरुद्वारा पंजा साहिब है। डॉन अखबार के मुताबिक लड़की कचरा फेंकने के लिए अपने घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं आई। उसके पिता हसनअब्दाल में एक दुकान चलाते हैं। खबर में इस बात का जिक्र नहीं है कि यह घटना कब हुई। उप संभागीय पुलिस अधिकारी राजा फैयाज उल हसन के हवाले से बताया गया कि हसनअब्दाल पुलिस ने लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर अज्ञात अपहर्ता के खिलाफ पाकिस्तान की दंड संहिता की धारा 365 बी के तहत अगवा करने (शादी करने के लिए अपहरण समेत) के तहत एक मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस लापता लड़की की तलाश कर रही है।जिला पुलिस के प्रवक्ता ताहिर इकबाल ने कहा कि लड़की के पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के तुरंत बाद अज्ञात अपहर्ता के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया।उपसंभागीय पुलिस अधिकारी हसन ने बताया कि जिस दिन लड़की लापता हुई, उसके अगले दिन उसने अपने पिता को वाट्सऐप पर एक मैसेज भेजकर बताया कि उसने अपनी इच्छा से शादी की है और इस्लाम कबूल कर लिया है।उन्होंने कहा कि पुलिस की कई टीमें लड़की की तलाश कर रही हैं ताकि उसे अदालत में पेश किया जाए और बयान दर्ज कराया जाए।पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सरदार अमीर सिंह ने पुष्टि की है कि गुरुद्वारा पंजा साहिब के पास स्थित घर से लड़की लापता हो गई।सिंह ने कहा कि लड़की के पिता और चाचा ने धार्मिक मामलों के संघीय मंत्री नूरउल हक कादरी से शुक्रवार को मुलाकात की और लड़की के लापता होने के बारे में उन्हें अवगत कराया।पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण और गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी के मामले आते रहते हैं लेकिन उनमें से ज्यादातर मामले सिंध प्रांत से आते हैं।

पाकिस्तान में सुरक्षा बलों ने चार आतंकवादियों को मार गिराया

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों ने कम से कम चार आतंकवादियों को मार गिराया। सेना ने यह जानकारी दी।सेना ने एक बयान में कहा कि सुरक्षा बलों ने शनिवार को खुफिया सूचना के आधार पर अवारान जिले के मध्य मकरान क्षेत्र में अभियान चलाया था। बयान के अनुसार, इस दौरान आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करके भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और संचार उपकरण बरामद किए गए। सेना ने कहा कि इस दौरान आतंकवादियों के प्रशासनिक शिविरों को भी तबाह कर दिया गया। बयान में कहा गया है कि शनिवार को एक अन्य घटना में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान जिले के स्पालगा इलाके में एक अभियान के दौरान आतंकवादियों के साथ हुई गोलीबारी में कम से कम दो सैनिकों की मौत हो गई। सैनिकों ने तलाशी अभियान के लिए इलाके की घेराबंदी की थी।

पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के 640 नए मामले

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 640 नए मामले सामने आने के बाद रविवार को इस महामारी के मामलों की संख्या बढ़कर 3,05,671 हो गई। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। इसने बताया कि इस अवधि में एक मरीज की मौत भी हो गई और इसके साथ ही देश में महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या 6,446 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान में अब तक कोविड-19 के 2,92,303 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 562 की हालत गंभीर है। सिंध में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के।,33,626 , पंजाब में 98,368, खैबर पख्तूनख्वां में 37,317, इस्लामाबाद में 16,126, गिलगित बाल्तिस्तान में 3,450 और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 2,517 मामले में आ चुके हैं।

तेज हवा से और भड़की कैलिफोर्निया के जंगल की आग, लोगों से घर खाली करने को कहा गया

जूनिपर हिल्स(अमेरिका)। लॉस एंजिल्स के पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों पर स्थित जंगल में करीब दो सप्ताह से लगी आग शनिवार को तेज हवा के चलते और भड़क गई और नीचे की तरफ बढ़ रही है। प्रशासन ने अब क्षेत्र के लोगों से इलाके को खाली करने को कहा है। आग की वजह से इलाके के कुछ घर भी जल गए हैं। इस बीच अधिकारी एक दमकल कर्मी की मौत की जांच में जुटे हैं। यह वैसी ही घटना थी जैसी इस महीने के शुरू में दक्षिणी कैलिफोर्निया के जंगल में पायरोटेक्निक उपकरण से लगी थी। उस उपकरण का इस्तेमाल एक दंपत्ति अपने बच्चे के प्रसव-पूर्व लिंग का पता लगाने के लिए कर रहे थे। अमेरिकी वन सेवा ने एक बयान में कहा कि लॉस एंजिलिस से करीब 120 किलोमीटर दूर सैन बर्नार्डिनो राष्ट्रीय वन में बृहस्पतिवार को दमकलकर्मी की जान गई जब उनका दल एल डोराडो की आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। उत्तरी लॉस एंजिलिस काउंटी में अग्निशमन कर्मी शनिवार को घरों को बचाने में जुटे थे।

उचित विशेषज्ञता चुनें

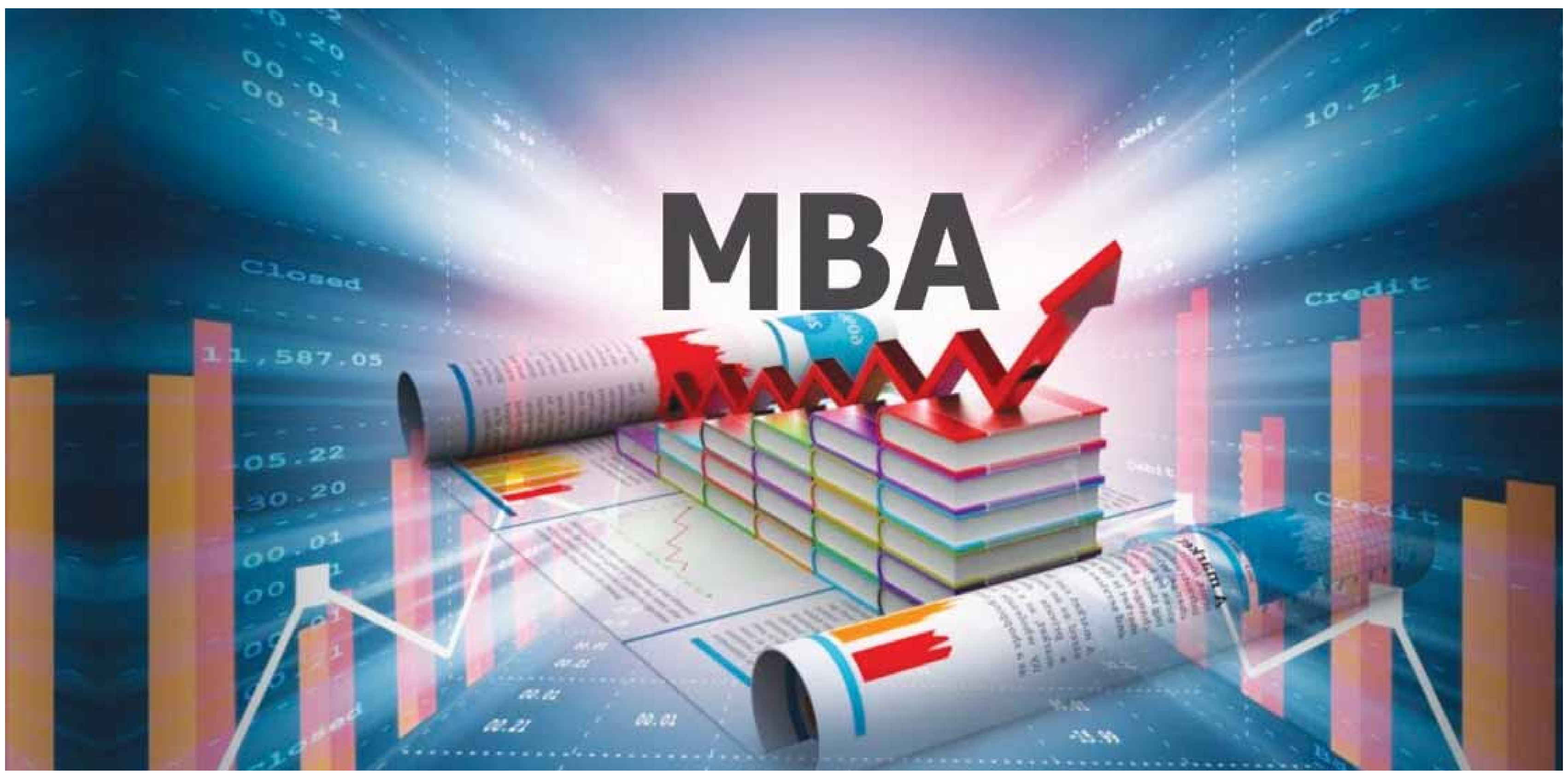

अर्जुन जगन्नाथन का कहना है कि उचित विशेषज्ञता चुनने के रुझान की कुछ साल पहले शुरुआत हुई थी। लेकिन अब उम्मीदवारों ने अपने पसंदीदा नौकरियां पाने हेतु विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता की महत्ता महसूस की है

भारत में, लगभग 3.6 लाख एमबीए उम्मीदवार हर साल निकलते हैं। लेकिन कोरोना वायरस स्थिति के कारण, बिजनेस स्कूलों (बी स्कूल) को पढ़ाने में अपने पारंपरिक तरीके में बदलाव करने पड़े हैं, और इन बदलावों के छात्रों पर गहरे प्रभाव पड़ेंगे।

ज्यादातर एमबीए पाठ्यक्रमों ने घोषणा की है कि वे अपने छात्रों को आनलाइन क्लासेज प्रदान करने के लिए डिजीटल होने की योजना बना रहे हैं। अनेक संस्थानों ने अपने एमबीए कोर्स शुरू होने की डेडलाइंस आगे बढ़ा दी हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि वे परिसरों को दुबारा तब खोलेंगे जब छात्रों के लिए कालेजों में कक्षाओं में भाग लेने के लिए आना सुरक्षित होगा। इसका अर्थ है कि एमबीए उम्मीदवारों को आनलाइन कक्षाओं में भाग लेना होगा और प्राय: क्लासरूप में भी ।

क्लासरूम छात्रों को अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे कि वे टापिक पर बहस कर सकें और तत्काल अपने संदेहों को स्पष्ट कर सकें। जब वे आनलाइन कक्षाएं करेंगे तो वे कैम्पस के अनुभव की कमी महसूस करेंगे और साथ ही साथ अन्य छात्रों व शिक्षक सदस्यों के साथ प्रत्यक्ष संवाद की भी।

लेकिन जहां तक प्रबंधन स्थिति की बात है तो वे काफी कुछ सीखेंगे और वे संस्थानों द्वारा प्रदत्त वेबिनारों व अन्य आनलाइन सत्रों में भाग लेने में भी सक्षम होंगे।

एमबीए कोर्स में जो बदलाव हो रहे हैं उसे देखते हुए ये कोर्स उम्मीदवार की अकादमिक क्षमता के अलावा अन्य योग्यताओं की भी परीक्षा करेंगे। वे अब संकट से निपटने में उम्मीदवार की योग्यता की भी जांच करेंगे।

यदि उम्मीदवार परिसर में एमबीए कोर्स में भाग लेता है, तो उन्हें टीमों में प्रोजेक्ट और केस स्टडीज में काम करना पड़ेगा। जब वे कालेज में टीमों के साथ होते हैं तो विमर्श करना, विचारों को साझा करना और प्रोजेक्ट पूरे करना अधिक आसान होता है। लेकिन वर्तमान स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती है।

इस स्थिति में, यह स्पष्ट हो जाता है कि नेतृत्वकारी भूमिका कौन लेता है, कौन टीम को एक साथ लाता है और कौन काम संभालता है। रोजगार बाजार पर कोरोना वायरस के असर ने एमबीए उम्मीदवारों को अपने एमबीए प्रोग्राम को चुनने से पहले पुनर्विचार करने के लिए बाध्य किया है। जब एक उम्मीदवार एमबीए करने का फैसला करता है, तो वह अपनी पसंद के क्षेत्र में विशेषज्ञता का चुनाव कर सकता है।

सही विशेषज्ञता चुनने के रुझान की शुरुआत कुछ साल पहले हुई थी। लेकिन अब उम्मीदवारों ने अपने पसंदीदा नौकरियां पाने हेतु विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकता की महत्ता महसूस की है।

प्रत्येक एमबीए प्रोग्राम में एक अनोखा प्रस्ताव रहेगा और हर बी स्कूल के पास अपने छात्रों को पढ़ाने का अपना तरीका होता है। यह उम्मीदवार पर निर्भर है कि वो भी स्कूलों द्वारा प्रदत्त जानकारियों का अध्ययन करे, अपना शोध करे और पता लगाए कि कौन सा कोर्स और कौन सा बी स्कूल उनके लिए सर्वाधिक अनुकूल है।

जनरल मैनेजमेंट में एमबीए, जो मैनेजमेंट और बिजनेस की व्यापक समझ प्रदान करता है, एक ऐसा एमबीए प्रोग्राम था जो मांग में था। लेकिन अब, एमबीए उम्मीदवार विशिष्ट एमबीए कोर्स चुनते हैं। वे अब अपने लिए उपलब्ध ऐसे विकल्पों की तलाश करना चाहते हैं जिसमें स्टेम (साइंस, तकनीक, इंजीनियरिंग एवं गणित) जैसे विषय भी सम्मिलित हैं।

जिस उम्मीदवार की टिकाऊ विकास की महत्ता व चुनौतियों की समझ में दिलचस्पी होती है उसके लिए बी स्कूल सस्टेनेबल डेवलेपमेंट में एमबीए का प्रस्ताव देते हैं। छात्र टिकाऊ विकास लाने वाली तकनीक और तरीके सीखते हैं, चाहे वे कार्पोरेट वातावरण के भीतर के हों या अन्य व्यवसायों में।

उम्मीदवार उदाहरण स्वरूप, लाजिस्टिक्स एवं सप्लाई चैन मैनेजमेंट, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट और इन्नोवेशन मैनेजमेंट में एमबीए करने का फैसला कर सकते हैं। दुनिया भर के बीस्कूल, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, आईआईएम, ईयू बिजनेस स्कूल तथा व्हार्टन बिजनेस स्कूल आदि, छात्रों के लिए अलग अलग एमबीए स्पेशलाइजेशन कोर्स के विकल्प प्रस्तावित करते हैं। इसके कारण, छात्रों के लिए अपने पसंदीदा कोर्स में दाखिला पाने के अवसर बढ़ गए हैं।

प्रत्येक एमबीए प्रोग्राम में एक अनोखा प्रस्ताव रहेगा और हर बी स्कूल के पास अपने छात्रों को पढ़ाने का अपना तरीका होता है। यह उम्मीदवार पर निर्भर है कि वो भी स्कूलों द्वारा प्रदत्त जानकारियों का अध्ययन करे, अपना शोध करे और पता लगाए कि कौन सा कोर्स और कौन सा बी स्कूल उनके लिए सर्वाधिक अनुकूल है।

यह फैसला करने के लिए, उम्मीदवार को पहले खुद को जानना होता है। उन्हें अपनी क्षमताओं व कमजोरियों को जानना होता है और अपने व्यक्तित्व व आकांक्षाओं के अनुकूल एमबीए प्रोग्राम चुनना होता है। लेकिन बीस्कूल द्वारा प्रस्तावित कोर्स की संभावना को समझना भी अनिवार्य होता है। कोर्स की संभावनाओं को समझने से उन्हें रोजगार भूमिकाओं तथा वेतन पैकेज को समझने में सहायता मिलेगी जो वे ग्रेजुएट होने के बाद प्राप्त करेंगे। एक बात उम्मीदवारों को याद रखनी चाहिए कि एमबीए एक निवेश है, पैसा और धन दोनों मामले में। इसलिए उचित फैसला करना और आज के संकट के समय के दौरान अपना सर्वोत्तम देना महत्वपूर्ण है।

– लेखक क्रेकवर्बल, के सह संस्थापक हैं।

युवाओं के लिए मददगार डिजीटल चैनल

लीजा हेडलॉफ का कहना है कि डिजीटल कंटेंट की इस दुनिया में जरूरी है कि महिलाओं को उन योग्यताओं से सशक्त बनाया जाए जिनकी उन्हें स्कूल से काम या अपनी पसंद के व्यवसाय में जाने के लिए आवश्यकता है

■ मैप आफमी (मॉम) है क्या ?

यह एक मोबाइल/ डिजीटल चैनल है जो युवाओं को वे योग्यताएं सीखने में सक्षम होने के लिए डिजाइन किया गया है जो उनके लिए उनकी मनचाही नौकरी पाने या ऐसे स्थायी व्यवसाय की शुरूआत करने के लिए आवश्यक है जिनसे शहर के लिए समस्याएं हल होती हैं।

यह शहर केन्द्रित है। दिल्ली, बैंगलुरू, कोलकाता। इसकी खूबियों वे योग्यताएं हैं जो शहर में आपको समस्या निवारक उद्यमी बनाने, के साथ साथ शहर में क्या है जो युवाओं के लिए रूचिकर है, के लिए आवश्यक हैं: स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट आर्ट, सिर्फ गलियों वाले खेल। मॉम का नयी आजीविकाओं, सेक्टरों व उद्यमों में युवा महिलाओं पर बहुत ज्यादा जोर रहा है और वह उससे जुड़े सवालों के उत्तर चाहती है। शहर में काम करने के जाने के संबंध में युवा महिलाएं क्या करना चाहती हैं? सुरक्षा? समान वेतन? काम के लचीले घंटे? साइकिल पथ से लेकर काम के लिए साइकिल? प्रदूषण मुक्त शहर?

मॉम को वैश्विक संचाद कंपनी बीटी का सहयोग प्राप्त है जो युवा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए डिजीटल कंटेंट की ताकत में विश्वास करती है जिनसे इन्हें ऐसी योग्यताएं प्राप्त होती हैं जो स्कूल से काम पर या अपना पसंदीदा व्यवसाय करने की ओर कदम बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं।

■ यह कैसे काम करती है?

यह आनलाइन काम करती है। 18-23 साल के युवा लोगों के लिए यह एक निशुल्क वीडियोयुक्त मंच है, हमें उम्मीद है कि युवा लोग इसे पसंद करेंगे, साइट देखना, रोजगार के लिए योग्यताएं सीखने हेतु सरकारी परिवहन द्वारा हर रोज काम पर जाने पर प्रत्येक सुबह देखा जाने वाला एप, नए व्यवसाय तलाशना, कालेज या नौकरी के लिए आने जाने के लिए हेल्मेट तथा साइकिल जैसा मजेदार साधन जीतने के लिए हमारी प्रश्न श्रंखलाओं का उत्तर देना।

कक्षा 11वीं और 12वी में युवाओं की हमारे दूसरे दर्शकों के लिए, नयी जीवन योजना बनाने के 26 चरण हैं जो स्कूल से काम तक आने जाने पर आधारित हैं।

Lisa Heydlauff
Director-founder, Going to School

■ लाभ क्या हैं ?

मॉम के फायदे ये हैं कि यह नि:शुल्क, मजेदार और प्रत्येक शहर की प्रत्येक भाषा में, पूर्वनिर्धारित कथ्य के साथ है। बीटी के वैश्विक टेलीकॉ सहयोग के साथ, लाखों लोगों तक पहुंचने के लिए मंच और कंटेंट बनाया गया है ताकि उन्हें वे नयी चीजें तलाशने के काम में सक्षम बनाया जा सके जिन्हें वे करना पसंद करते हैं। सरकारी स्कूलों के उन युवाओं तक भी पहुंच बनायी जा रही है जो वर्तमान आफलाइन हैं। बीटी वालंटियरों द्वारा स्कूल के युवा लोगों के लिए कंटेंट को मोबाइल फोन, टेबलेट्स, लैपटॉप पर लेना न केवल उन्हें नयी जीवन योजनाएं तथा आनलाइन बुलेट जर्नल्स बनाने के लिए होता है, बल्कि वे अपनी मनपंसद नौकरियों के साथ युवा लोगों से मिलते हैं और उनसे अनेक सवाल पूछ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा किस प्रकार किया था।

स्कॉलरशिप

द यूसी लॉरा जे क्लाड मेमोरियल, न्यूजीलैंड 2020 में इंटरनेशनल स्कालरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह स्कालरशिप मास्टर डिग्री और पीएचडी की थीसिस के लिए प्रदान की जाएगी।

लाभ : स्पांसरशिप में 2400 डॉलर की धनराशि प्रदान की जाएगी।

योग्यता : आवेदक ने अकादमिक वर्ष 2020-21 के लिए युनिवर्सिटी आफकेंटनबरी (यूसी) में इकालजी एवं इनवायरनमेंटल साइंस के क्षेत्र में एमएससी या पीएचडी की डिग्री के लिए आवेदन किया होना चाहिए। आवेदक को अपना सीवी, रूचि वक्तव्य, पासपोर्ट की प्रतिलिपि व मंतव्य कथन अपलोड करना होगा।

आवेदन की प्रवेश शर्तें : अगर आप यूसी में डिग्री के लिए पंजीकृत होने जा रहे हैं तो आपके पास कम से कम उच्च द्वितीय श्रेणी, अंडरग्रेजुएट आनर्स डिग्री या समकक्ष अंतर्राष्ट्रीय योग्यता डिग्री होना अनिवार्य है।

भाषा शर्तें : आवेदकों को मान्यता प्राप्त अंग्रेजी भाषा में न्यूनतम दक्षता मानक हासिल होना चाहिए।

आवेदन कैसे करें : अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको युनिवर्सिटी आफ केंटर्नबरी में पीएचडी और एमएससी डिग्री कोर्स की पढ़ाई में आवेदन के जरिए युनिवर्सिटी का छात्र बनना पड़ेगा। पूर्णकालिक पंजीकरण कराने के बाद, उम्मीदवार स्कालरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की अंतिम तिथि : 1 नवंबर, 2020।

द एसजीएस डीन वित्त सहायता का प्रस्तावित करता है और इंटरनेशनल छात्रों से युनिवर्सिटी आफ लेथब्रिज में अपनी मास्टर या पीएचडी की पढ़ाई के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।

लाभ : सफल प्रतिभागियों को 10000 डॉलर की धनराशि प्रदान होगी।

योग्यता : आवेदक पूर्णकालिक आवेदक होना चाहिए और उसे समझदारी, शोध कुशलता, सामग्री या/और प्रदर्शन संबंधी कार्यक्रम या गतिविधियों के बारे में बताना होगा। आवेदकों को अनौपचारिक दस्तावेज, मंतव्य पत्र, केरीकुलम बायोडाटा और भाषा योग्यता प्रमाणपत्र अपलोड करने होंगे।

प्रवेश शर्तें : प्रतिभागियों के पास ग्रेजुएट डिग्री कोर्स में आवेदन करने के लिए अंडरग्रेजुएट डिग्री होना अनिवार्य है।

भाषा शर्तें : विदेशी छात्रों को चाहिए कि वे अपनी अंग्रेजी भाषा दक्षता प्रदर्शित करने के लिए टीओईएफएल या आईईएलटीएस टेस्ट में भाग लें।

आवेदन कैसे करें : स्कालरशिप के लिए कोई अतिरिक्त आवेदन नहीं है। सभी योग्य आवेदकों को युनिवर्सिटी में मास्टर या पीएचडी डिग्री कोर्स में पंजीकरण के बाद ग्रांट के लिए योग्य मान लिया जाएगा।

आवेदन की अंतिम तिथि : युनिवर्सिटी तीन टर्म में आवेदन स्वीकार करती है :

समर टर्म के लिए मई-अगस्त, फॉल टर्म के लिए सितंबर-दिसंबर तथा स्प्रिंग टर्म के लिए जनवरी-अप्रैल कोर्स और टर्म के मुताबिक अंतिम तिथियों की जांच कर लें।

बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाह रहे 78 प्रतिशत माता-पिता

एसपी रोबोटिक्स वर्क्स द्वारा किए गए सर्वे और शोध अध्ययन , किड्स अंडर कोविड, के अनुसार, 78 फीसदी माता पिता तालाबंदी उपरांत तत्काल अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाह रहे हैं, भले ही बच्चे को दुबारा उसी कक्षा में पढ़ाना पड़ जाए।

माता पिता के लिए अपने बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: बैंगलुरू, मुंबई, हैदराबाद और लघु महानगरो के अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर शंकालु हैं, भले ही यह सुरक्षित घोषित हो, मगर 82 से 86 फीसदी अभिभावक बच्चों को लेकर कोई जोखिम मोल लेना नहीं चाहते। हालांकि, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहर उन प्रमुख शहरों में अकेले अपवाद हैं जहां उन अभिभावकों का अनुपात, जो अपने बच्चों को स्कूल भेजने का अवसर हाथ में लेना चाहते हैं, राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। इन समूहों में, वेतनशुदा अभिभावक सर्वाधिक सुरक्षात्मक हैं, जिनमें से केवल 17 फीसदी ही स्कूलों के दुबारा खुलने पर अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं जब 30 प्रतिशत व्यापारी और केवल 56 फीसदी फ्रीलांस कर्मचारी समूह अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है।

माता-पिता और छात्र आनलाइन की मौजूदा पढ़ाई को नकारते हैं: हालांकि अधिकांश स्कूलों ने सफलतापूर्वक आनलाईन पढ़ाई को अपना लिया है, मगर इस प्रारूप को क्लासरूम में पढ़ना पसंद करने वाले दो तिहाई बच्चों के साथ कम असरकारी पाया जाता है। दिलचस्प बात यह कि छोटे शहरों व गैर मेट्रो शहरों के, बच्चे, साथ ही साथ माता पिता भी, बैंगलुरू को छोड़कर, मेट्रो में पढ़ने वाले बच्चों की तुलना में आनलाइन पढ़ना पसंद करते दिखते हैं।

महिला उद्यमियों का दौर के संकेत: मनचाही नौकरियों के विकल्पों के बीच, 15 प्रतिशत लड़कियां, जो लड़कों की तुलना में अधिक है, बालिग होकर उद्यमी बनना चाहती हैं। डाक्टर बनने के सपने के इतर दूसरा सपना उद्यमिता है। मेकिंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए 2015 अध्ययन के अनुसार, भारत की जीडीपी 2025 तक 16-60 प्रतिशत तक बढ़ सकती थी यदि महिलाओं ने अर्थव्यवस्था में पुरूषों के साथ योगदान किया होता। पूर्वानुमान दिखाते हैं कि यह अर्थव्यवस्था में 2.9 खरब डॉलर की वृद्धि हो सकता था। यदि हम स्कूल जाने वाली लड़कियों के इस सपने को पोषित कर सकें, तो भारत में निश्चित रूप से 2025 तक 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है।

7 से 10 साल के बीच की उम्र के बच्चे उद्यमिता प्रोत्साहन से पोषित हुए दिखते हैं और यह संख्या 16-17 आयुसमूह में 17 फीसदी चली जाती है। उपलब्ध डाटा से, मिनी मेट्रो और गैर मेट्रो शहरों में मेट्रो की तुलना में ज्यादा उद्यमी पैदा करने की संभावना है। अन्य मनचाही नौकरियों में, स्टेम निरंतर युवा भारत की महत्वाकांक्षाओं पर हावी है जिसमें 52 फीसदी बच्चे या तो वैज्ञानिक या तकनीकविद, डाटा साइंटिस्ट या डाक्टर बनना चाहते हैं। हालांकि, वैज्ञानिक बनने की इच्छा समाप्त हो जाती है जैसे बच्चा बड़ा होता है, वर्तमान में स्टैम के सख्त तथा सैद्धांतिक नजरिए के कारण।

कोडिंग व रोबोटिक्स के लिए मार्ग प्रशस्त करते खिलौने: लाभकारी भविष्य के लिए स्टेम विषयों की बढ़ती संभावना को महसूस करके, 23 फीसदी अभिभावकों ने तालाबंदी अवधि के दौरान अपने बच्चों को आनलाइन रोबोटिकस कक्षा में शामिल कराया है, जबकि 32 फीसदी ने आनलाइन कोडिंग कक्षाओं में अपने बच्चों की भागीदारी कराई है। चौंकाने वाली बात यह कि रोबोटिकस/कोडिंग क्लासेज में 42 फीसदी बच्चों की भागीदारी के साथ मुंबई इस तालिका में सर्वोपरि है जबकि तकनीक का केन्द्र बैंगलुरू और कोलकाता में बच्चे वाद्य यंत्र का अभ्यास करने या पढ़ने जैसे पारंपरिक शौक में समय बिताना पसंद करते हैं।

माइंड इट

छोटे मेट्रो शहरों में बच्चों के लिए यूट्यूब नयी चीजें सीखने का एक पसंदीदा मंच बनता है लेकिन 26 प्रतिशत बच्चे वीडियो व एप्प गेम पर भी समय बिताते हैं। क्या हम अपने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अंजान हो रहे हैं? लगभग पचास प्रतिशत बच्चों की सोने की आदत बिगड़ गयी है जिनमें 13 फीसदी बच्चों की सोने की कोई नियमित दिनचर्या नहीं है। हालांकि भाई बहनों वाले बच्चों ने अपने आपको कम प्रभावित होने से बचा लिया है, फिर भी, बड़े बच्चे की नींद की दिनचर्या में खामियां दिखाई दी हैं। किशोर आयु के बच्चों की भी नींद दिनचर्या प्रभावित है।

समझने योग्य बात है कि 67 प्रतिशत माता पिता सोचते हैं कि उनके बच्चे का स्क्रीन टाइम तालाबंदी के दौरान कम से कम पचास प्रतिशत तक बढ़ गया है जिससे उनका एकाग्रता स्तर प्रभावित हुआ है और नींद की समस्या पैदा हुई है। महामारी के भय ने सर्वे किए गए चालीस फीसदी को प्रभावित किया है, कारण यह कि उनकी बेचैनी की समस्याओं पर उचित ध्यान नहीं दिया जा सका।